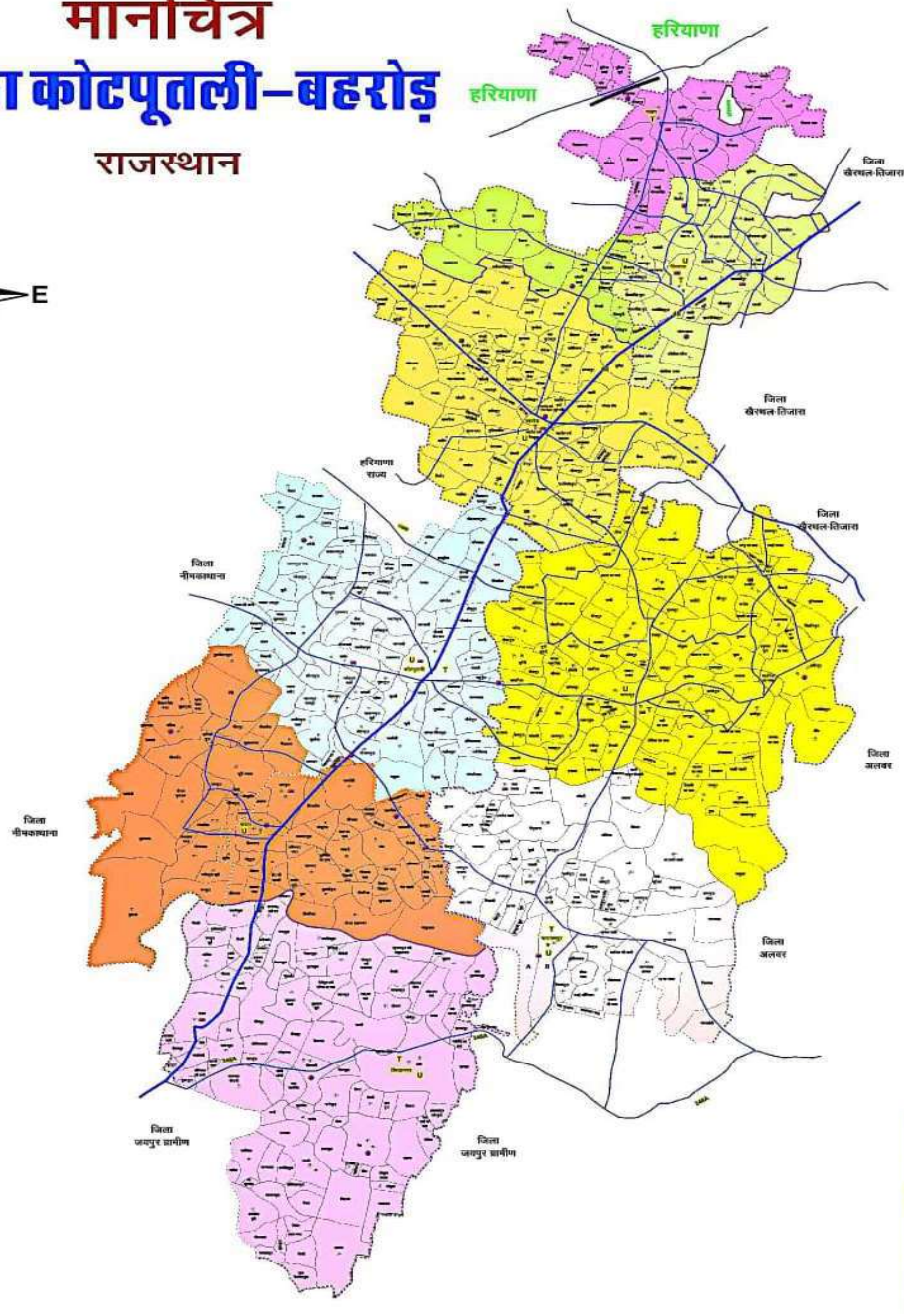


राजस्थान सरकार
कोटपूतली-बहरोड
जिला आपदा प्रबन्धन योजना
2025



संरक्षक

श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, आई.ए.एस

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अध्यक्ष

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कोटपूतली—बहरोड

संपादक

श्री ओम प्रकाश सहारन, आर.ए.एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी (सहायता)

सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कोटपूतली—बहरोड



कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड जिला आपदा प्रबन्धन योजना- 2024

प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व एवं आपदा के समय सही कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना-2025 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के दिशा-निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं आमजनों के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

यह योजना आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने का मकसद जिला स्तर पर आपदा से होने वाले जान-माल की क्षति को न होने देना या कम करना साथ ही मानव जनित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबन्धन में समीचीन योजना, संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्राबंधन सहित क्षमता निर्माण, ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावों का आंकलन, फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना है।

योजना को समझने के लिए सभी की भागीदारी, सहयोग, जानकारी और तैयारी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन योजना-2025, की सफलता तभी संभव है, जब हम सभी इसका अध्ययन करें और इसे आपदा के पूर्व की तैयारी एवं आपदा के समय बचाव कार्य में उपयोग में लायें।

इस योजना को व्यवस्थित तरीके से तैयार एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने योजना को बनाने में जनहित में अपनी सहभागिता निभाई। योजना को सफल बनाने में सब का सहयोग, बहुमूल्य सुझाव स्वागत योग्य है।

श्रीमती प्रियंका गोस्वामी आई.

ए.एस.

मजिस्ट्रेट

प्राधिकरण

जिला कलक्टर एवं जिला

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण परिचय	7
अध्याय 2	विकास और आपदा	17
2.1	बहु-आपदा अनुक्रिया योजना	17
2.2	जिला आपदा प्रबन्धन	18
2.3	कार्य योजना के उद्देश्य	19
2.4	नीतिगत कथन	19
अध्याय 3	कोटपूतली-बहरोड जिले की रूपरेखा	20
3.1	राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जिला कोटपूतली-बहरोड एक दृष्टि में (वर्ष 2011-12)	22
3.2	पर्यटन स्थल	30
3.3	परिवहन, संचार और उर्जा	35
अध्याय 4	आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति	36
4.1	आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य योजना	36
4.2	खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)	38
4.3	रोकथाम और शमन उपाय	39
अध्याय 5	राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा	41
5.1	आपदा प्रबन्धन चक्र	42
5.2	सूखा	42

5.3	बाढ़	43
5.4	भूकम्प एवं तीव्रता	45
5.5	जिले का खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण	49
5.6	आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग	50
अध्याय 6	कोटपूतली-बहरोड जिला की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	51
6.1	संभावित विपदाओं की पहचान	51
6.2	संवेदनशीलता	52
अध्याय 7	प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना	54
7.1	जिला आपदा प्रबन्धन	54
7.2	संस्थागत व्यवस्था	55
7.3	कार्य योजना के उद्देश्य	60
7.4	नियन्त्रण कक्ष	61
7.5	जिला एवं स्थानीय प्रशासन	61
7.6	पुलिस विभाग	63
7.7	अग्नि कार्य योजना	64
7.8	आकाशीय बिजली बचाव कार्य योजना	75
7.9	नागरिक सुरक्षा बल	79
7.10	राज्य आपदा प्रतिसाद बल : जंजम कपेंजमत त्मेचवदेम श्वतबमएँक्त्स्द्ध बम विस्फोट एवं आतंकवादी घटना	79
7.11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना	82
7.12	जल संसाधन विभाग कार्य योजना	87
7.13	बोरवेल की दुर्घटना	113
7.14	सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	116
7.15	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना	118
7.16	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना	119

7.17	परिवहन विभाग	120
7.18	खाद्य एवं रसद विभाग	120
7.19	सूखे की कार्ययोजना	120
7.20	दुर्घटना कार्य योजना	123
7.21	भूकम्प एवं कार्य योजना	126
7.22	ओला वृष्टि	129
7.23	बांध टूटना	129
7.24	खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्य योजना	130
7.25	ताप (लू) एवं शीतघात	130
अध्याय 8	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	135
अध्याय 9	पुर्ननिर्माण, पुर्नवास एवं रिकवरी उपाय	138
अध्याय 10	रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्य योजना	142
10.1	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	142
अध्याय 11	बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्य योजना	144
अध्याय 12	न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति की कार्ययोजना	145
अध्याय 13	साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़	146
अध्याय 14	विधालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय	149
अध्याय 15	कोटपूतली-बहरोड बस स्टैण्ड आपातकालीन कार्ययोजना	150
अध्याय 16	आपात प्रतिक्रिया योजना (ईमरजेन्सी रिस्पोन्स प्लान)	151
अध्याय 17	आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी	155
अध्याय 18	राजस्थान राहत कोष	156
अध्याय 19	तहसील कोटपूतली आपदा योजना	162
अध्याय 20	तहसील बहरोड आपदा योजना	164
अध्याय 21	तहसील नीमराना आपदा योजना	166
अध्याय 22	तहसील नारायणपुर आपदा योजना	168

अध्याय 23	तहसील बानसूर आपदा योजना	172
अध्याय 24	तहसील पावटा आपदा योजना	178
अध्याय 25	तहसील विराटनगर आपदा योजना	184
अध्याय 26	तहसील माढ़ण आपदा योजना	194
अध्याय 27	जिले के प्रशासनिक अधिकारी ,पुलिस अधिकारी ,जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण विभाग की सूची एवं दूरभाष नम्बर	196
अध्याय 28	आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली	201
अध्याय 29	कमियाँ एवं ठोस कार्यवाही	206

अध्याय : 1

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) – राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएँ और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ड) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभाग द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1) — राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य —

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाएँ अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 — जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

(क) जिले का कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक — सदस्य।

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी — सदस्य।

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

- (4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां।

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्य जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन।

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 30 – जिला प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य।

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा

अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रायोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :—

- (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा,
- (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटरिंग कर सकेगा,
- (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं :
- (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
- (v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
- (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।
- (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा :
- (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।
- (ix) खंड ,अपपपद्ध में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्वयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुसरण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकृत कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xix) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकृत कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

(xx) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा

और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31 – जिला आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी।

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं।

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएँ और प्रक्रियाएँ, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

(i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन :

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

(iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण।

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

(v) जनता को सूचना का प्रसार।

(ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

स्थानीय प्राधिकारी

धारा 41 – स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 – राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ)

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 45 – नियंत्रण, निर्देशन

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

धारा 46 – राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि।

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रदान करें।

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदशक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

अपराध और शक्तियां ; चमदंसजपमे दक च्त्वेमबनजपवदद्ध

धारा 51 – बाधा डालने आदि के लिए दंड।

जे कोई युक्तियुक्त कारण के बिना —

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा : या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 – मिथ्या दावे के लिए दंड।

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या

विश्वास करने को उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड।

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 55 – सरकार के विभागों द्वारा अपराध।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहा विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56 – अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता।

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त

लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 57 – अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।

यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

अध्याय : 2

विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है, परन्तु आज भी आपदाएँ उसके नियंत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मानवीयकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। 1990 में उड़ीसा में आये तूफान 'नचमत ब्लबसवदमद्धए' 26 जनवरी, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 26 दिसम्बर, 2004 में दक्षिणी राज्यों में आयी सुनामी, 29 अक्टूबर, 2009 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल डिपो में हुये भारत के सबसे भीषण अग्निकांड तथा 16 जून, 2013 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ/गौरीकुण्ड/गुप्त काशी में हुई भीषण प्राकृतिक तबाही इत्यादि इसके ताजा उदाहरण हैं।

2.1 बहु- आपदा अनुक्रिया योजना :

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, आंगजनी, सडक दुर्घटनाएँ, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। (1950-2000) के 50 वर्षों में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965-69, 1979-82, 1984-87, 1991-92, 1999-2000 में रहा है। 1980 से 2000 के दो दशकों में मात्र 1983-84, 1992-93, 1995-96 व 1997-98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की

निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी कभी पड़ता था वह स्थाई आपदा बन गया है।

संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियंत्रित जल विदोहन गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएँ हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन, एवं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

2.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य :-

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहायेग के साथ क्षमता बढ़ाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
5. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

7. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

2.3 कार्य योजना के उद्देश्य :-

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक धन दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति- आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया : त्मंबजपवदध्मेचवदेमद्ध कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
5. स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

2.4 नीतिगत कथन :-

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.2. 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लुण्णकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का

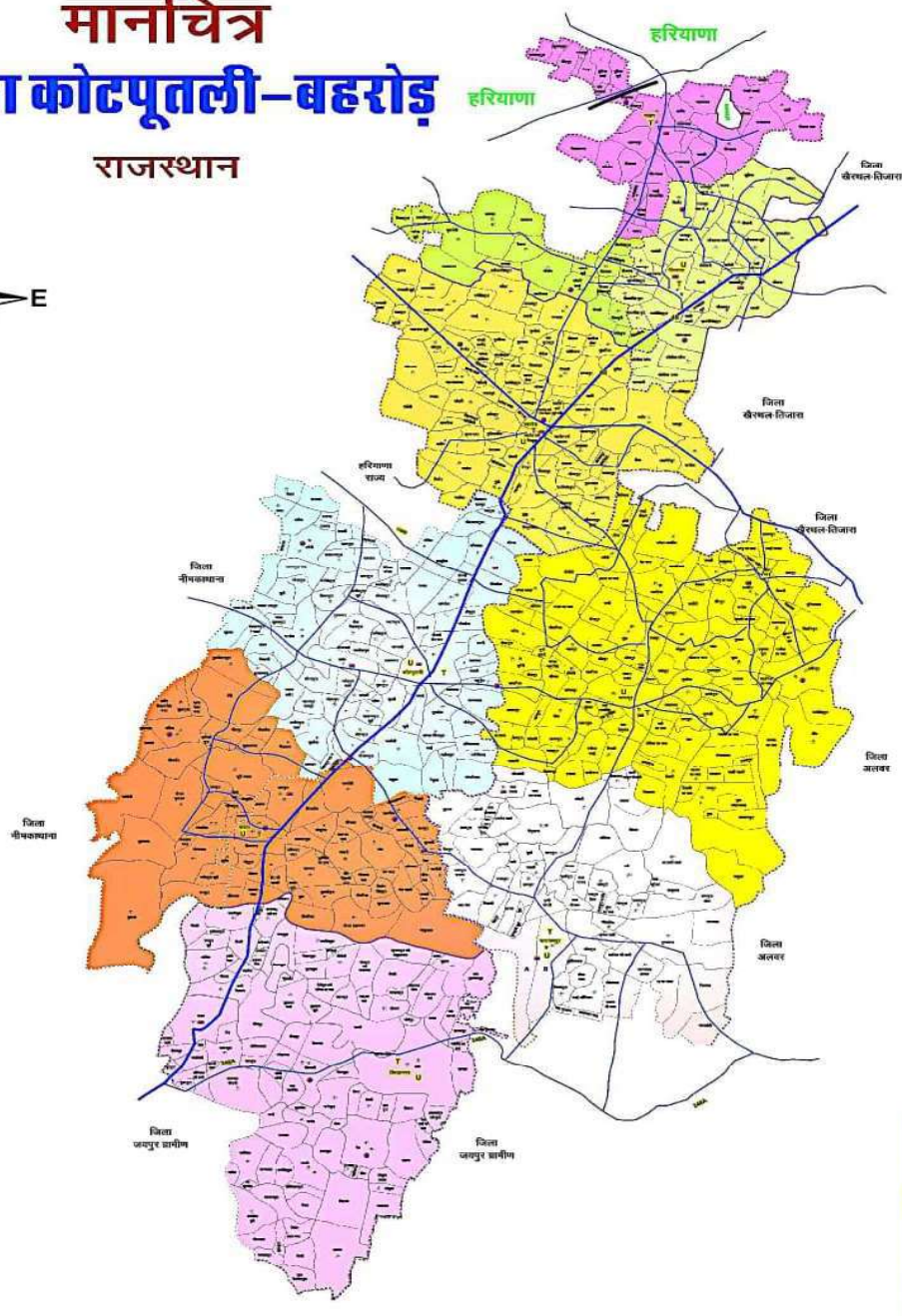
सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय : 03

कोटपूतली-बहरोड़ जिले की रूपरेखा एवं संरचना

राज्य सरकार द्वारा 07 अगस्त 2023 को कोटपूतली-बहरोड़ को नवीन जिला बनाया गया कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अलवर जिले और तत्कालीन जयपुर जिले की 8 तहसीलों कोटपूतली, बहरोड़ नीमराणा, बानसूर, माँढन, पावटा, नारायणपुर, विराटनगर को शामिल किया गया है कोटपूतली-बहरोड़ जिला अलवर, खैरथल-तिजारा व नीमकाथाना से सीमा बनाता है व हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कोटपूतली-बहरोड़ जिला 27.8867 डिग्री उत्तर और 76.2834 डिग्री पूर्व में स्थित है।

यह जिला भारत देश की राजधानी व राजस्थान राज्य की राजधानी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्थित है। जिले में साबी नदी बहती है। जिले के भैंसलाना का काला संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कम्पनी का कारखाना स्थापित है, जिले के बहरोड़ तहसील में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जिले के नीमराणा में स्थित बावड़ी को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया गया है, बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य जिले में स्थित है, जिले की तहसील विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास पुरा किया था, बकरी की सबसे सुन्दर नस्ल ग्राम जखराना में पाई जाती है। जिले में 07 उपखण्ड – कोटपूतली, बहरोड़, नीमराणा, नारायणपुर, बानसूर, पावटा, विराटनगर। जिले में 08 तहसील– कोटपूतली, बहरोड़, नीमराणा, नारायणपुर, बानसूर, पावटा, विराटनगर, माढ़ण । 6 पंचायत समिति– कोटपूतली, नीमराणा, बहरोड़, बानसूर, पावटा, विराटनगर । 06 नगरपालिका– पावटा, विराटनगर, नारायणपुर, बानसूर, बर्डोद, नीमराना। एवं 02 नगर परिषद कोटपूतली, बहरोड़ स्थित हैं।



3.1 जिला कोटपूतली-बहरोड एक दृष्टि में (वर्ष 2024-25)

1. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या स्थिति

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	क्षेत्रफल	हैक्टेयर	2023-24	288103
2	कुल जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	1296747
	पुरुष	संख्या	जनगणना 2011	682406
	महिला	संख्या	जनगणना 2011	614341
3	अनुसूचित जाति जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	185403
4	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	संख्या	जनगणना 2011	65253
5	लिंगानुपात	संख्या	जनगणना 2011	900
6	जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग किमी	जनगणना 2011	450
7	साक्षरता	प्रतिशत	जनगणना 2011	69.05

2. प्रशासनिक ईकाई

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	उपखण्ड	संख्या	2023—24	7
2	तहसील	संख्या	2023—24	8
3	उपतहसील	संख्या	2023—24	2
4	पंचायत समिति	संख्या	2023—24	6
5	कुल ग्राम पंचायत	संख्या	2023—24	193
6	कुल राजस्व ग्राम	संख्या	2023—24	657
7	कुल नगर निकाय	संख्या	2023—24	8
8	पटवार मण्डल	संख्या	2023—24	191
9	गिरदावर सर्किल	संख्या	2023—24	48

3. जनप्रतिनिधि

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	लोक सभा सदस्य	संख्या	2023—24	2
2	विधानसभा सदस्य	संख्या	2023—24	4
3	जिला परिषद सदस्य	संख्या	2023—24	19
4	पंचायत समिति सदस्य	संख्या	2023—24	136
5	सरपंच	संख्या	2023—24	192

6	वार्ड पंच	संख्या	2023—24	1983
7	नगर परिषद पार्षद	संख्या	2023—24	75
8	नगर पालिका के पार्षद	संख्या	2023—24	147

4. पशुपालन

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	बहु उद्येश्शीय पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	1
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	9
3	पशु चिकित्सालय	संख्या	2023—24	44
4	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	संख्या	2023—24	167
5	ब्लॉक स्तरीय पशु रोग निदान केन्द्र	संख्या	2023—24	7
6	मोबाईल यूनिट(1962)	संख्या	2023—24	7
20 वी पशुगणना				
क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	गाय	संख्या	20वीपशुगणना	79428
2	भैंस	संख्या	20वीपशुगणना	452395

3	बकरी	संख्या	20वीपशुगणना	161667
4	भेड़	संख्या	20वीपशुगणना	29345
5	गधा व घोड़ा	संख्या	20वीपशुगणना	301
6	उंट	संख्या	20वीपशुगणना	1251
7	सुअर	संख्या	20वीपशुगणना	2426
	योग	संख्या	20वीपशुगणना	726813

5. शिक्षा

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	कुल विद्यालय			
	प्राथमिक/उ० प्राथमिक/माध्यमिक/उ० माध्यमिक	संख्या	2023—24	936
	1. प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	288
	2. उ० प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	291
	3. माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	1
	अ. छात्र विद्यालय	संख्या	2023—24	1
	ब. छात्रा विद्यालय	संख्या	2023—24	0
	4. उ०माध्यमिक विद्यालय	संख्या	2023—24	356
	अ. छात्र विद्यालय	संख्या	2023—24	327
	ब. छात्रा विद्यालय	संख्या	2023—24	29
2	कुल विद्यार्थी			

	प्राथमिक/उ० प्राथमिक/माध्यमिक/उ० माध्यमिक	संख्या	2023-24	87441
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023-24	36615
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023-24	50826
	1. प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023-24	4978
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023-24	2231
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023-24	2747
	2. उ०प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023-24	15950
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023-24	6778
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023-24	9172
	3. माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023-24	54
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023-24	24
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023-24	30
	4.उ०माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी	संख्या	2023-24	66459
	अ. कुल छात्र	संख्या	2023-24	27482
	ब. कुल छात्रा	संख्या	2023-24	38877

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	राजकीय एलौपेथिक चिकित्सालय			
	अ. शहरी क्षेत्र			
	1. जिला मुख्यालय पर	संख्या	2023-24	3
	2. शेष नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में	संख्या	2023-24	6

	ब. ग्रामीण क्षेत्र			
	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023-24	15
	2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023-24	60
	3. कुल उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023-24	296
2	राजकीय एलौपेथिक चिकित्सालय में बैड			
	अ. शहरी क्षेत्र	संख्या	2023-24	468
	ब. ग्रामीण क्षेत्र			
	1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023-24	580
	2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	2023-24	360
3	अन्य			
	1. जिला क्षय रोग चिकित्सालय	संख्या	2023-24	0
	2. मेडिकल मोबाईल यूनिट व मेडिकल मोबाईल वैन	संख्या	2023-24	2
	3. ट्रौमा सेन्टर	संख्या	2023-24	1
	4. ब्लड स्टोरेज केन्द्र	संख्या	2023-24	1
	5. प्रथम रैफरल केन्द्र	संख्या	2023-24	18
	6. 104 जननी एक्सप्रेस	संख्या	2023-24	13
	7. 108 एम्बुलेंस सेवा	संख्या	2023-24	17
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय			
	1 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	2023-24	0
	2. आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	2023-24	0
	3. ब्लॉक आयुष चिकित्सालय	संख्या	2023-24	3

	4. आयुर्वेद औषधालय	संख्या	2023-24	89
	5. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय	संख्या	2023-24	0
	6. एकल चिकित्सक सीएचसी व पीएचसी पर कार्यरत	संख्या	2023-24	7

7. सहकारिता

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	सहकारी संस्थाओं की संख्या	संख्या	2023-24	170
2	दुग्ध सहकारी समिति	संख्या	2023-24	422
3	दुग्ध संकलन केन्द्र	संख्या	2023-24	280
4	दुग्ध सहकारी समितियों में सदस्य संख्या	संख्या	2023-24	9280

8. महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	संख्या	2023-24	1206
2	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र	संख्या	2023-24	1206
3	पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्र	संख्या	2023-24	1206
4	पूरक पोषाहार की उपलब्धि (लाभान्वित)	संख्या	2023-24	61000 प्रतिमाह
5	शाला पूर्व शिक्षा की उपलब्धि	संख्या	2023-24	21000

9. पंचायतीराज विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
----------	----	------	--------------	-------

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना				
1	योजनान्तर्गत परिवारो को उपलब्ध रोजगार	संख्या	2023-24	26286
2	योजनान्तर्गत मानव दिवस सर्जित	लाखों में	2023-24	13.31
3	योजनान्तर्गत औसत मजदूरी	रूपयों में	2023-24	211.33

10.यातायात एवं सड़के

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	निजी कार / जीप	संख्या	2023-24	1676
2	बस / मिनी बस	संख्या	2023-24	57
3	स्कूटर / मोपेड / मोटर साईकिल	संख्या	2023-24	6939
4	आटो रिक्शा	संख्या	2023-24	75
5	टैक्सी	संख्या	2023-24	120
6	ई-रिक्शा	संख्या	2023-24	153
7	ई-कार्ट	संख्या	2023-24	197
8	सार्वजनिक / निजी भारी वाहन	संख्या	2023-24	4226
9	ट्रैक्टर	संख्या	2023-24	1073
10	अन्य	संख्या	2023-24	142
कुल पंजीकृत वाहन		संख्या	2023-24	14658
सड़क				
1	सड़को की लम्बाई	कि०मी०	2023-24	2476.04
2	राष्ट्रीय राजमार्ग	कि०मी०	2023-24	117.4

3	राज्य राजमार्ग	कि०मी०	2023-24	182.7
4	मुख्य जिला सड़के	कि०मी०	2023-24	419.13
5	अन्य जिला सड़के	कि०मी०	2023-24	11
6	ग्रामीण सड़के	कि०मी०	2023-24	1745.81

11. बैंकिंग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	व्यवसायिक बैंक	संख्या	2023-24	78
2	ग्रामीण बैंक	संख्या	2023-24	26
3	भूमि विकास बैंक	संख्या	2023-24	1
4	सहकारी बैंक	संख्या	2023-24	6
5	निजी बैंक	संख्या	2023-24	54

12. सिंचाई

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	तालाब एवं बांध	संख्या	2023-24	2
2	नलकूप	संख्या	2023-24	28403
3	सिंचाई के लिये कुएँ	संख्या	2023-24	77530
4	कुओं की संख्या	संख्या	2023-24	39105

5	पड़त कुओ की संख्या	संख्या	2023-24	17523
6	काम में आने वाले कुओं की संख्या	संख्या	2023-24	21512

13.पुलिस विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	पुलिस थाना	संख्या	2023-24	15
2	महिला पुलिस थाना	संख्या	2023-24	1
3	पुलिस चौकी	संख्या	2023-24	16
4	कारागृह (बन्दी गृह+कारागृह)	संख्या	2023-24	2

14.पेयजल

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	शुद्ध पेयजल से जुड़े गांव	संख्या	2023-24	657
2	पेयजल हेतु हैडपम्प (ग्रामीण+शहरी)	संख्या	2023-24	75807
3	जल जीवन मिशन के तहत किये गए कुल कनेक्शन	संख्या	2023-24	178910

15.सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
छात्रावास				

1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023-24	5
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023-24	2
3	अन्य	संख्या	2023-24	3
समाजिक सुरक्षा पेंशन				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023-24	21529
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023-24	6003
3	अन्य	संख्या	2023-24	145208
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023-24	7
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023-24	2
3	अन्य	संख्या	2023-24	10
पालनहार योजना (लाभान्वित)				
1	अनुसूचित जाति	संख्या	2023-24	3321
2	अनुसूचित जनजाति	संख्या	2023-24	1107
3	अन्य	संख्या	2023-24	6642

16. ऊर्जा

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	विद्युतीकृत नगर (सिटी टाउन सहित)	संख्या	2023-24	8

2	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	2023-24	657
3	कुल ऊर्जा की खपत	यूनिट लाखों में	2023-24	22262.08
क	घरेलू उपभोग	यूनिट लाखों में	2023-24	2343
ख	व्यवसायिक व अस्थाई उपभोग	यूनिट लाखों में	2023-24	847.28
ग	औद्योगिक उपभोग	यूनिट लाखों में	2023-24	10243
घ	सार्वजनिक प्रकाश	यूनिट लाखों में	2023-24	50.51
ड	सिंचाई/कृषि	यूनिट लाखों में	2023-24	8511
च	जल प्रदाय	यूनिट लाखों में	2023-24	234.94
छ	अन्य उपभोग	यूनिट लाखों में	2023-24	32.35
4	सबग्रिड स्टेशन			
क	400 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023-24	2
ख	220 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023-24	4
ग	132 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023-24	10
घ	33 केवी. जी.एस.एस.	संख्या	2023-24	124
5	विद्युतीकृत कूप कृषि कनेक्शन (31.03.2024 तक)	संख्या	2023-24	43140

17. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	ई-मित्र केन्द्र	संख्या	2023-24	1267
अ	शहरी	संख्या	2023-24	305
ब	ग्रामीण	संख्या	2023-24	962
2	ई-मित्र कियोस्क	संख्या	2023-24	242

18. जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन

क्र. सं.	मद	ईकाई	सन्दर्भ अवधि	विवरण
1	जन्म पंजीयन	संख्या	2023—24	37198
2	मृत्यु पंजीयन	संख्या	2023—24	6892
3	विवाह पंजीयन	संख्या	2023—24	8126

3.2 पर्यटन स्थल

- **टीलाजी महाराज मेला-** पावटा तहसील से 3 किलोमीटर दूर खेलना गांव (तपस्थली) में धुलंडी के दिन आयोजित होने वाला संत टीलाजी महाराज का मेला अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है। जहां वृक्ष को टीलाजी महाराज का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है।
 - इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां कोई एक-दूसरे को रंग या गुलाल नहीं लगाता।
 - मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र डोरी बांधते हैं। मान्यता है कि इच्छा पूरी होने पर वे डोरी खोलकर मंदिर में चढ़ा देते हैं।
 - खेलना गांव न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। इस गांव में पेड़ काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
 - संत टीला जी महाराज का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, भक्ति, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण का एक अद्भुत संगम है।
 - ट्सकोल सरपंच प्रतिनिधि भैरू हुड्डा के अनुसार, टीला जी महेंद्रगढ़ के निवासी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य अपनाया और ग्राम खेलना में तपस्या करने लगे।
 - स्थानीय जोहड़ में स्नान कर परिक्रमा करने की परंपरा के कारण इस स्थान का नाम चक्कर तीर्थ पड़ा, जो अब चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।
- **टोरड़ा बगीची धाम-** तहसील पावटा से 5 किमी दूर टोरड़ा ग्राम में स्थित यह धाम लगभग 01 हजार वर्ष प्राचीन है, यहां पर जानकी रघुनाथजी, हनुमानजी व शंकर भगवान के प्राचीनतम मंदिर है।

- यह पवित्र स्थल माधवदास जी, भरतदासजी, गोपालदास जी जैसे महान संतो की तपोस्थली रही है।
- वर्तमान में मंगलदास जी महाराज के द्वारा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रम किये जा रहे हैं।
- **छापाला वाले भैरूजी मेला-** कोटपूतली में हर साल अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित कुहाड़ा गांव में स्थित छापाला वाले भैरू बाबा मंदिर में 30 जनवरी को एक विशाल लकड़ी मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं और भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण करते हैं।
 - महाप्रसाद: 551 क्विंटल चूरमा, जो JCB और श्रेसर से बनाया जाता है।
 - भंडारा: लाखों भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है।
 - कलश यात्रा: मेले से पहले 11,000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है।
 - पंचदेव खेजड़ी वृक्ष की पूजा: मेले में पंचदेव खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है।
 - मेले की पूरी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाती है।
- **भगवान जगन्नाथ का मेला -** कोटपूतली क्षेत्र के गांव पुरुषोत्तमपुरा का जगन्नाथ धाम भगवान मंदिर अटूट आस्था का केंद्र है। 4 जनवरी को यहां लगने वाले विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं।
 - मेले की खास बात है कि मेले वाले दिन उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाला भोग यहां लगता है।
 - भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेले वाली रात को मशाल जलाकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हैं।
- **सरुंड माता मंदिर-** सोता नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर शक्ति की अराधना का केंद्र है। कोटपूतली को नीमकाथाना से जोड़ने वाले डाबला रोड स्थित ग्राम सरुंड में बना श्री सरुंड माता का मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है।
 - प्रतिवर्ष चैत्र व शारदीय नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। राजस्थान समेत देश के कोने-कोने से हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं।
 - कहा जाता है कि मंदिर में मां की मूर्ति पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापित की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मंदिर में स्थापित चिलाय देवी मां की मूर्ति पांडवों की कुल देवी का ही रूप है।
 - विभिन्न समाजों के लोग मां सरुंड की पूजा कुलदेवी के रूप में करते हैं।

- **विराटनगर बौद्ध मंदिर-** बीजक की पहाड़ी पर स्थित ये बौद्ध परिसर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अतीत के प्रमाण हैं।
 - इन्हें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में बनाया गया था, और उनके पास अशोक के दो लघु शिलालेख, बैराट और कलकत्ता-बैराट लघु शिलालेख पाए गए थे।
 - यह सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर है और इसलिए बैराट मंदिर भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण धरोहर है।
- **भाब्रू के शिलालेख-** इन शिलालेखों में सम्राट अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी के रूप में किया गया है।
 - ये भाब्रू पहाड़ियों के पास पाए गए लघु शिलालेख हैं जो अब एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित हैं।
 - इस शिलालेख में, अशोक को "पियादासी राजा मगधे" ("पियादासी, मगध का राजा") कहा गया है।
- **जैन नसियां, विराटनगर-** श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसियां (जिसे नसियाजी के नाम से भी जाना जाता है) राजस्थान के जयपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बैराट शहर के बाहर स्थित है।
 - श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसियां का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था।
 - मंदिर के चारों ओर जैन संतों का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ समाधियाँ हैं।
 - आचार्य शुभचन्द्र स्वामी की तपोभूमि तथा जैन मुनि श्री विमलसूरीजी की जन्मभूमि इस नगरी में मुख्य बाजार में दो भव्य प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर, दिलवाडा शैली में निर्मित 16वीं शताब्दी का श्वेताम्बर जैन मंदिर स्थित है
 - यहां विराजमान 1008 भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा 400 वर्ष प्राचीन है।
- **त्रिवेणी धाम-** (विधानसभा-विराटनगर एवं उपखंड-शाहपुरा में स्थित) विक्रमी संवत् 1795 में आचार्य गंगादास जी महाराज के द्वारा विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम की स्थापना की गई थी, जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर शाहपुरा के समीप अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है।
 - संत शिरोमणि गंगादास जी, जानकीदास जी, रामदास जी, भजन दास जी, भगवान दास जी और नारायण दास जी जैसे ही महान संतों की तपोस्थली त्रिवेणी धाम रहा है, जो 03 पवित्र जल धाराओं का संगम है जिसे 'धाराजी' के नाम से भी जानते हैं।
 - ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र जल के स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, यह प्रयागराज संगम की तरह एक पवित्र तीर्थ स्थल है।
 - महाराज श्री नारायण दास जी ने चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में पूण्यार्थ कार्य किये हैं। वर्तमान में त्रिवेणी धाम की गद्दी पर विराजमान संत श्री राम रिछपाल दास जी महाराज हैं।
- **श्री नीलका धाम-** श्री नीलका धाम ग्राम पंचायत आंतेला, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ में N.H. 48 से 2 किलोमीटर अन्दर सुन्दर मनोरम पहाड़ियों में स्थित है जहां श्री सीताराम जी का मंदिर है।

- इस मंदिर का पौराणिक इतिहास 400 वर्ष पुराना है। पहले मंदिर मौजूदा स्थान से 1.5 किलोमीटर अन्दर पहाड़ियों में स्थित था।
 - आज नीलका धाम मंदिर में चली आ रही संतों की यह परंपरा की 22वीं पीढ़ी चल रही है। अब से पांच पीढ़ी पूर्व संत सिरोमणी श्री मंगलदास जी महाराज हुए।
 - हाल ही में संत श्री धन्नादास जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे, जो बनारस विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर थे, वे 19 फरवरी को ब्रह्मलीन हो गए।
 - संत धन्नादास जी के दो शिष्यों श्री मोहनदास जी एवं श्री रामदास जी को इस महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधी प्राप्त हुई है।
 - मंदिर में बाबा मंगलदास जी महाराज गौशाला संचालित है जिसमें करीब 1000 गायें हैं और नंदीशाला में करीब 650 नंदी हैं।
 - आज नीलका में भव्य मंदिर व 2000 आदिमियों को एक साथ भोजन प्रसादी की सुन्दर व्यवस्था है।
 - नीलका धाम में खेली के पानी की महत्वता है। आज भी भक्तगण खेली का पानी ही लेकर जाते हैं।
- **मनसा माता मंदिर-** दहमी स्थित में मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान दूर-दूर से भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
- यह 600 साल से अधिक पुराना मंदिर है जिसमें लगा घंटा मराठा सरदार द्वारा स्थापित किया गया था।
- **बाबा खेतानाथ मंदिर-** नीमराना नगरपालिका क्षेत्र में स्थित गांव उमरावगढ़ में जौशीहोड़ा आश्रम पर बाबा खेतानाथ का मंदिर स्थित है।

आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारी की रणनीति

4.1 आपदा प्रबन्धन तैयारी योजना के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना

क्र. सं.	क्या करना है ?	कौन-कौन शामिल होगा ?	कार्य कैसे किया जाये ?
1	आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अति. कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि., जल संसाधन, पीएचईडी, विद्युत, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओ,वार्ड/पंचायत प्रतिनिधि	➤ पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं के इतिहास का आंकलन एवं विश्लेषण एवं चर्चा। ➤ नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकार्ड। ➤ पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति ➤ आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय
2	परिस्थिति का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। ➤ डेमोग्राफी/मानव के रहन सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। ➤ हेविटेशन पैटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। ➤ प्राकृतिक सम्पदा को नक्शा पर दर्शाना। ➤ सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पत्ति की सूची तैयार करना। ➤ सुरक्षित, संसाधन/संभावित नुकसान, सड़क,रेल,हवाई, अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।

3	खतरे का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ पूर्व अनुभव के आधार पर एवं रिकॉर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जीविकोपार्जन एवं सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है।
4	संवेदनशीलता का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ संवेदनशील जगहों एवं कारकों का अलग-अलग सूची तैयार कर नक्शा तैयार करना। ➤ संवेदनशील व्यक्ति जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे, गर्भवती एवं विधवा महिलाएँ, परिवार जो जर्जर एवं कमजोर मकानों में रहते हैं, का चिन्हीकरण एवं सूची बनाना। ➤ सम्पत्ति एवं पशुधन को चिन्हीकरण कर चारे का उचित प्रबन्धन, सभी कमजोर मकान एवं सुविधा एवं साधन का सूची तैयार करना। ➤ बांध, जल भराव क्षेत्र के कमजोर बिन्दुओं, ऑवरब्रिज पुल, ग्रिड एवं पावर हाउस, नहरी क्षेत्र, पानी की टंकी, जल प्रयोजना, पानी जमाव के निचले क्षेत्र, संभावित अग्नि खतरा क्षेत्र, उची इमारते एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर सूची बनाना। ➤ जल बहाव क्षेत्र का चिन्हीकरण
5	मौका / अवसर का विश्लेषण	उपरोक्त	➤ मौजूदा संसाधन का चिन्हीकरण जो लोगों के जीवन एवं सम्पत्ति के अनुसान को कम कर सके। ➤ ऊँचें प्लेटफार्म, खुली जगह, हाइड्रेन्ट पॉइन्ट, जल भण्डारण, सुरक्षित घर एवं राहत सामग्री व

			शिविरों के लिए उचित स्थानों का चिन्हिकरण। ➤ आश्रय स्थल के लिए जगह का चिन्हिकरण ➤ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का चिन्हिकरण ➤ सुरक्षित आपात निकासी का चिन्हिकरण ➤ आपात प्रबन्धन की तैयारी के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था एवं स्ट्रोंत की पहचान
--	--	--	---

4.2 खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान का विश्लेषण (एचवीआरए)

खतरा का वर्गीकरण

उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने खतरे को निम्न भागों में विभाजित किया है :-

क्र. सं.	सम्बन्धित आपदा	चिन्हित आपदा
1	जल एवं जलवायु संबंधित	1. बाढ़ एवं ड्रेनेज क्षति 2. तुफान 3. चक्रवात एवं हरिकेन 4. औलावृष्टि 5. बादल का फटना 6. लू एवं शीतलहर 7. बर्फबारी 8. बिजली का गिरना 9. समुद्र का कटना 10. सुखा
2	भूगर्भीय सम्बन्धित	11. भूकम्प 12. भूस्खलन 13. बंध का टूटना एवं बाध का नुकसान 14. खदान दुर्घटना
3	रासायनिक, आद्यौगिक, न्यूक्लियर संबंधी	15. रसायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना 16. रेडियोलॉजी आपात स्थिति एवं न्यूक्लियर आपदा

4	दुर्घटना सम्बन्धित	17. सड़क, रेल, जलपोत एवं अन्य परिवहन दुर्घटना 18. खदान बाढ़ 19. बड़े मकान गिरना 20. सीरियल बल बलास्ट 21. उत्सव के दौरान दुर्घटना 22. शहरी आग दुर्घटना 23. तेल बहाव 24. ग्रामीण आग दुर्घटना 25. नाव डूबना 26. जंगल की आग 27. बिजली दुर्घटना एवं आग
5	बायोलॉजिकल सम्बन्धित	28. महामारी एवं रोगों का फैलना 29. विषाक्त भोजन 30. पशु महामारी 31. किटाणु छिड़काव

4.3 रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेष रूप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संस्कृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। उम्रनतमे कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थत तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण।

स्ट्रक्चरल शमन उपाय— यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की और से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्टर प्लान स्पष्ट रूप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संसोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन परिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरूरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत-नियमितकरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बढ़ने पर एक योजना बनाना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्डिंग कोड सख्ती

से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही त्मजतवपिजजपदह भी विशेष सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं—

— मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

गैर संरचनात्मक शमन उपाय— गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रूप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

तैयारी क्रियाविधि— आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार कर के , पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। इस संबंध में क्वड। इस नियमित आधार पर तैयारियों के लिये उचित पद्धति सुझाएगा और जिले की विभिन्न गतिविधियों की योजना होगी।

जागरुकता कार्यक्रम— हर जगह हड़तालों, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यहां गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रृंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचाने के लिये आयोजित किया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रूप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे—

— जनसभाएं

— पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने

— नुक्कड़ नाटक

— इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी

— ऑडियो/विडियो शो

— बैनर और हॉल्लिडिंग

— चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रूप से स्कूलों में छात्र रैलियां

— अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

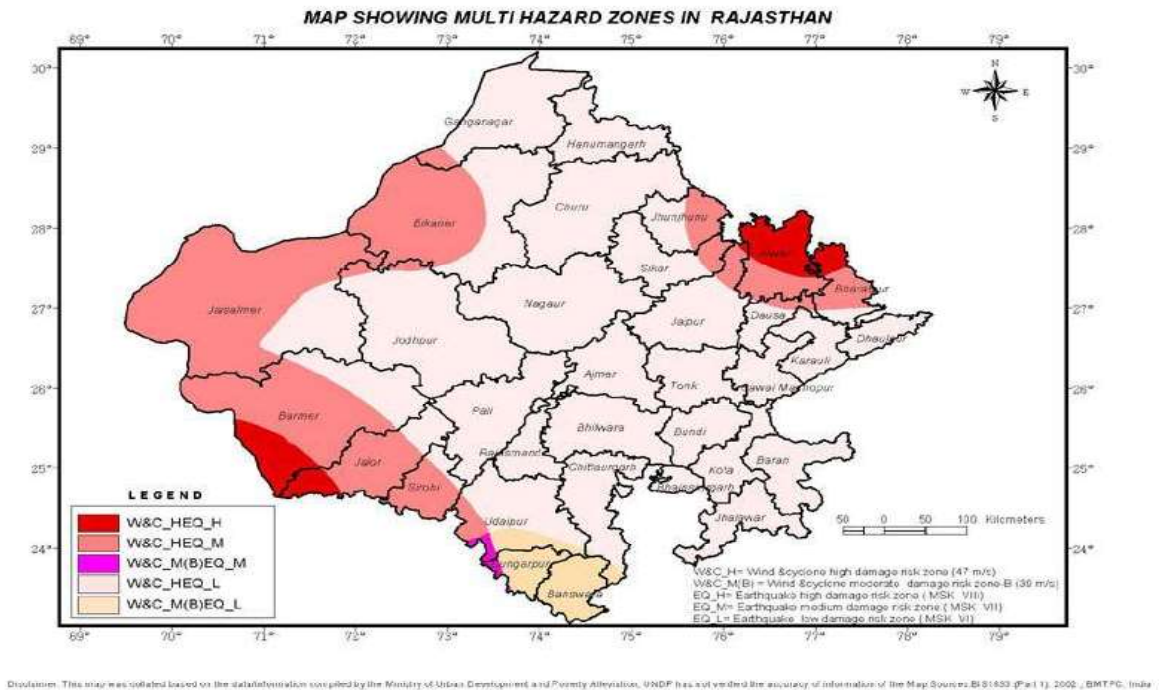
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण—विशेष समूहों और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है / किया जाएगा। सभी समुदाय आधारित संगठनों सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षेत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाएगा।

अध्याय 05

राजस्थान राज्य के खतरे की रूपरेखा

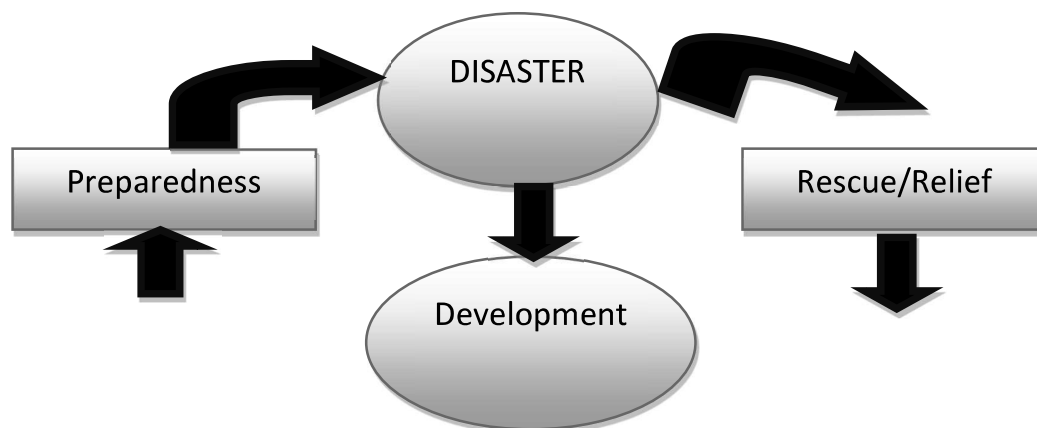
राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। बार—बार प्राकृतिक आपदा से राज्य में मानव, पेड़ पौधे, पशुधन, पर्यावरण एवं सम्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव होता रहा है। राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएँ सूखा, बाढ़, अग्नि, औलावृष्टि, आदि से काफी नुकसान होता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या न्यूनीकरण करने के लिए सरकारी एवं समुदाय के स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, फिर भी आपदाओं की भयावहता, आपातकालीन स्थिति, संसाधनों की कमी एवं संवेदनशीलता आपदा के परिणामों को गतिशील करता जा रहा है। जिससे नुकसान का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

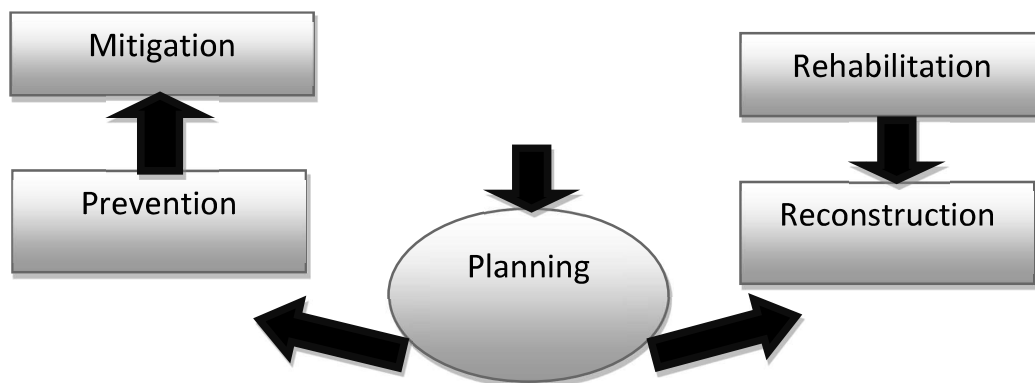
सामूहिक प्रयास एवं क्षमता संवर्धन को विकास कार्यक्रम से जोड़ना अति आवश्यक हैं। प्रभावशाली आपातकालीन तैयारी से लोगों के जीवन, पर्यावरण एवं संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता हैं।



5.1 आपदा प्रबन्धन चक्र

आपदा प्रबन्धन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कार्य करता हैं, एवं विकास की गति को बनाये रखता हैं। आपदा के तुरंत बाद की प्रतिक्रिया, बचाव, राहत, पुनर्वास के तरीकों को संचालित एवं प्रबन्धन करता है ताकि नुकसान को अधिक से अधिक कम कर सके, और प्रभावित न हो। यह एक सटीक आपदा प्रबन्धन योजना को निर्देशित करता हैं।

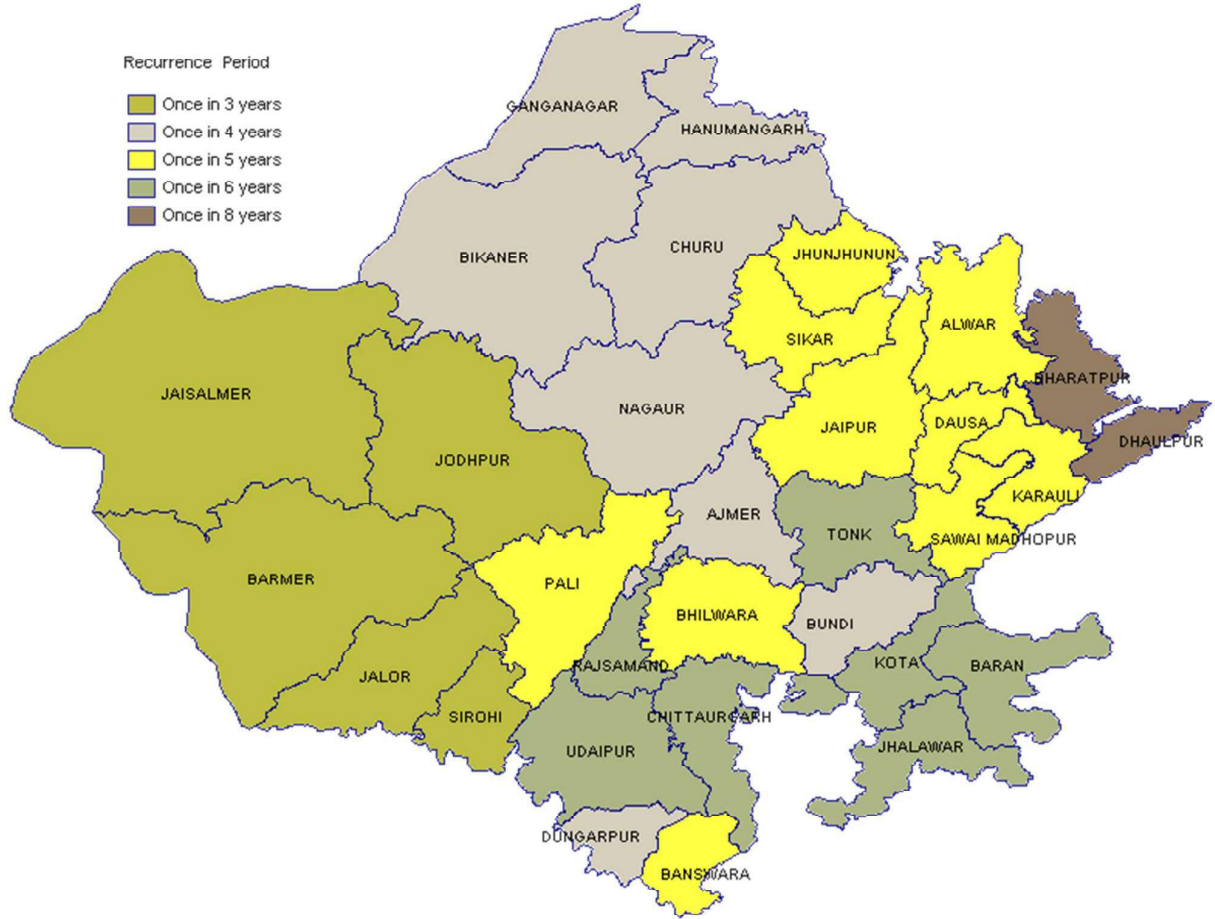




5.2 सूखा

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका परिमाण धीरे-धीरे एवं लम्बे समय तक रहता है। कम वर्षा एवं बेरुखी मौसम के स्वभाव से राजस्थान सूखा के मामले में अधिक संवेदनशील रहा है। राजस्थान का कोई न कोई जिला प्रत्येक 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 8 वर्ष में सूखा के चपेटे में रहने का इतिहास है। सूखे से जमीन की नमी समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भोजन उत्पादन एवं आर्थिक संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है। सूखे का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल पर होता है, और विपरीत परिणाम भूकम्प और बाढ़ से अधिक होता है। सूखा का प्रबन्धन अधिक कठिन है। कुपोषण एवं महामारी सूखे का सीधा परिमाण होता है।

राज्य सूखा मॉनिटरिंग सेल, कृषि, पशु विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राष्ट्रीय फसल पुर्वाग्रह केन्द्र के सहयोग से फसल के नुकसान, फसल पैदावार पानी के संसाधन की कमी, पशुधन चारा पर प्रभाव, जंगलों एवं पेड़ पौधों पर सूखा पर प्रभाव, जमीन की गुणवत्ता का आंकलन, मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभावी कार्य योजना बनाते हैं।



5.3 बाढ़

राजस्थान का कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। पिछला इतिहास देखें तो राज्य का अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लूणी एवं चम्बल नदी के आस-पास के बेसिन क्षेत्र में रहा है। राज्य में कुल 13 नदी के स्त्रोत/बेसिन है। जैसे शोखावटी, रूपरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, बनास, चम्बल, माही, साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास व सुखली। जिसमें से लूणी, बनास एवं चम्बल बेसिन सबसे बड़ा है, एवं कई छोटे-छोटे बेसिन में बंटा हुआ है, इन नदियों में लूणी नदी अजमेर, बाढमेर, जालौर और जोधपुर से होकर गुजरती है। इसमें सब बेसिन का स्त्रोत मूंद हमावास, सुखडी, जवाय एवं बेंदी का स्त्रोत पाली, जालौर, सिरोही है। इसी प्रकार बनास नदी का बेसिन उदयपुर एवं बूंदी में होकर जाता है, एवं इसका सबबेसिन बैराज, मोरेल, एवं मासी चितोडगढ, एवं जयपुर जिले से गुजरता है। चम्बल का स्त्रोत राज्य में सबसे अधिक है, इसके सब बेसिन काली सिंध एवं पार्वती, बूंदी, कोटा, झालावाड एवं बांरा से गुजरती है। भरतपुर जिले का अधिक भाग बाणगंगा के बेसिन

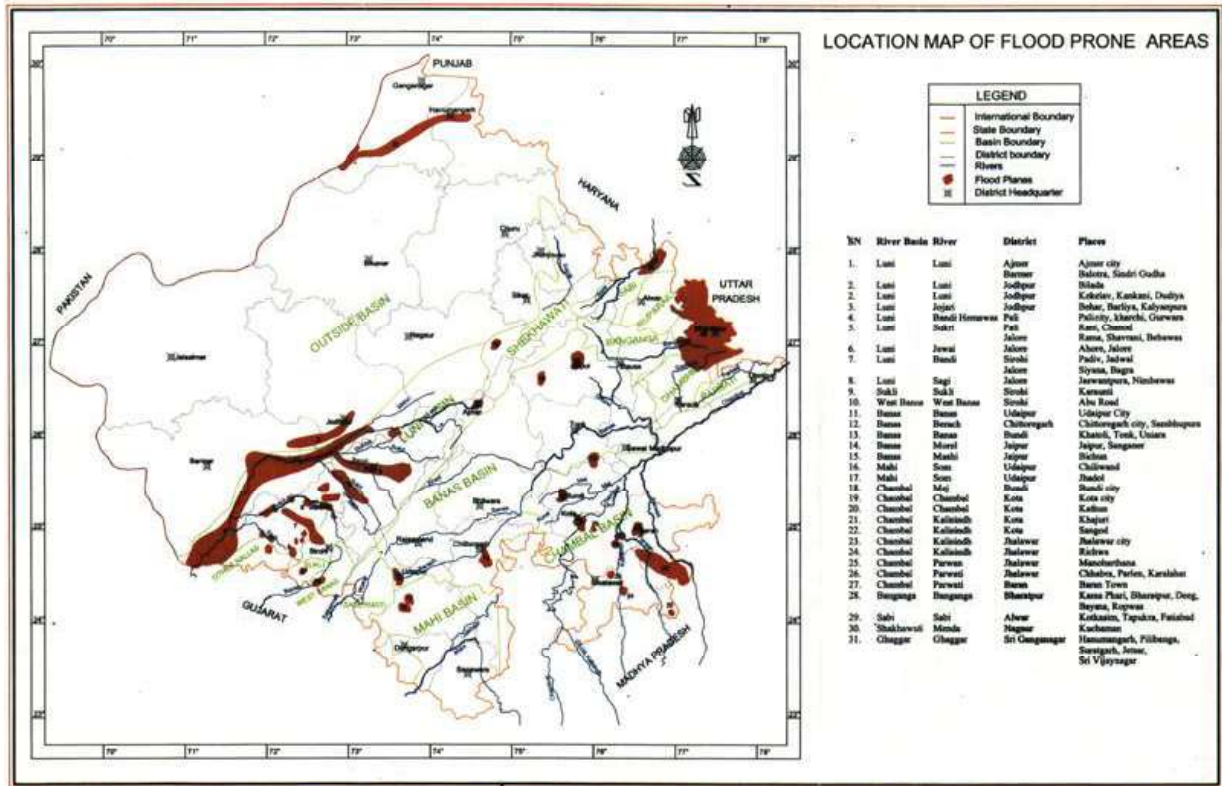
में आता है एवं घग्घर नदी गंगानगर जिले को सबसे अधिक प्रभावित करने का इतिहास रहा है।

क्षेत्र में बाढ़ के मुख्य कारक

1. केचमेंट क्षेत्र में अधिक वर्षा।
2. अचानक अधिक मात्रा में बांध एवं जल संग्रहण क्षेत्र से पानी को छोड़ना।
3. बड़ें जल संग्रहण क्षेत्र/बांध का टूटना या क्षतिग्रस्त होना।
4. कम जल संग्रहण क्षमता।

शहरी बाढ़

शहरी बाढ़ एक मानवीकृत आपदा है, अव्यवस्थित एवं बढ़ती शहरी आबादी अचानक बाढ़ या शहरी बाढ़ के मुख्य कारक है। ड्रेनेज का नहीं होना, वर्षा जल के स्वाभाविक बहाव में रुकावट एवं जल का जमाव होना, निचले क्षेत्रों में आबादी का बढ़ना शहरी बाढ़ को दिनों दिन गतिशील कर रहा है। जिसके कारण, महामारी एवं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ से लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाना, अधिक पानी के बहाव से कमजोर मकानों का गिरना एवं संसाधन की कमी, स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1981 एवं 2002 में जयपुर शहर में आयी अचानक बाढ़ से जयपुर शहर को भारी नुकसान हुआ था।



5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उदगम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

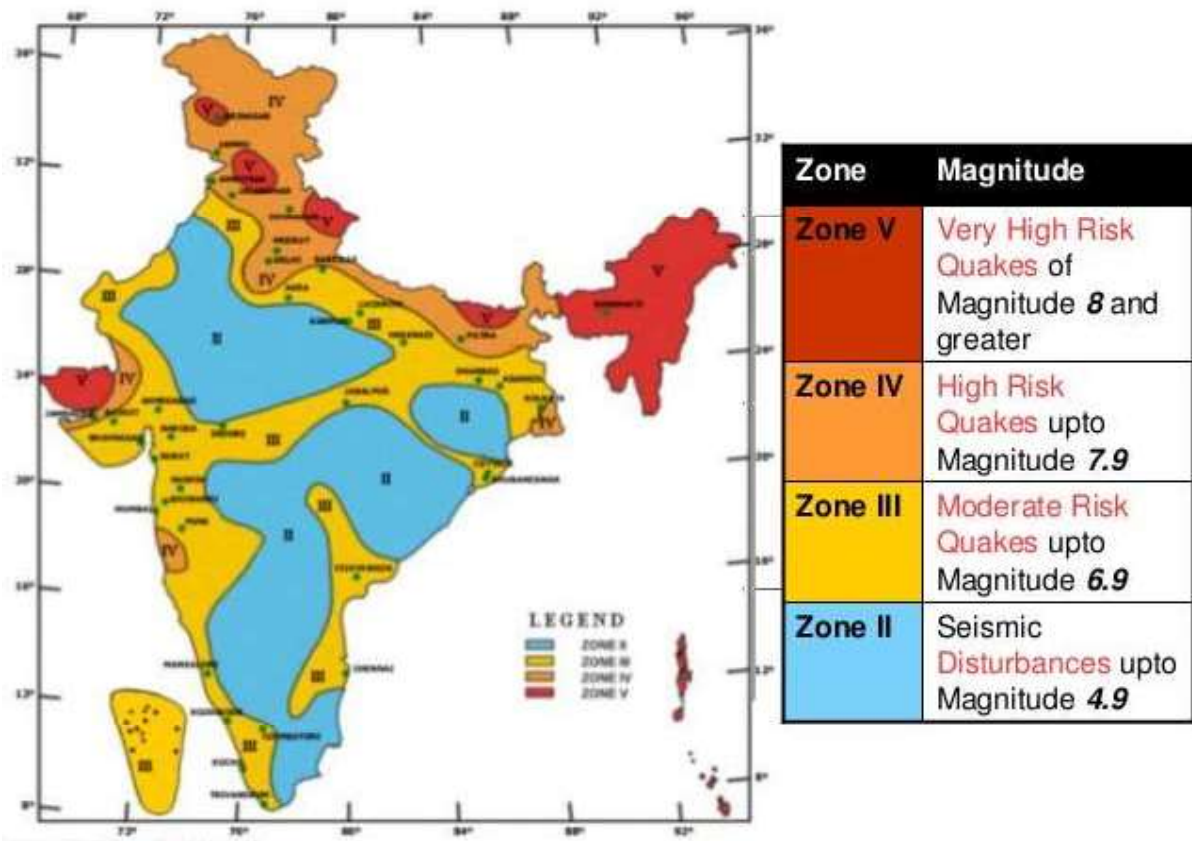
भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं

को भी हानि पहुंचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी. दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

1. ज्वालामुखी क्रिया
2. भ्रंशन
3. भूसंतुलन में अव्यवस्था
4. जलीय भार
5. भूपटल में संकुचन
6. गैसों का फैलाव
7. प्लेट विवर्तनिकी



Source: IS 1893 (Part 1) : 2002 (BIS)

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काउंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मरकरी मापक पर 4–5 तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि 9–10 तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

- 1) क्षेत्र V – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार 5 या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- 2) क्षेत्र IV- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड टप्प संभावित है इसे उच्च नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 3) क्षेत्र III- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर डड टप्प की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 4) क्षेत्र II – क्षेत्र में संभावित तीव्रता डड टप्प इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान संभावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 5) क्षेत्र I – इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर डडट या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम	संभावित प्रभावित क्षेत्र
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0	
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5	
साधारण एवं आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं। चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न	4–4.8	गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धोलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर के कुछ भाग, उदयपुर, झुन्झुनू, सीकर एवं जयपुर।
अतिप्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है। दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5–5.9	उदयपुर के कुछ भाग सिरोही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुन्झुनू, सीकर के कुछ भाग, जयपुर, कोटपूतली–बहरोड एवं भरतपुर।
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2	
विनष्टकारी	मकान धंस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती है। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9	बाडमेर के कुछ भाग(चोहटन ब्लॉक), जालौर (सांचोर ब्लॉक), अलवर(तिजारा ब्लॉक), भरतपुर (ब्लॉक नगर पहाड़ी)
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है	7.0–7.3	

अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1	
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।		

5.5 जिला खतरा एवं नुकसान का विश्लेषण

आपदा का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई–सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	उँची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियाँ
तापघात	अप्रैल–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिले के सभी भाग
अग्नि	मार्च–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल,

		प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सड़क परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल-अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
सड़क दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
औलावृष्टि	मार्च- मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

5.6 आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के जिम्मेदार विभाग

क्र.सं.	जिम्मेदार विभाग	आपदा एवं खतरा
1	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सूखा, औलावृष्टि, लू एवं शीतलहर, बिजली गिरना, तूफान, भूस्खलन
2	ऊर्जा विभाग	बिजली वितरण एवं उत्पादन में आपदाएँ
3	गृह विभाग	आतंकवादी घटना, कानून व्यवस्था बिगड़ना, साम्प्रदायिक तनाव, रेल, सड़क, हवाईजहाज दुर्घटना, बायोलॉजिकल, रासायनिक न्यूक्लियर,

		रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति, मेला एवं उत्सव के दौरान दुर्घटनाएँ।
4	जल संसाधन विभाग	बाढ़, अचानक तेज पानी का बहाव, बांध का टूटना, बादल का फटना
5	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बड़ी ईमारतों का गिरना, सड़क दुर्घटना।
6	खदान एवं पट्रोलियम विभाग	खदान अग्नि एवं बाढ़ दुर्घटना, तेल रिसाव।
7	उद्योग विभाग	रासायनिक एवं आधोगिक दुर्घटना।
8	शहरी विकास विभाग	शहरी अग्निकांड
9	राजस्व	ग्रामीण अग्निकांड एवं नावों का डूबना
10	वन विभाग	जंगल की आग।
11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	बायोलॉजिकल, महामारी एवं विषाक्त भोजन।
12	कृषि विभाग	कीटाणु नाशक का छिड़काव।
13	पशुपालन विभाग	पशुओं में महामारी।

कोटपूतली-बहरोड जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारिरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

6.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन आपदाओं को चिन्हित किया है उन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया गया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।

- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** — रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** — आग, बम विस्फोट, वायु, सडक, एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** — महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया गया। जिले में संभावित 11 आपदाएँ चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पांच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। छः मुख्य विपदाएं निम्न हैं—

1. सूखा
2. आग
3. सडक दुर्घटनाएं
4. साम्प्रयादिक दंगे
5. भूकम्प
6. बाढ़

इसके अलावा अन्य 5 विपदाएं ओलावृष्टि, खुले बोरवेल की दुर्घटनाएं, औद्योगिक विपदाएं, ताप, शीतघात इत्यादि हैं।

6.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगो के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना के समय पर निर्भर करती हैं।

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

(ब) पक्की हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपडियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिला भूकम्प के दृष्टिकोण से लो डेमेज रिस्क जोन में हैं। अतः भूकम्प से नुकसान की संभावना बहुत कम है।

(ब) पक्की हुई ईंटें या बड़े पत्थर के घर

जिले में पक्की हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(ग) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचे के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक किया जा सकता है।

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपडियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपडियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सैं. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

जिले के खतरे एवं नुकसान का विश्लेषण

खरते का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ़	जुलाई—सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	निचले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	उँची ईमारत, कमजोर मकान, अपार्टमेन्ट, दुकान, मॉल, पुल, बांध, घनी, आबादी बस्तियाँ
तापघात	अप्रैल—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव	जिले के सभी भाग
अग्नि	मार्च—जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	शहरी क्षेत्र, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कच्चे मकान
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान	औद्योगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल—अगस्त	मानव एवं पशुधन का नुकसान	जिले के सभी भाग
सडक दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पत्ति का नुकसान	जिले के सभी भाग
औलावृष्टि	मार्च— मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग

अध्याय 07

प्रशासन के द्वारा सामान्य कार्य योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु-अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

7.1 जिला आपदा प्रबंधन :

1. समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
2. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।
3. संभावित आपदाओं का विवरण अभिलेखन रखना व उसके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।
4. जिला में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।

5. जिला में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
6. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
7. जिला में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही कर क्रियान्वयन करना।
9. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।
- 10.

7.2 संस्थागत व्यवस्था

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप

धारा 25 के अनुसार जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	प्राधिकरण में पदभार	सम्पर्क
1	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड	अध्यक्ष	01421-299177,9414648780
2	जिला प्रमुख कोटपूतली-बहरोड	सह-अध्यक्ष	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटपूतली-बहरोड	सदस्य	9999353741
4	पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड	सदस्य	9414000039
5	अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी कोटपूतली-बहरोड	सदस्य	9414537005
6	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन कोटपूतली-बहरोड	सदस्य	9414545917
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली-बहरोड	सदस्य	9828261988
8	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) कोटपूतली-बहरोड	सचिव	9413514599

निम्न गणमान्य जनप्रतिनिधि स्थाई रूप से प्राधिकरण में आमंत्रित रहेंगे

सांसद/विधायकगण जिला कोटपूतली-बहरोड			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण

विधायक, कोटपूतली	श्री हंसराज पटेल	कोटपूतली	कोटपूतली
विधायक, बानसुर	श्री देवी सिंह शेखावत	बानसुर	बानसुर
विधायक, विराटनगर	श्री कुलदीप धनखड़	विराटनगर	विराटनगर
विधायक, बहरोड	श्री जसवंत यादव	बहरोड	बहरोड

प्राधिकरण के अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से जो उपयुक्त होगा किसी भी व्यक्ति विशेष व विशेषज्ञ को प्राधिकरण की बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार हैं।

- जिला कलक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में प्रतिवर्ष 15 जून से माह सितम्बर तक आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है।

जिला संकट प्रबन्धन समूह :-

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय-समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जाँच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना है। इसमें निम्न सदस्य रहेंगे :-

क्र.सं.	पद एवं पदनाम	समिति
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	कारखाना निरीक्षक	सदस्य सचिव

3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	प्रतिनिधि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद	सदस्य
5	उप नियंत्रक विस्फोटक	सदस्य
6	अधिकांशी अभियंता पीएचईडी/पीडब्ल्यूडी/जल संसाधन/बिजली	सदस्य
7	अधीक्षक मुख्य अस्पताल/सीएमएचओ	सदस्य
8	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
9	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
12	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
13	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
14	अध्यक्ष उद्योग संघ/रीको	सदस्य
15	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
16	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	सदस्य

जिला अधिकांशी समिति (डीईसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व/सहायता होता है।

क्र. सं.	पद एवं पदनाम	समिति में पद
----------	--------------	--------------

1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	अध्यक्ष
2	आयुक्त नगर परिषद	सदस्य
3	अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	सीएमएचओ	सदस्य
5	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
6	जिला सूचना एवं जन जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
7	अधिकाधी अभियंता पीएचईडी / पीडब्ल्यूडी / जल संसाधन / बिजली	सदस्य
8	सेना अधिकारी	सदस्य
9	समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
10	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
11	रेल्वे अधिकारी	सदस्य
12	अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
13	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
14	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15	अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
16	अधिकारी सिविल डिफेंस	सदस्य
17	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
18	अध्यक्ष, उद्योग संघ / रीको	सदस्य
19	प्रबन्धक तेल कम्पनी	सदस्य
20	विषय विशेषज्ञ रसायन एवं आपदा प्रबन्धन	विशेष आमंत्रित

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, एवं तहसीलदार एवं अन्य विभाग उसे आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति, ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशु चिकित्सक, महिला बाल विकास अधिकारी इत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। उपखण्ड की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष में एक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विकास अधिकारी	सदस्य
4	नायब तहसीलदार/ गिरदावर	सदस्य
5	सहायक अभियंता विद्युत	सदस्य
6	सहायक अभियंता सा.नि.वि	सदस्य
7	सहायक अभियंता पीएचईडी	सदस्य
8	सहायक अभियंता खनन	सदस्य
9	चिकित्साधिकारी	सदस्य
10	कृषि अधिकारी	सदस्य
11	पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
12	ईओ नगरपालिका/आयुक्त नगरपरिषद	सदस्य
13	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	सदस्य
14	ब्लॉक महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मनोनीत अध्यक्ष सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत्त दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन का विकास, आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवं सहायता प्रदान करना एवं जान-माल के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजाना के अनुरूप होगी जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पद
1	सरपंच	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव	सदस्य
3	ग्राम पटवारी	सदस्य
4	चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य
5	पशु चिकित्साधिकारी (यदि हो)	सदस्य सचिव
6	स्थानीय पुलिस अधिकारी	सदस्य
7	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (स्कूल/कॉलेज)	सदस्य
8	एक सेवानिवृत्त सैनिक	सदस्य
9	एएनएम	सदस्य
10	स्वयंसेवी संस्था के मनोनीत सदस्य	सदस्य

11	आंगनबाडी कार्यकर्ता	सदस्य
----	---------------------	-------

7.3 कार्य योजना के उद्देश्य :-

सुचारु योजना के अभाव में आपदा आने पर इससे निपटने एवं कार्यों का समन्वय नहीं हो पाता। प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं समुचित योजना की कमी से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक घटना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिससे नुकसान की गंभीरता अधिक हो जाती है तथा स्थिति भयावह हो जाती है। जान-माल एवं प्राकृतिक सम्पदा की अधिक से अधिक क्षति होती है।

अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति- आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
2. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
3. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
4. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोंतो की सूची तैयार करना।
5. स्त्रोंतो के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
6. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
7. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 2ए में वर्णित प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर जिले में घटित किसी भी आपदा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर (जिला मुख्यालय) जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- जिला कलेक्टर द्वारा संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवाना तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करना तथा सूचना सचिव सहायता को भेजना।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों की स्थाई व्यवस्था, इसे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेते हैं।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना।

7.4 नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में 24 घंटे संचालित है।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. उपलब्ध है। जिला नियंत्रण कक्ष (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) के फोन नं. 01421-299036 एवं टॉल फ्री 1077 है।

7.5 जिला एवं स्थानीय प्रशासन

1. आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
2. रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
3. नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
4. सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
5. प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
6. प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
7. दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
8. आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाना।
9. जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

नगर परिषद / नगरपालिका / ग्राम पंचायत कार्ययोजना

1. जिला प्रशासन के साथ उपरोक्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में संसाधन का भण्डारण एवं आपातस्थिति में उपयोग सुनिश्चित करना होता है।
 2. आपदा के समय अधिक से अधिक लोगों को बचाव कार्य में लगाना एवं राहत प्रदान करना है।
 3. आपदा के पूर्व रोकथाम के लिए आवश्यक कदम साफ— सफाई, नालों का रख—रखाव, महामारी रोकने का उपाय, अग्निशमन विभाग की देखभाल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
 4. आपदा के बाद मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।
 5. आवश्यक बचाव उपकरणों की खरीद, संसाधन का रख—रखाव सुनिश्चित करना है।
 6. सहायक अग्निशमन अधिकारी श्री सत्यनारायण (मो.8947061263) फायर स्टेशन पर निम्नलिखित उपकरण/सामग्री सदैव तैयार रखेंगे। जैसे अग्निशमन वाहन फौम कैन/बीए सैट ऑक्सीजन से भरे हुये सिलेण्डर मास्क इत्यादि।
 7. प्रभारी अधिकारी स्टोर शाखा/स्टोर कीपर निम्न लिखित आवश्यक सामग्री सदैव तैयार रखेंगे जैसे—रस्से, आपातकालीन लाईट, बल्लिया, ट्यूब, गैंती, फावड़े, पंजा, हतोडे, डी.टी.टी. पाउडर, वैल्विंग मशीन, हाथ आरा मशीन, 100 कट्टे मिट्टी से भरे हुए तैयार रखेंगे एवं ड्रेगन लाईट, ट्यूब, गैस मास्क, इत्यादि।
 8. प्रभारी अधिकारी गैराज शाखा नगर परिषद के वाहन जैसे— जे.सी.बी. मशीन, नैनो सीवर जैट/कॉम्पेक्टर, मैला वाहन (बड़ा या छोटा), टैम्पू बिना कैरियर, ऑटो टिप्पर, मड़ पम्प पानी का टैंकर इत्यादि वाहन एवं 200 लीटर डीलज व आवश्यकतानुसार ऑयल सदैव तैयार रखेंगे।
 9. मुख्य सफाई निरीक्षक नगर परिषद के सफाई संवेदक से उपलब्ध संसाधन जैसे— जे. सी.बी. ट्रैक्टर मय ट्रौली, लोडर, डम्पर व टैम्पू इत्यादि की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 10. प्रभारी अधिकारी रोशनी शाखा विधुत सप्लाई कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सैट/जनरेटर/इन्वैटर मय बैटरी बैकअप कि उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
 11. प्रभारी अधिकारी निर्माण शाखा नाव/तैराक की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 12. प्रभारी अधिकारी अन्नपूर्णा रसोई समस्त अन्नपूर्णा रसोईयो पर अपातकालिन समय में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखेंगे।
- आपदाओं से निपटने के मुख्य रूप से निम्नलिखित संसाधन नगर परिषद कोटपूतली में उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	उपलब्ध संसाधन
1.	जे.सी.बी.-2
2.	मैला वाहन -2
3.	पानी का टैंकर -2
4.	अग्निशमन वाहन-2
5.	फौम- कैन
6.	ऑटो टीप्पर-14
7.	नैनो सीवर जेट-
8.	कॉम्पेक्ट-
9.	टैक्टर मय ट्रौली -10

संवेदक के संसाधन :-

क्र. सं.	उपलब्ध संसाधन
1.	जे.सी.बी.-2
2.	टैक्टर मय ट्रौली -10
3.	लोडर -01
4.	डम्पर -
5.	ऑटो टीप्पर-14

किसी भी प्रकार के आपदा आने पर प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष में सभी प्रभारी अधिकारी/सहयोगी/समस्त सफाई निरीक्षक/सैक्टर प्रभारी नियंत्रण कक्ष में तुरन्त एकत्रित होंगे एवं अपने-अपने क्षेत्र में बचाव व राहत कार्य के लिये जायेंगे।

7.6 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल

विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

1. आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
2. खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
3. लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
4. आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
5. बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

7.7 अग्नि एवं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वर्क्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है, घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं।

अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकांड मानवजनित होते हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती हैं। जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड रबी की सूखी फसल में बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है।

जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र –

शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प छविगृह, कृषि उपज मण्डी, गैस एजेन्सी, आदि है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ –

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं लेकिन जिले में ज्वलनशील इकाईयाँ नहीं होने के कारण तथा अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के भण्डारण नहीं होने के कारण यहां ऐसी संभावना कम हैं।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियाँ—

बिजली :-

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना करें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हों।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :-

रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिए।

- गैस सिलेण्डर या नली को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नली आई.एस.आई. मार्का की ही होनी चाहिए।
- साडी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिडकीदार हों।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।

- गैस ज्यादा लीकेज हो तो उपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसाई के सारे खिडकी दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चुल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीडी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मानते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीडी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे कि आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हों।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैंकने चाहिए।
- खलिहानों या कच्चे छप्परो के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

- गावों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर पार्टी की स्थापना की जावे जहां घण्टी, फावड़े, बाल्टी, टार्च, रस्सी, खाली बोरियों परात, नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि हों।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़ें या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सके।
- बिल्डिंग कोड भारतीय मानक संहिता 2005 के अनुरूप, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना। फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट

बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।

- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार व जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त मौके के अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि जिला मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष “समेकित आपदा प्रबन्ध समिति” को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं।

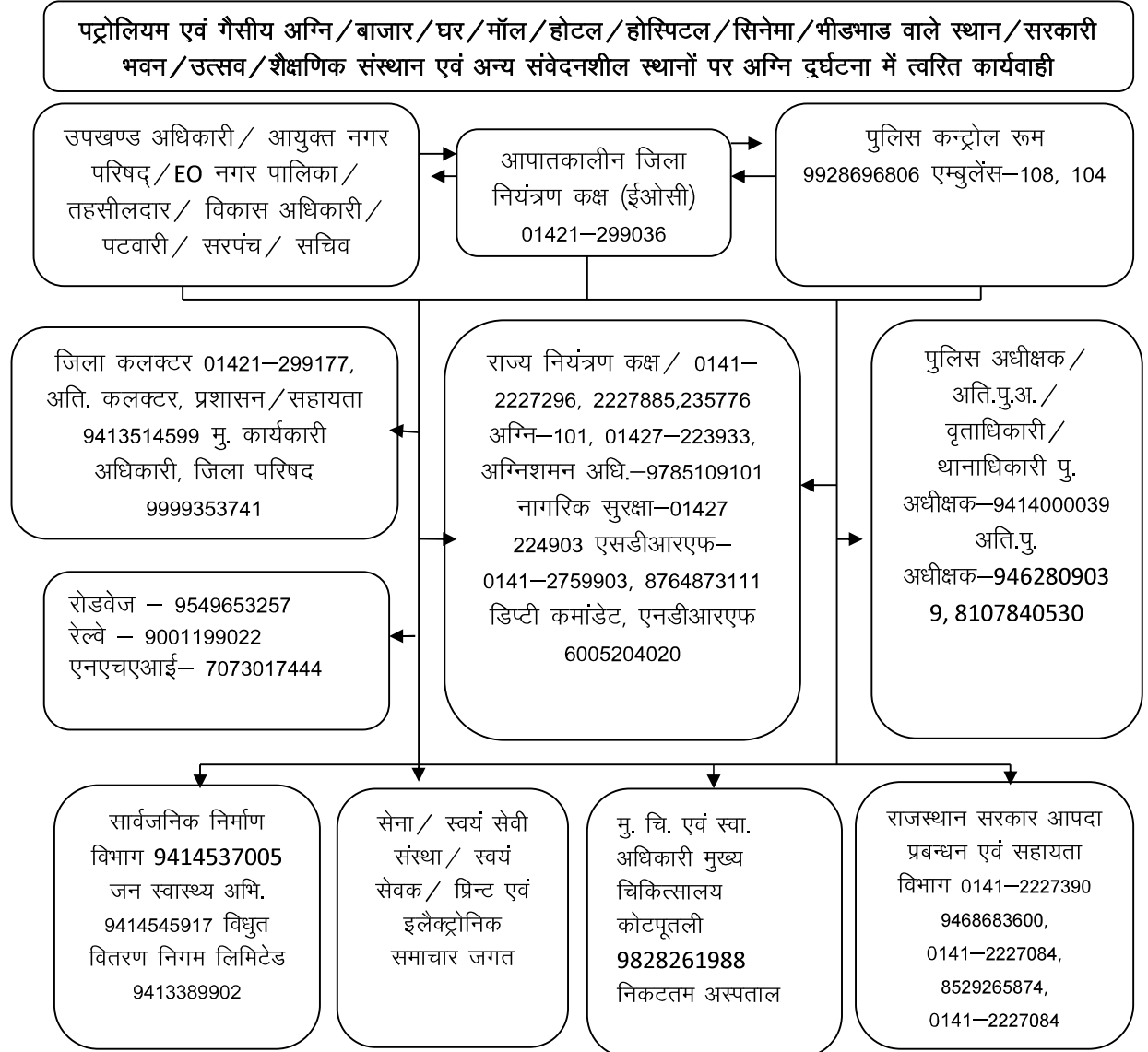
यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिला कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका :-

जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।

- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञान करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं।



अग्निशमन केन्द्र : नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों एवं कर्मियों की उपलब्धता

- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

1. आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचना।
2. आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करना।
3. आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
4. कानून व्यवस्था में मदद करना।
5. आश्रय स्थलों पर व ट्रॉफिक व्यवस्था में प्रशासन की सहायता करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- यातायात की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- सेवाओं के घटना स्थल पर पहुंचने के मार्ग से बाधा हटाना व उन्हें सही रास्ते के दिशा निर्देश देना।
- घटना स्थल पर वीआईपी विजिट की स्थिति में आवश्यक प्रबन्धन करना जिससे आवश्यक सेवाओं के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- बचाव कार्यों में मदद करना।
- घटना स्थल की घेराबन्दी करना।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल करना।
- संबंधित अभियन्ता मय स्टाफ आपदा स्थल पर तत्काल रिपोर्ट करे।
- आपदा स्थल पर प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई/कटौती की उचित व्यवस्था।
- विद्युत सप्लाई बन्द के दौरान आपदा स्थल पर आवश्यक विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- विद्युत लाईनों (उपरी/भूमिगत) की उचित देखभाल करना जिससे अनावश्यक विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोंतो से जल की उचित आपूर्ति।
- संबंधित अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक हुआ तो पानी की सप्लाई बन्द करेंगे व आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवायेंगे।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता को देखते हुए हाईड्रैन्ट्स को चालू हालात में रखना, विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में टैंकरों से अग्निशमन हेतु आवश्यक पानी सप्लाई करवाना।
- गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा खपत को देखते हुए आवश्यक पानी की सप्लाई बनाये रखने की व्यवस्था करें। उपभोक्ताओं द्वारा घरों में बुस्टर लगा कर पानी खेंचने पर अंकुश लगावें।
- वर्षा के मौसम के दौरान पानी में आवश्यक क्लोरीन की व्यवस्था करावें ताकि दूषित पानी से निजात मिल सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना।
- घटना/आपदा स्थल पर तत्काल एम्बूलेंस मय मेडीकल स्टॉफ भिजवाना।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।

- हताहतों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाना ।
- औषधियों की उचित व्यवस्था करना ।
- मेडिकल स्टोर/ थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क रखना ।
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता ।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना ।
- समय समय पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आवश्यक सेनिटेशन की व्यवस्था करना व खान पान की वस्तुओं को चैक करना ।
- स्वयं सेवी एजेन्सीयों से सम्पर्क करना ।

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना ।
- राहत शिविर लगाना ।
- सहायता सामग्री का वितरण ।

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना ।
- आपदा की स्थिति में जानवरों की बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक टीकाकरण/ औषधियों की व्यवस्था करना ।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की तैनाती ।
- आपदा के पश्चात मृत जानवरों से महामारी की स्थिति न बने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

नगरपालिका/ नगर निगम

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन ।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना ।
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकार स्थितियों की देखभाल । राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची ।

- आश्रय स्थलों की उचित सफाई व्यवस्था।
- घटना स्थल पर आवश्यक लाईट की व्यवस्था करना।
- मृत लोगों व जानवरों के अन्तिम संस्कार/ दफनाने की व्यवस्था करना।
- महामारी की स्थिति से बचाव के उपाय करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना।

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें :-

क्या करें —

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त नगर निगम जयपुर को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :-

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

7.8 आकाशीय बिजली बचाव कार्य योजना:—

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम एप “सचेत” एवं प्लव द्वारा आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व चेतावनी हेतु “दामिनी” मोबाईल एप के आमजन में प्रचार प्रसार हेतु जिले के पदाधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित किया जाता है। ताकि प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व जनसाधारण को आपदा की जानकारी उपलब्ध हो सके एवं आपदा के नुकसान से बचा जा सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आकाशीय बिजली के संपर्क से बचने के लिए, कुछ सुरक्षा युक्तियाँ और शमन उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैं।

घर से बाहर रहने की स्थिति में करने योग्य उपाय:—

1. कोई भी बाहरी गतिविधियाँ शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। आंधी चलने और बिजली गिरने की स्थिति में 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहें।
2. गर्जना हो तो आश्रय लें और सुरक्षित स्थान या भवन के अंदर रहें। धातु के साथ धातु संरचनाओं और निर्माणों से दूर रहें। आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और बंद खिड़कियों वाले हार्ड—टॉप वाहन शामिल हैं।
3. कृपया ऊँचे स्थानों जैसे पहाड़ियों या टीलों, या चोटियों से तुरंत उतर जाएँ।
4. खुले क्षेत्र में बिजली गिरने की स्थिति में, तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर निकलें और पास के सुरक्षित स्थान पर शरण लें। आदर्श रूप से किसी निचले इलाके में आश्रय ढूँढ़ें और सुनिश्चित करें कि वही स्थान चुना गया है।
5. बिजली गिरने की स्थिति में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।

6. बिजली का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं जैसे टेलीफोन, बिजली, डमजंस थमदबसे, ओवरहेड तार, रेल— सड़क ट्रैक, पवन चक्कियां आदि, पेड़ों और पहाड़ियों से दूर रहें।
7. यदि आप तूफान और बिजली गिरने के दौरान समूह में हैं तो जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
8. रबर— सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

क्या न करें

1. प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशी चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने या सामान्य यात्रा करने के लिए घर से बाहर न निकलें।
2. यदि आप वन क्षेत्र में हैं तो छोटे और बौने पेड़ों के नीचे आश्रय लें।
3. बिजली गिरने के दौरान बिजली या टेलीफोन के खंभों या पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।
4. धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें और बाइक, बिजली या टेलीफोन के खंभे, तार की बाड़, मशीनों आदि से दूर रहें।
5. यदि आप खुले मैदान/आउटडोर में काम कर रहे हैं और आपके पास सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो अपने पैरों को एक साथ सटाकर रखें अर्थात् एडियां एक—दूजे को स्पर्श करते हुए रखे एवं सिर को झुकाकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें और अपने हाथों को अपने कानों पर रखें, ताकि जमीन के साथ न्यूनतम संपर्क हो।
6. बिजली गिरने के दौरान कभी भी मोबाइल फोन और लोहे की छड़ वाले छाते का उपयोग न करें।

घर के अंदर सुरक्षित रहने हेतु करने योग्य उपाय:—

हालांकि बिजली तूफान के दौरान घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों जैसे आश्रयों को सुरक्षित माना जाता है, फिर भी व्यक्ति जोखिम में हो सकता है। यहां रखने के लिए कुछ युक्तियां दी गई हैं

1. संचार के विभिन्न तरीकों से अपडेट और चेतावनी निर्देशों के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करते रहें।
2. यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें और यात्रा से बचें।
3. दरवाजों, खिड़कियों, बरामदों और कंक्रीट के फर्श, फायरप्लेस स्टोव, बाथटब या किसी अन्य विद्युत कंडक्टर से दूर रहें।
4. विद्युत आउटलेट से जुड़े विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव या अन्य चीजों को अनप्लग करें, क्योंकि मुख्य बिजली आपूर्ति के दौरान बिजली की आपूर्ति बढ़ सकती है।
5. बिजली के साथ तूफान आने पर खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और अपने घर के बाहर की वस्तुओं (जैसे फर्नीचर, डिब्बे, आदि) को सुरक्षित रखें।
6. सुनिश्चित करें कि बच्चे और पालतू जानवर अंदर ही रहें।
7. पेड़ की लकड़ी या कोई अन्य मलबा हटा दें जो उड़कर दुर्घटना का कारण बन सकता है।

क्या न करें

1. बिजली और गरज के समय, बारिश के दौरान स्नान न करें, रुके हुए या बहते पानी के साथ कोई अन्य संपर्क न रखें क्योंकि बिजली किसी इमारत के प्लम्पिंग और धातु के पाइपों से होकर गुजरती है। तार वाले फोन या किसी धातु के तार/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें।
2. कार्ड वाले फोन और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालाँकि, बिजली और तूफान के दौरान तार रहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है।
3. खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट, खुली संरचनाओं/स्थानों जैसे पोर्च, खेल के मैदान जैसे गोल्फ कोर्स, पार्क और खेल के मैदानों, तालाबों, झीलों, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से बचें।

यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें:-

1. बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जाँच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है, तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें।
2. परिवर्तनीय मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और खेल के मैदान जैसी खुली संरचनाओं का होना सुनिश्चित करें।
3. आंधी और बिजली के दौरान गोल्फ कोर्स, पार्क, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तट जैसे खुले स्थानों से दूर रहें।
4. साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से तुरंत उतर जाएं जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं।
5. यदि नौकायन या तैराकी हो तो यथाशीघ्र उतरें और किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें।
6. तूफान खत्म होने तक मदद पहुंचने तक वाहन के अंदर ही रहें क्योंकि धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। आंधी और बिजली गिरने के दौरान खिड़कियां ऊंची रहनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली लाइनों से दूर खड़ा किया जाना चाहिए।
7. जंगली क्षेत्र से बाहर साफ जमीन की ओर जाएं। बिजली गिरने और आंधी के कारण जंगल में आग लगने की संभावना होती है।

बिजली: प्राथमिक चिकित्सा उपचार

1. बिजली गिरने से पीड़ित को तुरंत चिकित्सा पेशेवर के पहुंचने से पहले प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें जिससे जान बचाई जा सकती है। बिजली गिरने से पीड़ित को छूना सुरक्षित है। बिजली गिरने से प्रभावित लोगों के पास कोई विद्युत चार्ज नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है।
2. पीड़ित की जाँच करें कि वह साँस ले रहा है और दिल की धड़कन चल रही है। नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे अच्छी जगह कैरोटिड धमनी है जो गर्दन पर सीधे जबड़े के नीचे पाई जाती है।
3. यदि पीड़ित साँस नहीं ले रहा है, तो तुरंत मुँह से मुँह में साँस देकर पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित की नाड़ी नहीं चल रही है, तो कार्डियक कंप्रेशन के साथ-साथ सीपीआर भी शुरू करें।

4. बिजली गिरने से बचे व्यक्ति की दृष्टि और श्रवण हानि और टूटी हुई हड्डियों की जाँच करें जो पक्षाघात या प्रमुख रक्तस्राव जटिलताओं का कारण बन सकती हैं।
5. पीड़ित और बचावकर्ता दोनों के लिए बिजली के निरंतर खतरे के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, यदि जिस क्षेत्र में पीड़ित स्थित है वह उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करें।
6. बिजली गिरने का शिकार व्यक्ति अलग-अलग डिग्री की जलन, सदमा और कभी-कभी कुंद आघात से पीड़ित हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो चोट की जाँच करें और व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाएँ।
7. हेल्पलाइन नंबर 112/1078 पर कॉल करें और सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए सही दिशा-निर्देश प्राप्त करें और पीड़ित की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएँ।

7.9 नागरिक सुरक्षा बल : (CIVIL DEFENCE)

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण (युद्ध) की स्थिति में हवाई हमला के दौरान जान व माल की सुरक्षा व नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किये जाने के उपरान्त आगरिक सुरक्षा अधिनियम में भी आंशिक संशोधन (नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009) करते हुए आपदा प्रबन्धन से जोड़ दिया गया है जिससे नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य “हवाई हमले के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवकृत” आपदाओं की स्थिति में नागरिकों के द्वारा – नागरिकों के लिए वो तमाम प्रयास करना है, जिससे उनके जान और माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही जिले में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न शिक्षण संस्थानों, होटलों, पब्लिक सेक्टरों इत्यादि में आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक सुरक्षा बल के द्वारा त्वरित कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है:—

- आपदा की सूचना मिलने पर संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तत्काल आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचेंगे व नियंत्रक (जिला कलक्टर) के निर्देशानुसार बचाव कार्यो को अन्जाम देंगे।
- आपदा के दौरान हताहतों के खोज व बचाव का कार्य करना।

- हताहतों को घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देना व अस्पताल भिजवाना। आश्रय स्थलों पर भोजन / पानी कपड़े इत्यादि हेतु स्वयंसेवक उपलब्ध कराना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।
- जिले में क्षमता संवर्द्धन के तहत आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण देकर लोगों को आपदा प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों को निभाना।

7.10 राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद (मोचन) बल (NDRF)

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा एवं सम्भावित मानव कृत आपदा एवं अन्य घटनाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल (State Disaster Response Force, SDRF) की 01 टुकड़ी मय उपकरणों के साथ नारोली किशनगढ़, जिला अजमेर में उपलब्ध है, जिसके कमाण्डर डिप्टी कमान्डेंट, श्री योगेश मीना मो. न. 6005204020 है, से सहायता ली जा सकती है।

बम विस्फोट/ आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थिति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान माल को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना है।

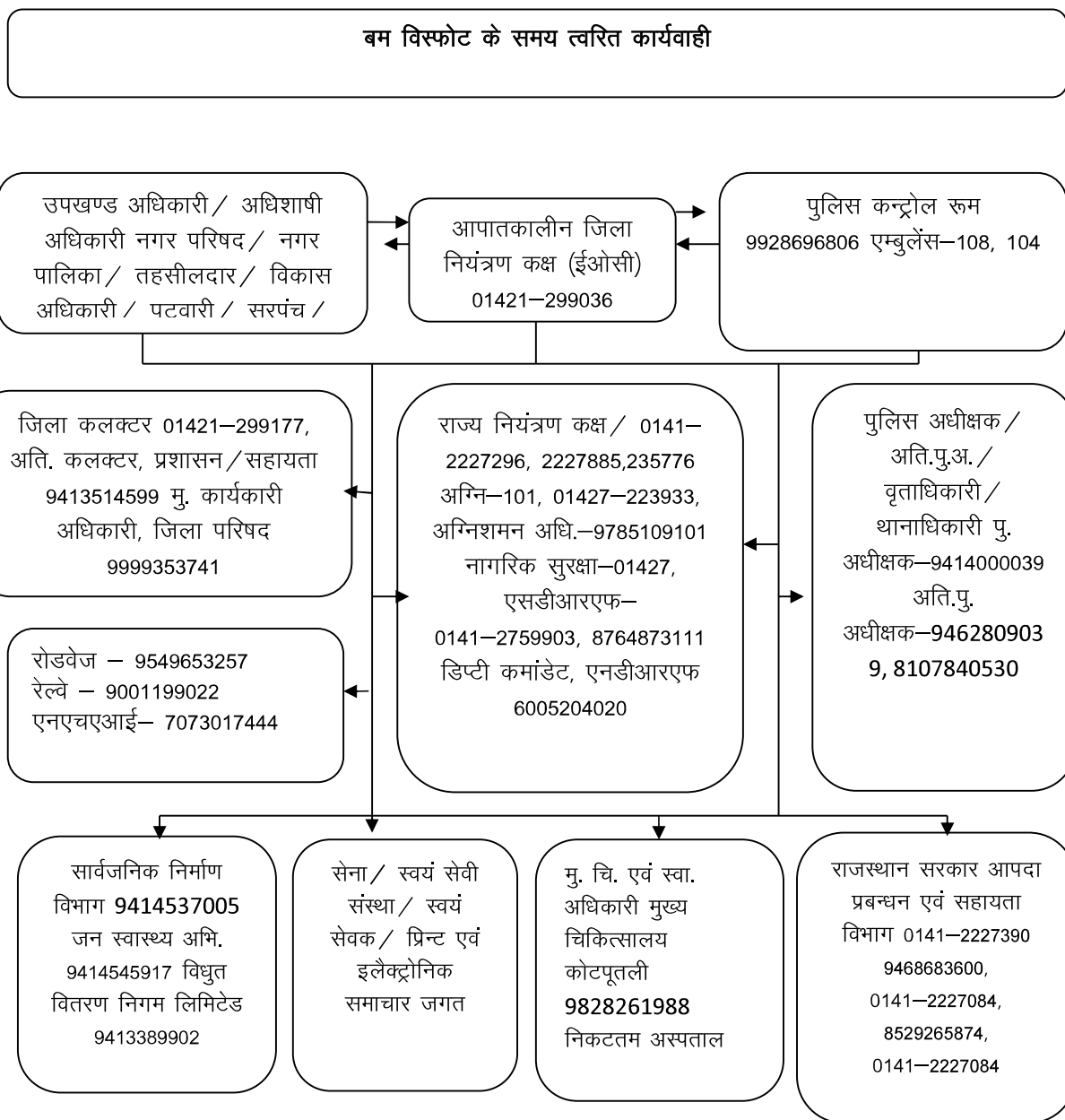
यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, स्कूल, सरकारी संस्थान एवं महत्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही :-

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरन्त बाद जिले में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती है जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती है तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती है।

2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
3. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस-पास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है। इसलिए अधिक सक्रियता बरतेंगे।
4. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देंगे।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगोंकी मदद से कार्यवाही करेंगे।
6. आतंकवादियों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेंगे।
7. खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देंगे।

8.



7.11 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात स्थिति में कार्य योजना :-

जिले में आपदा प्रबन्धन की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए तेज अर्धड तूफान, तीव्र गर्जन एवं बिजली गिरना, जलभराव/बाढ, दूषित जल एवं मच्छर, मक्खियों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे आन्त्रशोध, हेजा, पीलिया, टायफाइड, उल्टी-दस्त

एवं अनायास आपदा रोकथाम हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये समयबद्ध कार्य संपादन हेतु निम्न कार्य-योजना तैयार की गई है।

1. **कंट्रोल रूम व्यवस्था :-** जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें चिकित्सा दल 24 घण्टे तैनात रहेगा। जिसके दूरभाष नं. 9680412396 है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर आरआरटी गठित है। जो आपदा/अतिवृष्टि/जलभराव एवं बाढ़/ मौसमी बीमारियों की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर बीमारी से बचाव व उपचार की कार्यवाही करेगी।
2. **प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा :-** सामान्य तौर पर किसी भी आपदा के कारण कुछ ग्राम व ढाणियाँ सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बिल्कुल अलग-अलग हो जाती है एवं आसपास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर भी प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों में पृथक से मोबाईल चिकित्सा टीम को अस्थाई तौर पर लगायी जायेगी। मोबाईल चिकित्सा टीम को जीवन रक्षक दवाईयां, ब्लीचिंग पाउडर, ओआरएस पैकेट, एम.एल. ओ., टेमीफॉस, पायरेथ्रेम आदि उपलब्ध करवाया जावेगा।
3. **पेयजल शुद्धिकरण :-** अनायास विपदा के कारण सामान्य तौर पर सभी पेयजल स्रोतों का दूषित होना स्वाभाविक है, इसलिये पेयजल स्रोतों का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है, जहाँ-जहाँ पेयजल स्रोतों में पानी भरा है, उसे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नियमित शुद्धिकरण किया जावेगा।
4. **बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार:-** ऐसे ग्राम व ढाणियाँ जिनमें यकायक उल्टी -दस्त, पीलिया, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर आदि का प्रकोप/आपदा होने पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा। वहाँ संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीएचसी/सीएचसी के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही अपितु जिला स्तर से भी अविलम्ब चिकित्सा दल को भिजवाया जावेगा।
5. **सतर्कता:-** समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) कोटपूतली-बहरोड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड जिले में किसी भी प्रकार की अनायास विपदाओं बाबत पूर्णरूप से

सर्तक रहेंगे। इनका विशेष प्रयास रहेगा कि संबंधित विकास अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों से निरन्तर संपर्क बनाये रखें।

6. **सूचना एवं संचार व्यवस्था :-** साधारणतया विभिन्न विपदाओं के बाबत तत्काल सूचना दिये जाने के लिए अलग-अलग समय-समय पर पुरजोर दिशा निर्देश दिये जाते रहेंगे और जिसके लिए सम्पर्क सूत्र बनाये रखने के लिए सभी स्तरों पर दूरभाष सुविधायें उपलब्ध हैं, मगर फिर भी आवश्यकता पडने पर समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधिक्षक को आग्रह करते हुए वायरलैस सुविधाओं का उपयोग किया जावेगा किसी भी क्षेत्र में आपदा के प्रकोप होने पर तथा तत्काल नियन्त्रण कार्य किये जाने के बाबत समय-समय पर निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनसमुदाय को वास्तविकता से अवगत कराया जाना विभाग के हित में होगा।
7. **एन्टीलार्वा उपाय :-** अस्वच्छ एवं रूके पानी के भराव वाले स्थानों पर एन्टीलार्वा उपाय जैसे गंबूसिया मछली, एमएलओ, टेमीफोस का उपयोग किया जावेगा। साथ ही मलेरिया रोधी दवाओ की समुचित भण्डारण किया जाकर दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जावेगी।

चिकित्सा विभाग स्तर के अधिकारियों के नाम व मोबाईल नम्बर निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	मोबाईल न०	व्हाटसऐप न०
1.	DR. ASHISH SINGH SHEKHAWAT	CMHO KOT-BEHROR	CMHO OFFICE KOT-BEHROR	9828261988	9828261988
2.	DR. PRAMOD SINGH BHADORIYA	DY.CMHO (H)	CMHO OFFICE KOT-BEHROR	8619043649	8619043649
3.	DR.JAIBHAGWAN YADAV	DY.CMHO (FW)	CMHO FW OFFICE KOT-BEHROR	8094265634	8094265634
4.	DR. ARVIND AGARWAL	RCHO KOT-BEHROR	RCHO OFFICE KOT-BEHROR	9414924745	9414924745

5.	DR SURESH CHAND YADAV	PMO	DH BEHROR	9414200744	9414200744
6.	DR CHETAN RAWAT	PMO	DH KOTPUTLI	9414083793	9414083793
7.	DR. RAJESH KUMAR YADAV	PMO	SDH BANSUR	9269711092	9269711092
8.	DR. RAVI KUMAR BANSAL	PMO	SDH PAOTA	7737895567	7737895567

जिला स्तरीय आरआरटी टीम निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का एवं आर.आर.टी का नाम	चिकित्सा दल सदस्यों का नाम	पदनाम/पदस्थापन	सम्पर्क नम्बर
1.	जिला स्तरीय आर.आर.टी. कोटपूतली-बहरोड़	डॉ० प्रमोद सिंह भदौरिया	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०), सीएमएचओ कार्यालय कोटपूतली-बहरोड़	8619043649
		डॉ० दिलीप पंवार	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सरदार जनाना अस्पताल, कोटपूतली	8619181338
		श्री जितेन्द्र सिंह खरेरा	एलटी, राजकीय सरदार जनाना अस्पताल, कोटपूतली	8696138984
		श्री राजेश कुमार हरिजन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सीएमएचओ कार्यालय कोटपूतली-बहरोड़	9602107135
2.	जिला कंट्रोल रूम	श्री ख्याली राम यादव	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	9771009606
		श्री बनवारी लाल यादव	एमपीडब्ल्यू	9509955246
		श्री महेन्द्र शर्मा	एमपीडब्ल्यू	9785113774

जिले में चिकित्सा संस्थानों की स्थिति निम्नानुसार है जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है:—

- ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी :— 06
- जिला चिकित्सालय :— 02
- उपजिला चिकित्सालय :— 02
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :— 20

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :- 59
 - उपस्वास्थ्य केन्द्र :- 291
 - शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :- 01
 - जनता क्लिनिक :- 04
 - 108 एम्बुलेंस :- 17
 - 104 एम्बुलेंस :- 13
 - 108 बाइक एम्बुलेंस :- 02
 - एएलएस :- 03

पशुपालन विभाग कार्ययोजना

- आपदा की सूचना मिलने पर नियंत्रण अधिकारी सभी पशु चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- प्रभावित क्षेत्रों में घायल पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार करना
- घायल भर्ती पशुओं के चारे, दाने की व्यवस्था करना।
- आपदा स्थल पर पशु चिकित्सकों एवं पैरा वेटेनरी स्टाफ को आपदा से निपटने के लिए सम्पर्क करना।
- तहसील स्तर पर मोबाईल वेटेनरी यूनिटों को आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- मृत पशुओं के निस्तारण हेतु नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत की मदद लेना।
- स्वस्थ पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना।

7.12 जल संसाधन विभाग कार्ययोजना

बाढ़ के समय उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु कार्य योजना का प्रारूप :-

कोटपुतली बहरोड जिले में वर्षाकाल में जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ –

- कोटपुतली बहरोड जिले में जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में स्थित बांधों की सूची, लोकेशन एवं क्षमता अवलोकनार्थ संलग्न है। (Annexure -1)
- पंचायती राज विभाग से इस वर्ष हस्तान्तरित बांधों की सूची, बांधों के भराव क्षमता एवं अन्य विवरण (Annexure -2)

- अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण बाढ़ के डूब क्षेत्र एवं डाउन स्ट्रीम में आने वाले गांवों की सूची संलग्न है। (Annexure -3)
- जिले में आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर जन-धन के बचाव हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार सम्बन्धित कार्य जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाता है। विभाग के जिले में प्रगतिरत कार्य वर्तमान में सुरक्षित स्तर पर है तथा सभी बांधों पर चेतावनी बोर्ड लगवा दिये गये हैं एवं सम्बन्धित प्रभारी अभियंतों के नाम मय मोबाईल नम्बर की सूची संलग्न है। (Annexure -4)
- जिले में स्थित विभागीय बांधों/नहरों के गेटों की ऑयलिंग व ग्रीसिंग का कार्य मानसून पूर्व पूर्ण करा दिया जायेगा।
- जिले में स्थित बांध एवं फ्लड कंट्रोल रूम पर खाली कट्टे, ट्यूब, टायर, रस्सा, सुरक्षा सम्बन्धित उपकरण एवं अन्य सामग्री का विवरण की सूची संलग्न है। (Annexure -5)
- जिले में स्थित सभी विभागीय बांधों पर आवश्यकतानुसार 200 से 500 तक खाली सीमेंट के कट्टे मिट्टी से भरवाये जाकर मानसून पूर्व सुरक्षा हेतु रखवा दिये जायेंगे। उपखण्ड मुख्यालयों पर 5000 खाली सीमेंट के कट्टे भी मानसून सत्र में उपलब्ध रहते हैं।
- जिले में विभाग के प्रत्येक बांध पर नागरिकों की सुरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड लगवा दिये गये हैं।
- जिले में स्थित वर्षामापी स्टेशनों (रैनगैज स्टेशनों) की सूची संलग्न है। (Annexure -6)
- जिले में आवश्यकता पड़ने पर जेसीबी/एक्सेक्यूटर/ट्रेक्टर/श्रमिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराने का कार्य प्रगतिरत है।

ANNEXURE-1

जल संसाधन खण्ड जयपुर (जिला –कोटपुतली बहरोड) के अधीन
बांधों की सूची :-

क्र. सं.	नाम बांध	तहसील	कुल गेज (मीटर. में)	कुल क्षमता (एम.क्यू.एम. में)
1.	छितौली	विराटनगर	6.86	24.301
2.	धुलकोट	विराटनगर	3.45	1.019
3.	बुचारा	कोटपुतली	10.44	16.367
4.	बनेडी	कोटपुतली	5.13	4.984
5.	पंचपहाडी	पावटा	3.04	1.28

ANNEXURE-3

पंचायतीराज विभाग से इस वर्ष हस्तांतरित बांधों का विवरण

Ø-la-	cka/kks dk uke	rglhy	xst ¼ehVj½	iw.kZ Hkjko {kerk ¼Mcum½	flafpr {ks= ¼lhlh,&gSDVs;j esa½
1.	रामपुरा	विराटनगर	3.65	0.3126	259.10
2.	सिक्कावाली	विराटनगर	-	-	170.70
3.	भाभरू/ बहडोदा	विराटनगर	4.2672	2.516	89.47
4.	बैराठ	विराटनगर	4.572	1.1326	20
5.	पण्डो	विराटनगर	4.267	0.3347	110.10
6.	जग्गा जी	विराटनगर	1.828	0.233	17
7.	टंकू	विराटनगर	2.134	0.656	120
8.	बागावास	विराटनगर	3.352	0.1699	132
9.	नीमली	विराटनगर	3.9624	0.3012	-
10.	बैरी	पावटा	7.31	0.897	-
11.	पांचूडोला	पावटा	5.48	0.6592	58.70
12.	दांतिल का नाका	पावटा	3.44	0.8495	49

ANNEXURE-3

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर
बांधों के टूटने पर बाढ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

क्र. स.	बांध का नाम	तहसील	श्रेणी	गेज (मीटर में)	भराव क्षमता (एम. क्यू.एम में)	सी.सी. ए. (हैक्टर)	बांध के टूटने पर बाढ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची	Over Flow की स्थिति में प्रभावित होने वाले गांवों की सूची	विशेष विवरण
1	बुचारा बांध	कोटपूतली	मध्यम	10.44	16.367	2640	रामपुरा, भूरी बडाज, सुजात नगर, प्रागपुरा, कांसली, नारहेडा, पनिहाला, केसवानाराजपूत कोटपूतली के बाहरी क्षेत्र कुंजोता, पावटा, भैंसलाना	फैक्ट्री एरिया केसवाना राजपूत	विगत 24 वर्षों में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।

2	बनेडी	कोटपूतली	लघु	5.13	4.984	1344	रामपुरा, बुढी बडाज, सुजान नगर, प्रयागपुरा, नारेडा, पनीहाला, केसवाना राजपूत कोटपूतली के बाहरी हिस्सा, कुजोता, पावटा, भैसलाना, बाकली, आसपुर	फैक्ट्री केसवाना राजपूत	एरिया	विगत 24 वर्षों में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
3	छितौली	विराटनगर	लघु	6.86	24.301	1660	छितौली सूरजमल की ढाणी, किशनपुरा, जोधपुरा, कौटपूतली धूलकोट	सुरज मल की ढाणी		विगत 24वर्षों में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
4	धुलकोट	विराटनगर	लघु	3.45	1.019	197	सुरजमल की ढाणी, धूलकोट किशनपुरा, जोधपुरा, कोटपूतली	धूलकोट, किशनपुरा		विगत 24 वर्षों में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।
5.	पंचपहाडी	पावटा	लघु	3.04	1.28	208.38	हापोडा, कारोली, बडा गांव	हापोडा, कारोली, बडा गांव		विगत 15 वर्षों में बांध 0 बार पूर्ण भरा है।

ANNEXURE-3

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन ,जयपुर

मानसून 2025

**श्री अनिल थालोर
अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन खण्ड जयपुर
मुख्यालय जयपुर**

फोन नं. 2203696 (मोबाईल नं. 9910980129)

श्री शैलेन्द्र गढवाल सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, शाहपुरा 9967309819	श्रीमति कुसुम चौधरी क0अभि0 अनु0 पावटा / कोटपुतली 9461500964	श्री बद्रीनारायण चोपड़ा क0अभि0 अनु0 विराटनगर 8824950445
--	---	--

ANNEXURE-4 (i)

खण्डीय भण्डार (जयपुर) में सामान की सूची जो उपलब्ध रहेगी।

क्र.सं.	सामान का नाम	मात्रा
1	खाली सीमेन्ट के कट्टे	5000
2	लाईफ जैकेट	10
3	रेनकोट	05
4	टार्च 3 सेल	05
5	पावडा	20
6	गेती	20
7	पेट्रोलैक्स	03
8	तगारी प्लास्टिक	20
9	मूंज नारियल	50 किलों ग्राम
10	मोटा रस्सा	150 फुट

11	ट्यूब	10
----	-------	----

ANNEXURE-4(ii)

जल संसाधन उपखण्ड शाहपुरा में उपलब्ध सामग्री का विवरण

जल संसाधन उपखण्ड शाहपुरा

अनुभाग शाहपुरा/विराट नगर/कोटपूतली

1	गैती	10
2	बल्ली	10
3	मूंजवान	25 किलो ग्राम
4	खाली कट्टे	5000
5	फावडे	10
6	तगारी	10

ANNEXURE-5

कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित रैनगैज स्टेशनों की सूची

जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित – 2

क्र. सं.	रैनगैज स्टेशन	तहसील	जिला	अक्षांतर	देशांतर
----------	---------------	-------	------	----------	---------

1	टसकोला	पावटा	कोटपुतली बहरोड	27°35'34.37"	76°01'27.11"
2	चैचाला	विराटनगर	कोटपुतली बहरोड	27°19'6.0"	76°03'36"

राजस्व विभाग द्वारा संचालित – 3

क्र. सं.	रैनगैज स्टेशन	तहसील	जिला	अक्षांतर	देशांतर
1.	बैराठ (विराट नगर)	विराटनगर	कोटपुतली बहरोड	27°25'53.3"	76°09'48.8"
2	पावटा	पावटा	कोटपुतली बहरोड	27°35'11.61"	76°04'11.39"
3	कोटपुतली	कोटपुतली	कोटपुतली बहरोड	27°42'11"	76°12'0.18"

(2) सिंचाई विभाग के कार्यों के रख रखाव एवं निगरानी के संबंध में :

वर्षा के आरम्भ की तिथि 15 जून मानकर जल संसाधन विभाग के सभी बांधों की आवश्यक मरम्मत की जाती है तथा सभी गेटों की आइलिंग-ग्रीसिंग व गेज पेन्टिंग कर दी गई है, इसके अतिरिक्त सभी बांध पर निगरानी रखने हेतु अस्थाई चौकीदार लगाये जाते हैं। अधिकांश बांध अत्यधिक पुराने हैं व रख-रखाव मद में उचित बजट आवंटन होने की स्थिति में बांधों की मरम्मत हेतु अति आवश्यक कार्य सम्पादित कराये गये हैं व सामान्य परिस्थितियों में बांध सुरक्षित हैं। सभी बांध में मिट्टी कच्ची होने के कारण वर्षाकाल में इनकी निरन्तर देखरेख व निगरानी की आवश्यकता होती है। विभागीय श्रमिक उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ श्रमिकों की आपूर्ति निविदा के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर की जावेगी, किन्तु बांधों की निरन्तर निगरानी हेतु श्रमिक अपर्याप्त हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना

तुरन्त नजदीकी फ्लड कन्ट्रोल रूम को दे दी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन द्वारा सहयोग लिया जावेगा।

वर्षा काल में संभावित समस्याएँ व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. शहरी क्षेत्रों में अनेक बार जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है अथवा जल निकासी हेतु निर्मित नाले आदि उचित सफाई नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों में जल भराव होता है।
अनेक बार संग्रहित जल किसी नये रास्ते से बहने लगता है, जिससे जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/नगर पालिका/नगर विकास न्यास आदि अपने स्तर पर भी पृथक् से फ्लड कन्टीजैन्सी प्लान तैयार करें व वर्षाकाल में जल निकासी हेतु मार्ग को पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेवे।
2. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के अधीन बांधों की भी उचित देख रेख व स्लुस गेटो की ऑईलिंग, ग्रीसिंग वर्षाकाल से पूर्व सुनिश्चित कर ले व वर्षाकाल में बांधों की सघन निगरानी सुनिश्चित की जावे। बांधों में पानी की आवश्यकता को जिला परिषद के स्तर पर दैनिक सूचना प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
3. मिट्टी के कच्चे बांधों में पाईपिंग अति महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका अविलम्ब पता लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि पाईपिंग बन्द करने हेतु मरम्मत कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जा सकें एवं किसी ब्रीच की स्थिति को उत्पन्न होने पर रोका जा सके। इस बाबत स्थानीय ग्रामवासियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, चूंकि यदि पाईपिंग को समय रहते दृष्टिगत कर लिया जावे व इसका उपचार किया जावे तो किसी सम्भावित हानि से बचा जा सकता है। इस विभाग के सभी तकनीकी अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में स्थित जल संसाधन विभाग के बांधों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
4. वर्षाकाल में अनेक बार छोटे क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां पानी की निकासी हेतु मार्ग नहीं होता है ऐसी स्थिति में जल निकासी हेतु मोटर पम्प लगाया जाना ही एक मात्र विकल्प है इस बाबत पम्पों की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस संबंध में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा न्यूनतम दो पम्प मय सैक्शन पाईप व डिलिवरी के चिन्हित किये जाने उचित होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ट्रेक्टर ट्रोलियों का भी चिन्हिकरण किया जाना उचित होगा जिन्हे बाढ़ की स्थिति में प्रयोग में लिया जा सके।
5. निरीक्षण वाहन की आवश्यकता:— वर्तमान में इस विभाग के अधीन कोई राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है। अतिवृष्टि व बाढ़ की स्थिति में मोबीलिटी अतिमहत्वपूर्ण होती है व

तत्परता मे की गई कार्यवाही से जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है। अतः जिला पूल से वर्षाकाल में 2 जीप इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है

कोटपूतली-बहरोड जिले के जन प्रतिनिधिगण

सांसद/विधायकगण जिला कोटपूतली-बहरोड			
पदनाम	नाम जनप्रतिनिधि	कार्यालय	निवास
सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण
विधायक, कोटपूतली	श्री हंसराज पटेल	कोटपूतली	कोटपूतली
विधायक, बानसुर	श्री देवी सिंह शेखावत	बानसुर	बानसुर
विधायक, विराटनगर	श्री कुलदीप धनखड़	विराटनगर	विराटनगर
विधायक, बहरोड	श्री जसवंत यादव	बहरोड	बहरोड

सांसद सदस्य

सांसद, जयपुर ग्रामीण	श्री राव राजेन्द्र सिंह	जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण
----------------------	-------------------------	---------------	---------------

पंचायत समिति प्रधान

बानसूर	श्रीमती सुमन देवी	9214565620	
बहरोड	श्रीमती सरोज देवी	9414014700	
नीमराना	श्रीमती संतोष देवी	992964242	
कोटपूतली	श्रीमती नेहा	9001688844	
पावटा	श्रीमती मीरा कुमारी सैनी	7791800011	
विराटनगर	श्रीमती बूंदी देवी	9929615378	

7.13 बोरवेल की दुर्घटना

भारत में पीने के पानी के संसाधनों की समस्या के लिये आये दिन विभिन्न आवासीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदे जाते हैं। बोरवेल के निर्माण के समय या बोरवेल में पानी नहीं मिलने पर खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेते हुये राहत कार्य चलाये गये। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस दुर्घटना से बचाव हेतु निम्न कार्य योजना तैयार की गई है।

दुर्घटना से बचाव हेतु :-

- जन जागरूकता हेतु प्रचार- प्रसार जिसमें यह संदेश हो कि बोरवेल खुदाई कर्ता ठेकेदार किसी भी स्थिति में बोरवेल को खुला नहीं रखे। बोरवेल खुदाई के समय ढकने हेतु पत्थर एवं लोहे का पर्याप्त आकार का ढक्कन लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। लोग बोरवेल खुदाई के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन को बोरवेल खुदाई स्थल, खुदाई कर्ता ठेकेदार के नाम व पता मय ठेकेदार के सुरक्षा की पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं के सम्बन्ध में सूचित करना।
- हर जिले में उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अनुसूची के अनुसार दुर्घटना होने पर पूर्व तैयारी व जानकारी रखें।
- बोरवेल में बच्चे गिरने की दुर्घटना होने पर बचाव कार्य हेतु निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जा सकती है :-
 1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
 2. सम्बन्धित पंचायत समिति के उपखण्ड विकास अधिकारी
 3. सम्बन्धित मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
 4. सम्बन्धित उप अधीक्षक पुलिस।
 5. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
 6. जलदाय विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता डिलिंग।
 7. भू- जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के भू- गर्भ शास्त्री।

8. भू- जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता।
9. बिजली विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
10. भू- सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, से सम्बन्धित क्षेत्र का विशेषज्ञ अधिकारी।
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशाषी /सहायक अभियंता।
12. उप- नियंत्रक नागरिक सुरक्षा।

दुर्घटना होने पर :-

- सर्वप्रथम जिला कलेक्टर कंट्रोल रूम तथा उपखण्ड कंट्रोल रूम में सूचना।
- सम्बन्धित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को मौके पर मय जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपकरण व दवाईयां, एम्बुलेन्स तथा मेडिकल टीम सहित पहुंचने की सूचना।
- उपरोक्त टीम को मौके पर पहुंच कर तत्काल उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार बोरवेल में क्लोज सर्किट केमरा या इन्फ्रारेड कैमरा व ऑडियो विजुअल मॉनेटरिंग सिस्टम तथा स्वास्थ्य रक्षक उपकरण स्थापित करना।
- उपरोक्त टीम द्वारा दुर्घटना घटित होने के एक घंटे में बचाव कार्य हेतु संयुक्त रूप से मौके पर स्थिति अनुसार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर समानान्तर बोरवेल खुदाई या अन्य प्रकार से अनुसूची के अनुसार शेष संसाधनों को एकत्रित करने तथा बचाव कार्य करने की कार्य योजना तैयार करना।
- उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करना।
- मौके पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा राहत टीम के लिये रहने व भोजन की व्यवस्था।
- प्रति घंटे अति० जिला कलक्टर राहत को राहत कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना।

अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग से सहायता मांगी जायेगी। उपरोक्त प्रकार की दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु वांछित उपकरणों एवं संसाधनों पर व्यय की राशि का आंकलन किया जाकर राज्य सरकार को सूचित किये जाने की तैयारी की जा रही है।

खुले बोरवेलों से होने वाले हादसों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिशा निर्देश।

राज्य में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने की कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं एवं इन दुर्घटनाओं में कई मासूमों को जान गंवानी पड़ी तथा राज्य सरकार को भी अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ा है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। दिनांक 9.2.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोरवेल में बच्चों के फंस कर मरने की अत्यधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में

बोरवेल ड्रिल करने के पश्चात उसे सूना छोड़े जाने पर बोरवेल ड्रिल करने वाली कम्पनी/ मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 36/ 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.2.2010 द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार भूजल विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12(6) जीडब्लूडी/09 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये तथा इन निर्देशों की समयबद्ध पालना रिपोर्ट निरन्तर मंगवाई जा रही है।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, खुले बोरवेलों को आवश्यकता नहीं होने पर तुरन्त पाटने (बन्द करवाने) एवं हादसा होने पर बोरवेल करने वाली कम्पनी / मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, इस संबंध में होने वाले समस्त व्यय की वसूली की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर होने वाले अनावश्यक व्यय एवं जानमाल की क्षति से बचा जा सके। इस हेतु जिला कलक्टर के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ठोस कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबंद किया गया है।

7.14 सार्वजनिक निर्माण विभाग आपात स्थिति में कार्य योजना

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे व आवश्यक तकनीकी सलाह देंगे।
- घटना स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों (भारी मशीनरी) की सूचियां रखना व आवश्यकतानुसार उनकी सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु ढंग से हो सके।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना।
- घटना स्थल पर बचाव दलों के कार्यों के दौरान आवश्यकतानुसार क्षति ग्रस्त ढांचों को ढहाना व सहारा देना।
- क्षति ग्रस्त भवनों में बचाव दलों को भवन संबंधी आवश्यक सलाह देना।
- मानसून पूर्व सरकारी भवनों (विशेषतया स्कूलों/कॉलेजों) को आवश्यक देखभाल करना व क्षतिग्रस्त होने की हालात में उसे अनुपयोगी करार देते हुए गिराने की कार्यवाही करना आदि कार्य हेतु दक्ष तथा प्रशिक्षित इंजिनियर उपलब्ध किये जा सकते हैं।
- घटना स्थल से मलबा हटाने आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना या वैकल्पिक मार्ग तैयार करना ताकि राहत कार्य सुचारु ढंग से हो सके इस हेतु विभाग के अधीन संवेदकों या अन्य से संपर्क कर मशीनरी व अन्य साधन (क्रेन/जेसीबी) आदि की व्यवस्था की जाती है।

- साथ ही अस्थायी राहत कैम्प का निर्माण किया जाता है।
- अतिवृष्टि की संभावना के समय सैंड बैग की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहती है।

7.15 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपात स्थिति में कार्ययोजना

1. वृत्त कार्यालयों के अधीन खण्डीय कार्यालयों एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है। उपखण्ड/तहसील में कार्यरत फिल्ड अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित है।
2. बाढ़, तूफान, भूकम्प व अन्य दुर्घटनाओं में पानी की स्थिति में पानी की पाईप लाईन बन्द होने एवं अन्य किसी कारणवश पेयजल सप्लाई में बाधा होने पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सभी सहायक अभियन्ता मुख्यालय एवं कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों पर पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेशन हेतु उपलब्ध है। जहां नियमित रूप से जल स्रोत के पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है।
3. पानी की पाईप लाईनों की देख भाल विभाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जाती है तथा किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त होने पर सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचना दी जाती है। जिसे तत्परता से मरम्मत की जाती है। मरम्मत हेतु विभाग में सभी आवश्यक सामान कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालयों पर उपलब्ध होता है।
4. विभाग के समस्त उच्च जलाशयों/स्वच्छ जलाशयों पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। जीर्ण शीर्ण उच्च जलाशयों की मरम्मत की जाती है अथवा उनको गिराने की व्यवस्था की जाती है। नये बनने वाले उच्च जलाशयों पर सीढ़ियों पर गेट बनवाने का प्रावधान लिया जा रहा है।
5. सभी उच्च जलाशयों / पम्प हाउसों पर 24 घन्टे हाईड्रेट से पानी लेने की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
6. गर्मियों में पानी की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करना। टैंकरों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करना।

7. अग्निशमन व्यवस्था के तहत वाटर हाईड्रेंटों को चिन्हित करना व उनको चालू हालात में रखना। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी देना।
8. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को तत्काल ठीक करवाना।

7.16 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्ययोजना

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता तत्काल आपदा स्थल पर पहुंचे।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजलीकी सप्लाई आपदा स्थल तक पहुंचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।
- खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चालू रखने हेतु उपयुक्त मात्रा में आवश्यक सामग्री जैसे पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था रखी जाना।
- जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों को डी.पी. पर रखा जाना।
- ढीले तारों को कसा जाना।
- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

7.17 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
- घायलों को चिकित्सा शिविरों तक पहुंचाना।
- सहायता सामग्री को राहत शिविरों तक पहुंचाना।

7.18 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व कैरोसीन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

7.19 सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

पदाधिकारी	चिकित्सा समिति (मौसमी बीमारियां एवं राहत कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था हेतु पृथक्-पृथक् समितियां हैं, किन्तु सदस्यगण समान हैं)	राहत कार्य व नियोजन समिति	चारा व्यवस्था समिति	गेंडु के सुरक्षित भण्डारण एवं समुचित आवन्तन समिति (तहसील स्तर पर)
अध्यक्ष	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटपूतली-बहरोड	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)	उपखण्ड अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अति. मुख्य कार्य अधिकारी, जिला परिषद	उप निदेशक, कृषि (विस्तार)	विकास अधिकारी
सदस्य	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी	अधि. अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	मण्डल वन अधिकारी	बाल विकास अधिकारी
सदस्य	उपखण्ड अधिकारीगण समस्त जिला	विकास अधिकारीगण	उप निदेशक, पशुपालन विभाग	रसद कार्यालय का खाद्य निरीक्षक
सदस्य	—	परियोजना अधिकारी, भू.सं. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	उपखण्ड अधिकारीगण	—

दीर्घकालीन उपाय

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण।
4. अवकमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
11. स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपों स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि का विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।

- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

स्थानीय एवं जिला प्रशासन की भूमिका

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण।
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएँ, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपों स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।

- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना ।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना ।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना ।

7.20 दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उप जिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम, सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना में 1,40,000 मौतें प्रतिवर्ष होती है, प्रतिदिन 400 मौतें एवं प्रतिघन्टा 18 मौत दर्ज की गई है। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना से करीब 10,000 मौतें हो रही है। अधिकतर दुर्घटना से मौतें लापरवाही एवं सुरक्षा कानूनों की अनदेखी करने से हुई है। यदि इस दिशा में सार्थक प्रयास न किया गया तो गम्भीर परिणाम समाज को भुगतना होगा।

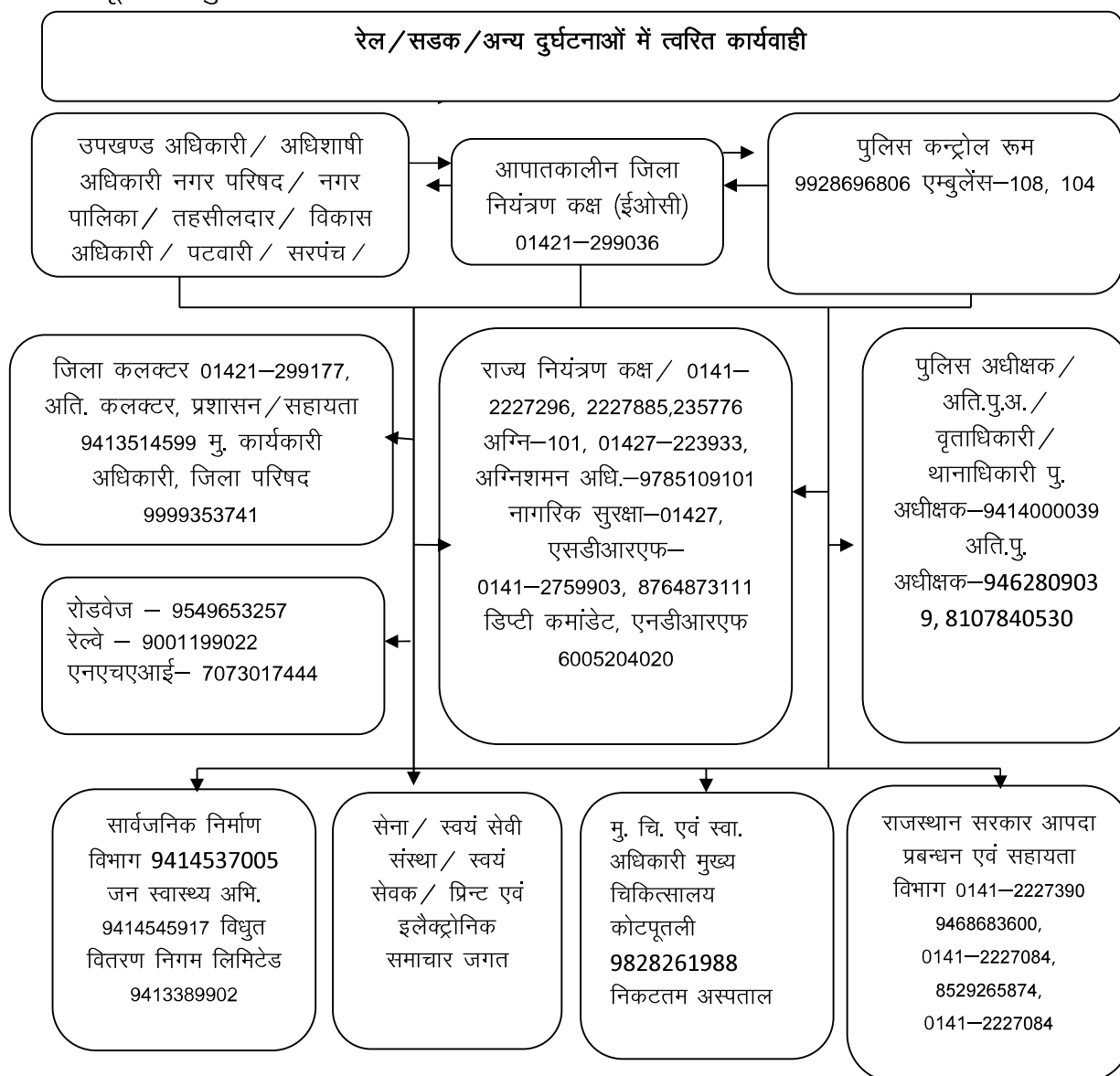
संरचनात्मक उपाय — दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय — सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाडी न चलाए।
- शराब पीकर गाडी न चलाए।

- हेलमेट पहने, कार में आगे और पीछे बैठे सवारी को सीट बेल्ट बांधना आवश्यक है।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।
- दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्तव्य
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- हानि का आंकलन करना।
- चिकित्सा विभाग
- तहसील में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची संलग्न है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।
- पुलिस विभाग
- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।

- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना। संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।



7.21 भूकम्प एवं कार्य योजना

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प की दृष्टि से सिसमिक जॉन ॥ में आता है, जिससे गंभीर खतरे की संभावना कम है, फिर भी बिगड़ते हुए प्रदूषण के कारण भूकम्प की संभावना बढ़ती जा रही है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचाती है,

जिसकी पुनःपूर्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :-

स्थानीय एवं जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गार्ड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फसें लोगो को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार सभाल करना।
- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

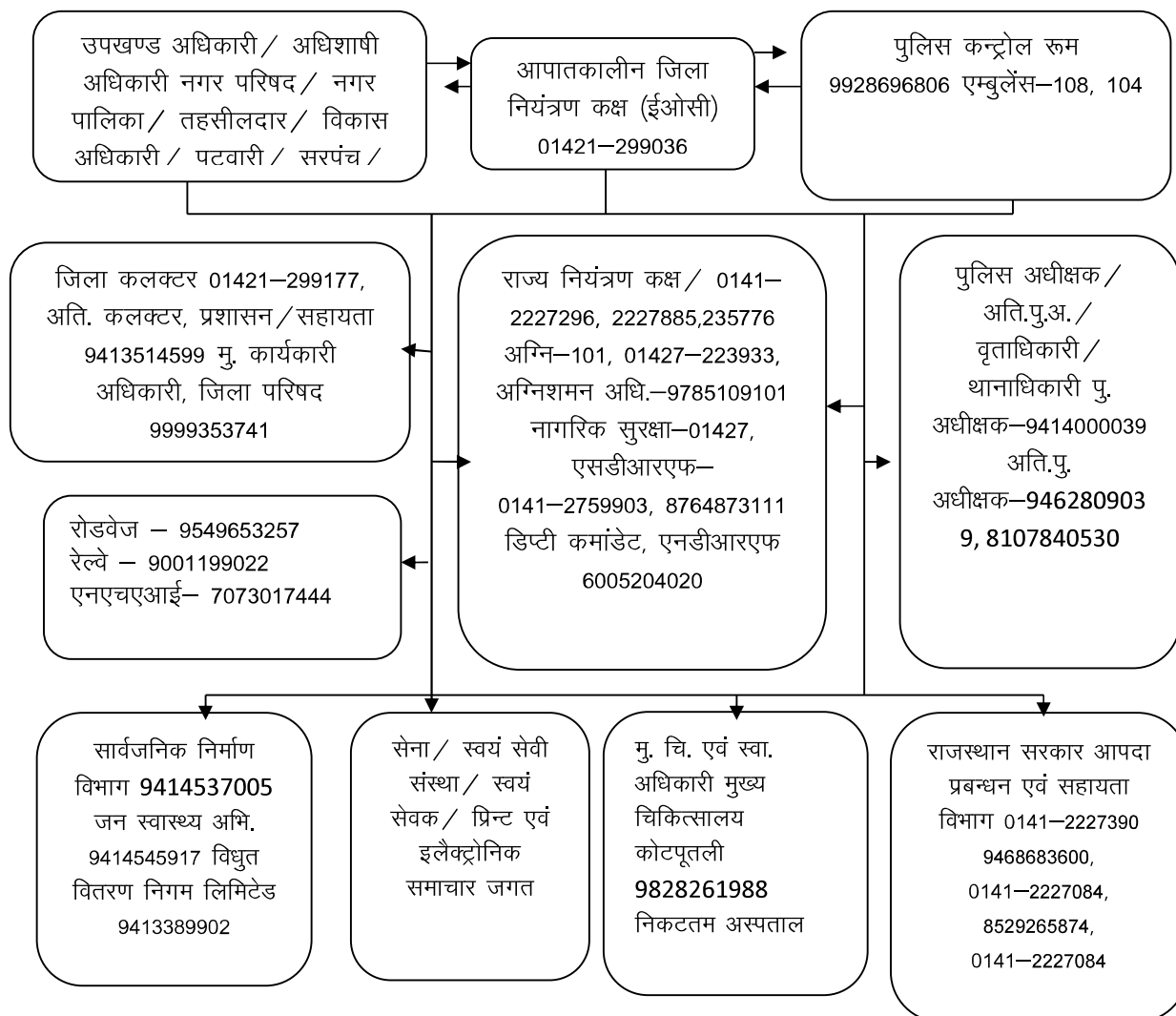
सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य पकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
 - लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
 - बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
 - चिकित्सकों पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

भूकम्प में बचाव एवं त्वरित कार्यवाही



7.22 ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन, एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है।

ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार को तत्काल निर्देशन करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही संभव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं।

7.23 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उधोगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जात है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी का फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारु हो जाते हैं। इसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांध के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि :-

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अति जल निकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: चेन, रस्सा, चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।

- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

7.24 खदान दुर्घटना आपातकालीन कार्ययोजना :

जिले एवं आस-पास के जिलों में विविध प्रकार के खनिज के खदान है। जिनमें मृत्तिका,, पत्थर, रेत मुख्य है। इन खनिजों की खुदाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनरीज, मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन के नीचे की खुदाई में कई दुर्घटनाओं की सूचना प्रतिदिन आती रहती है एवं प्रशासन के सतत प्रयास से लोगों को बचाया जाता है। फिर भी खान दुर्घटन से प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत एक आपातकालीन प्रशासनिक संसाधन का एसओपी विकसित किया है। जिससे खान दुर्घटना एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

7.25 ताप (लू) एवं शीतघात तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु एवं बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 42° से0 और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 29° से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मईकी अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। जिसके कारण तापघात से मृत्यु दर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। किसी-किसी दिन अधिकतम तापमान 45° या 47° तक पहुंच जाता है। घटती हरियाली, बिगड़ते पर्यावरण एवं अवैध जंगलों की कटाई तापमान बढ़ोतरी के मुख्य लक्षण है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना

- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- नमक चीनी का घोल पानी के साथ पीना लाभप्रद है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनावें कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहां अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0° सें. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8° से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिक को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आ कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएं।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।

- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफीन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुंह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर का इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाईल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

अध्याय— 8

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

दृष्टिकोण— आपदाएं समय-समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ-साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक एवं कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विशम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परन्तु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

1. क्षमता निर्माण हेतु योजना—

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

— प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु-आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

— राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।

— अपनी कुशलता सिद्ध कर चुके ज्ञान-आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

— अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

— पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

— राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्यवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण— जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों, अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण— समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर-सरकारी संगठनों/रेड क्रॉस एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

1. नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को निदेशालय नागरिक सुरक्षा जयपुर द्वारा समय-समय पर आपदा की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2. आपदा प्रबंधन की शिक्षा
 1. स्कूलों- जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन-जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
 2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
 3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचय:— आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण हैं और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। ऐसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकड़े जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रूप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते हैं और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

9.1 लघु अवधि योजना—

अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती हैं और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षेत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी—

1. राहत के रूप में जुटाए जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीव्रता के आकड़ों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता है।
2. कुछ क्षेत्र आपदा से ग्रस्त हैं और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा, में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबंधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

आपदा के बाद:-

9.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव, निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायु सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए। सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उद्योग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगा। परंपरागत रूप से, चिन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेंसियों, जो बड़ी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे हैं। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर, दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढ़ाने और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा।

9.1.3 राहत अभियान

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीड़ितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प ,आग, बाढ, दंगे, आतंकवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

9.1.4 पुनर्वास

अल्पावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के शेष कार्यों को ले जायेगा।

9.2 दीर्घकालिक योजना

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नहीं है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।

2. पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है, के स्तर का फैसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आंकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।

3. एक समुदाय, जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते हैं विस्तृत सर्वेक्षण, बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

4. दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोश जनक आश्रय, आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्देश्य नहीं है और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।
5. लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है। उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए जरूरत है, एक ही भूमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।
6. लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

रासायनिक एवं औद्योगिक आपात स्थिति कार्ययोजना

10.1 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे— भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं। अपर्याप्त संसाधन, अप्रशिक्षित कार्यदल, ठोस कानून का अभाव एवं अग्नि एवं सुरक्षा ऑडिट की पालना न होना बढ़ती आबादी के साथ एक बड़े संभावित आपदा को चिन्हित कर रहा है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्वक मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का हाना भी आवश्यक है।

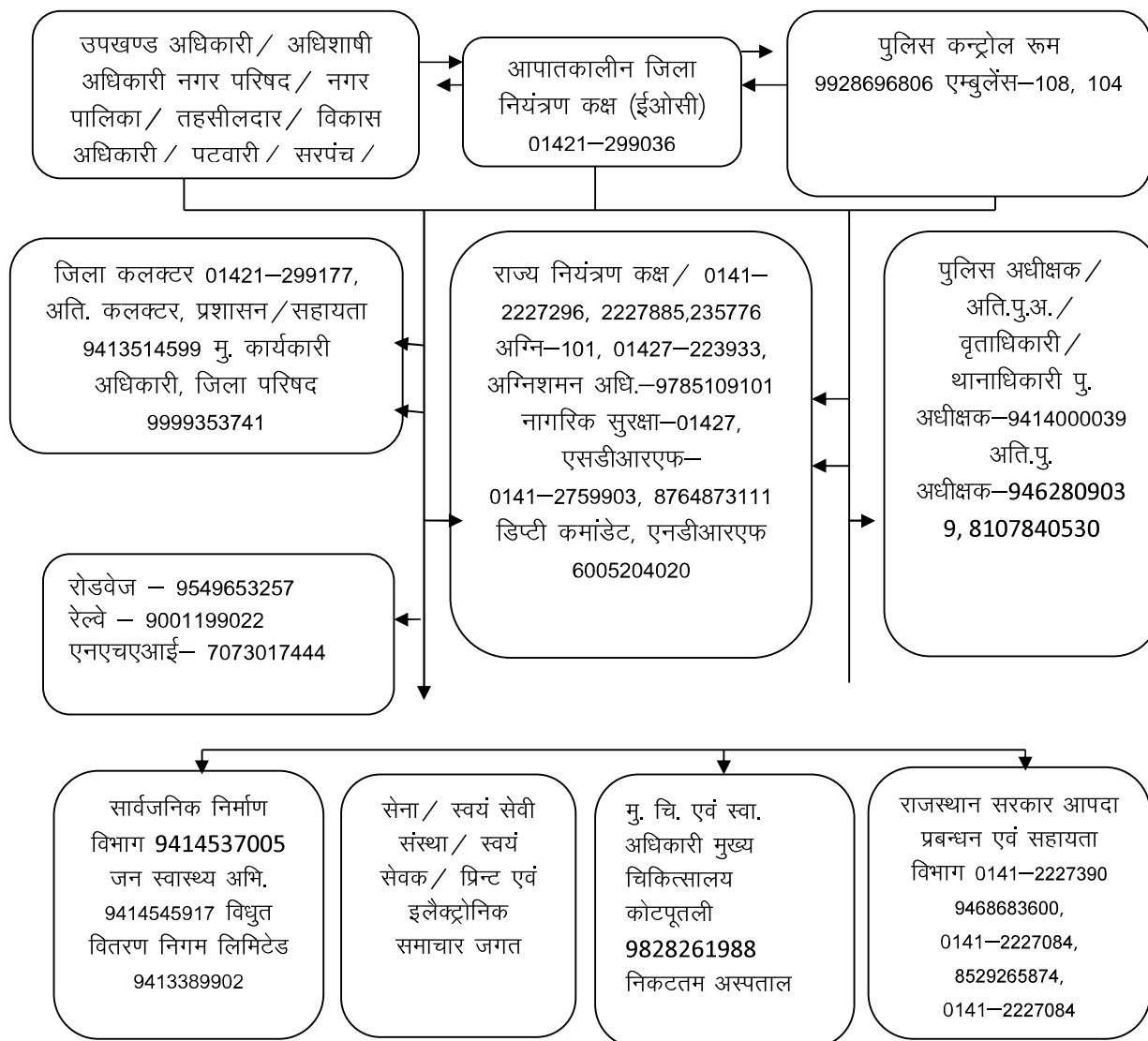
प्रभाव :—

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं:—

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/ गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही



बायोलॉजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

महामारी एवं रोगों का फैलना बायोलॉजिकल आपदा की श्रेणी में आता है। पेड़ पौधे, पशुओं का सड़ना, जल का प्रदूषित होना, विषाक्त कीटाणुओं का फैलाव होना आदि से जीवन पर बुरा प्रभाव होता है। महामारी से बड़े क्षेत्र में जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिक से अधिक मौतें होती हैं, जैसे कॉलरा, प्लेग, जापानी इन्फ्लुएंजा, एक्वूट एनसेफलायटिस सिंड्रोम इत्यादि। कुछ ऐसी भी महामारी हैं, जिसके कीटाणु विश्व एवं देश के सभी कोने में फैल कर अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं साथ अधिक संख्या में मौतें हो जाती हैं, जैसे एन्फ्लुएंजा एन1एन1, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि।

अध्याय: 12

न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति कार्ययोजना

12.1 आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही

1. किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर या रेडियोलोजिकल आपात स्थिति होने पर या आशंका होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार जो नोडल एजेंसी का कार्य करता है, से सहायता के लिए सम्पर्क किया जाता है।
2. परमाणु ऊर्जा विभाग में एक काईसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। आपात स्थिति में जिला कलेक्टर या अन्य अधिकृत अधिकारी मैनेजमेंट ग्रुप को सूचित करेगा। यह ग्रुप मुम्बई में स्थित है जहां 24x7 घण्टे नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहता है।
3. काईसिस मैनेजमेंट ग्रुप केवल परिस्थिति पर नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया ;त्मेचवदकद्ध करने के लिए अपना विशेषज्ञ सलाह एवं सहायता देगा। यह विभाग त्मेचवदकमत के रूप में कार्य नहीं करेगा।
4. इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश के अलग-अलग जगहों पर ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्बद्ध स्थापित किये हुए हैं।
5. इसी क्रम में एक ईमरजेंसी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्बद्ध जयपुर में परमाणु खनिज निदेशालय प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बनाया गया है।
6. आवश्यकता पडने पर काईसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सूचना देने के साथ-साथ स्थानीय ईमरजेन्सी रिस्पोन्स सेन्टर ;म्बद्ध से सहायता ली जा सकती है।
7. म्ब के विशेषज्ञ टीम को काईसिस स्थल पर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
8. छक्ड। ने देश के कुछ चुनिंदा पुलिस स्टेशन को न्यूक्लियर एवं रेडियोलोजिकल आपात स्थिति के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही रेडियेशन मॉनिटर मुहैया कराया जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त छक्ड। की बटालियन को केमिकल, बायोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाती है तो प्रभावित लोगों के बीच आयोडिन बांटना आवश्यक है।

अध्याय : 13

साम्प्रदायिक तनाव एवं भगदड़

13.1 साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मों के लाग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं सामाजिक विद्वेषों तथा व्यक्तिगत छोटे छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होना तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। उपद्रव होने पर जन-धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है।

वर्तमान में इस दृष्टिकोण से सभी साम्प्रदायों में आपसी सौहार्द है तथा सभी साम्प्रदायों के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहारों में बढचढ कर सम्मिलित होते हैं।

फिर भी यदि साम्प्रदायिक तनाव व दंगे हो जाये तो उन्हें कम करने हेतु जिला एवं स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते हैं। जिनमें वह सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते हैं।

13.2 भगदड़ एवं कार्ययोजना

बढती आबादी एवं असुरक्षा का नतीजा है भगदड़ 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन पटना के गांधी मैदान में भगदड़ के कारण 33 लोग मारे गये, इससे पहले अगस्त 2014 के अन्तिम सप्ताह में मध्यप्रदेश के कादमगिरी में सोमवती अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में 10 लोग मारे गये थे।

नेशनल कार्ड्स रिकार्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2011 के दौरान भगदड़ की घटनाओं में 489 लोग मारे गये थे। धार्मिक अवसरों पर ही भगदड़ नहीं हुई है, रेलवे स्टेशन, सेना व पुलिस

की भर्ती के दौरान भी भगदड की घटनाएँ हुई है और लोगों ने जान गवाई है। वर्ष 2005 में तमिलनाडु में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के शिविर में भगदड मच गई थी, जिससे कई मौतें हुई थी, किन्तु यह निर्विवाद है कि 95 प्रतिशत घटनाएँ हिन्दु धार्मिक उत्सवों के दौरान घटी है, और मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाएँ व बच्चे रहें हैं। वर्ष 2011 में हरिद्वार में भगदड तब हुई जब यज्ञ में डाली जा रही सामग्री से पैदा धुएँ के कारण लोगों का दम घुटने लगा। मंदिरा देवी मंदिर में भगदड में 300 लोग मारे गये थे, कारण यह था कि धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए एक महिला सिर पर इतनी सामग्री ले जा रही थी कि वह गिर पड़ी और तेल बिखर गया, जिसकी फिसलन से भगदड मच गई। 2003 के नासिक कुंभ में साधुओं ने बिना अनुमति हाथियों और कार पर जुलूस निकाला और भक्तों पर प्रसाद व सिक्के फेंकना शुरू कर दिये, जिनको बटोरने की स्पर्धा में भगदड मच गई और 118 लोग मारे गये। राजस्थान के जोधपुर जिले में नवरात्रा पूजा के दौरान मंदिर में भगदड से 55 लोग मारे गये जिसमें अधिकतर महिलायें थी।

भगदड का धार्मिक सोच—विचार से गहरा सम्बन्ध है, धार्मिक विचार खुद असुरक्षित होने के अहसास पर टिका हुआ होता है, जो मनोविज्ञान हमें इन स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करता है, बढ़ती सामाजिक असमानता, असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जो बदले में इस तरह का अहसास और बढ़ाती है। हमारे यहां तंत्र एवं भगदड की घटना का सम्बन्ध इस प्रकार की सोच ही है।

भगदड की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना

- संभावित भगदड स्थल का चिन्हीकरण।
- एक समय में कितने लोगों का एकत्रित होना।
- स्थल पर जाने— आने का रास्ता का चिन्हीकरण।
- सडक के आवागमन का नक्शा।
- स्थल पर भीड इकट्ठा होने की क्षमता (समय के अनुसार)
- एक समय में कितनी भीड ठहरती है।

- भीड के प्रबन्धन के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था।
- भीड वाले स्थल का खतरा, संवेदनशीलता एवं नुकसान की रोकथाम के लिए चैकलिस्ट एवं सूचना तैयार करना।
- क्या—क्या खतरा हो सकता है, और उससे क्या नुकसान हो सकता है की सूची तैयार करना।
- आपात निकासी, नक्शा तैयार करना एवं विशेषज्ञ से जांच कर पारित कराना।
- आपातकालीन ठहराव स्थान एवं आवागमन के लिए नक्शा तैयार कर चिन्हीकरण करना।
- आवश्यक अग्नि चेतावनी व्यवस्था एवं अन्य चेतावनी बोर्ड लगवाना।
- भीड सम्बोधन यंत्र की व्यवस्था करना।
- प्रथम चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना।
- ट्रौमा सेंटर एवं नजदीकी चिकित्सा सुविधा स्थापित करवाना।
- संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल, प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा लेना।

विद्यालय सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव उपाय

(माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिशा निर्देश)

विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के जांच एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पूर्व अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन बचाव उपाय एवं आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण की स्थिति नगण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश 13 अप्रैल 2009 में पारित कर स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सभी संचालित विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के सुरक्षा एवं अग्नि बचाव उपाय की पालना सुनिश्चित की जाये। सभी विद्यालयों में तय मानको के अन्तर्गत अग्निशमन यंत्र लगाये जायें, बिल्डिंग बायलॉज 2005 के अन्तर्गत विद्यालय के भवनों की सुरक्षा मानक तय की जाये एवं आपदा एवं बचाव उपायों पर कार्ययोजना बनाकर सभी स्टाफ एवं छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये। लेकिन जांच में पाया जा रहा है कि विद्यालय प्रबन्धन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार आपदा थोड़ी सी लापरवाही से पूर्व में हो चुकी है एवं कई मौतें रिकॉर्ड पर है। सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर आपदा प्रबन्धन योजना एवं आपातकालीन नम्बरों को दर्शाया जाए, विद्यालयों में प्रशासन की मदद से मॉक ड्रिल एवं आवश्यक प्रशिक्षण एक समय सीमा के अन्तराल पर कराई जाये। इस सुरक्षा मामले की लापरवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित न होने पर न्यायसंगत कार्यवाही आदेश में अंकित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (2 ए) के अन्तर्गत जिला कलक्टर किसी संभावित आपदा को रोकने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है, अतः कलक्टर अपने निर्देश से सभी संचालित सरकारी एवं निजी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें, ताकि संभावित आपदा को समय पूर्व रोका जा सकें, साथ ही खतरा एवं संवेदनशीलता चिन्हित हो सके।

कोटपूतली-बहरोड बस स्टेण्ड आपातकालीन कार्ययोजना

- बस स्टेण्ड पर बम विस्फोट की घटनाएँ।
- आकस्मिक अग्निकांड

बस स्टेण्ड, शहर के मध्य स्थापित है। इन आगार द्वारा अपने अधिकृत मार्गों पर भेजी जाने वाली वाहनों को समयानुसार भिजवाया जाता है तथा यहां वाहनों को निर्धारित स्टेण्डो से बुकिंग कराते हुए गन्तव्य स्थानों पर भेजा जाता है। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत आगार की व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार से है:-

1. बम विस्फोट की घटना होने पर तुरन्त ही आस-पास के क्षेत्र को खाली करवाया जा सकता है।
2. बस स्टेण्ड पर खाली निगम वाहन उपलब्ध होने के कारण आकस्मिक व्यवस्था तुरन्त ही उपयोग में लायी जा सकती है।
3. लगातार 24 घंटे प्रत्येक प्लेटफार्म पर ड्यूटी ऑफिसर एवम् वाहन आवागमन क्लर्क एवम् पुछताछ क्लर्क का पदस्थापन किया हुआ है जो होने वाली घटनाओं पर पारीनुसार निगरानी करते है व बार बार सतर्क रहने की चेतावनी उद्घोषित करते रहते है।
4. निगम परिसर में वर्कशॉप में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रहरियों को पारी अनुसार विभाजन कर लगाया हुआ है तथा सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढ़ाने हेतु निगम मुख्यालय लिखा जा चुका है।
5. बस स्टेण्ड परिसर में निगम का निजी ट्यूब वैल स्थापित होने के कारण पूरे परिसर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है।
6. बस स्टेण्ड पर बुकिंग घरों को स्थापित किया हुआ है। जो चारों ओर जाली से बनाये हुए है जिससे टिकिट पत्रक टिकिट वितरण करते है साथ ही बाहर की गतिविधियों पर निगरानी भी रखते है।
7. निगम परिसर में स्थापित शौचालयों पर टैकेदार के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किये हुए है जो इन स्थानों को नियमित रूप से साफ करते रहते है।
8. समस्त निगम परिसर में अग्नि यंत्रों की व्यवस्था की हुई है।

आपात प्रतिक्रिया योजना (इमरजेन्सी रिसपोन्स प्लान)

आपदा को चरणबद्ध तरीके एवं सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के लिए राज्य एवं जिला प्रशासनिक स्तर के संगठन में आपसी तालमेल एवं समन्वय की जरूरत होती है, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर आपात प्रतिक्रिया कार्ययोजना तैयार की जाती है। यह योजना एक ही प्लेटफार्म से कई आपदा को एक साथ प्रबन्धन करने का सटीक औजार है, जो आपसी समन्वय से संचालित किया जाता है, ताकि आपदा के प्रभाव को कम समय में कम कर नुकसान एवं क्षति को रोका जा सके। इसके लिए लिखित रूप में प्रभावी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिसका समय-समय पर मॉक ड्रिल एवं चर्चा कर संसाधन एवं आपातकालीन सम्पर्क नम्बर को अपडेट किया जाता है।

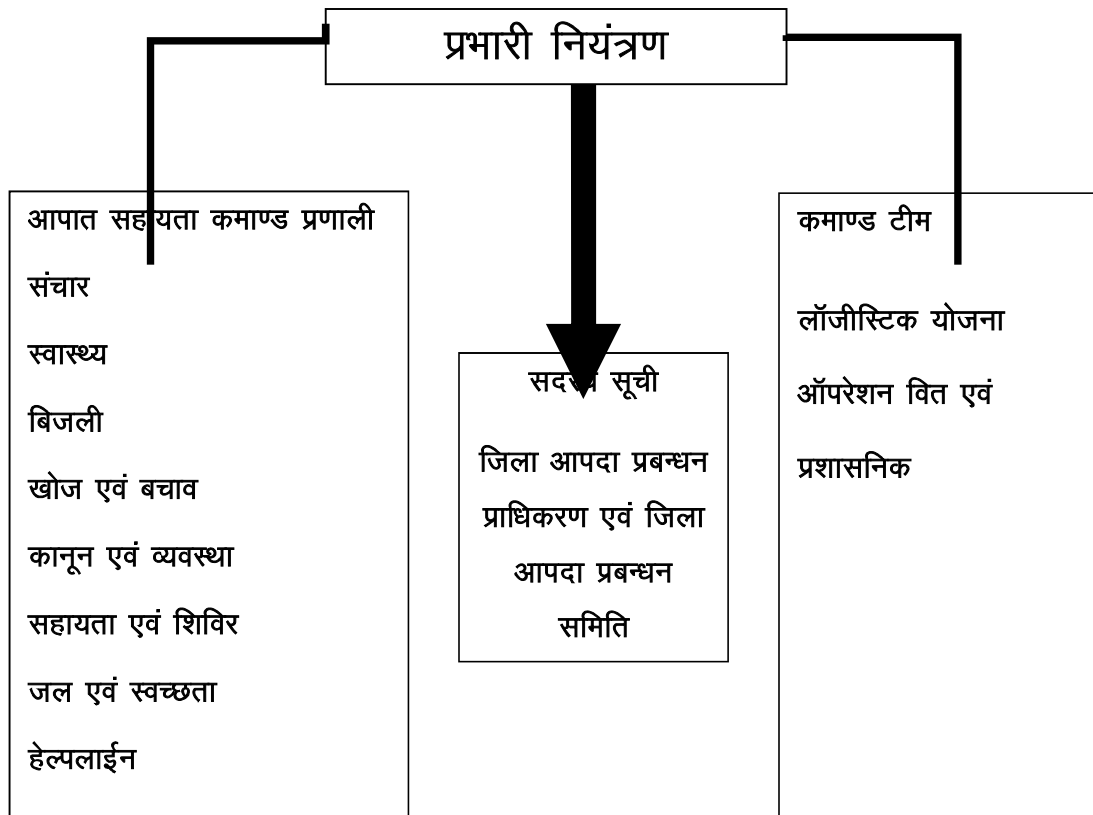
प्रतिक्रिया (रिसपोन्स) योजना को लागू करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम जिले में संभावित विभिन्न आपदा को चिन्हित किया जाये।
- पूर्व की घटित आपदा का विश्लेषण।
- भूगर्भीय व्यवस्था।
- आपदा में संवेदनशीलता की भूमिका।
- सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नुकसान का आंकलन।
- राज्य के गाईडलाईन के आधार पर इमरजेन्सी रिसपोन्स कार्यकलाप चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी एजेंसी का चिन्हिकरण।
- जिम्मेदार अधिकारी, मानव संसाधन एवं अन्य मौजूदा संसाधन का चिन्हिकरण।
- प्रथम एवं द्वितीय एजेंसी का चिन्हिकरण।
- व्यवस्था को सुचारु संचालित करने के लिए प्रशिक्षण , मिटिंग, मॉक ड्रिल, सेमीनार का बराबर आयोजन।

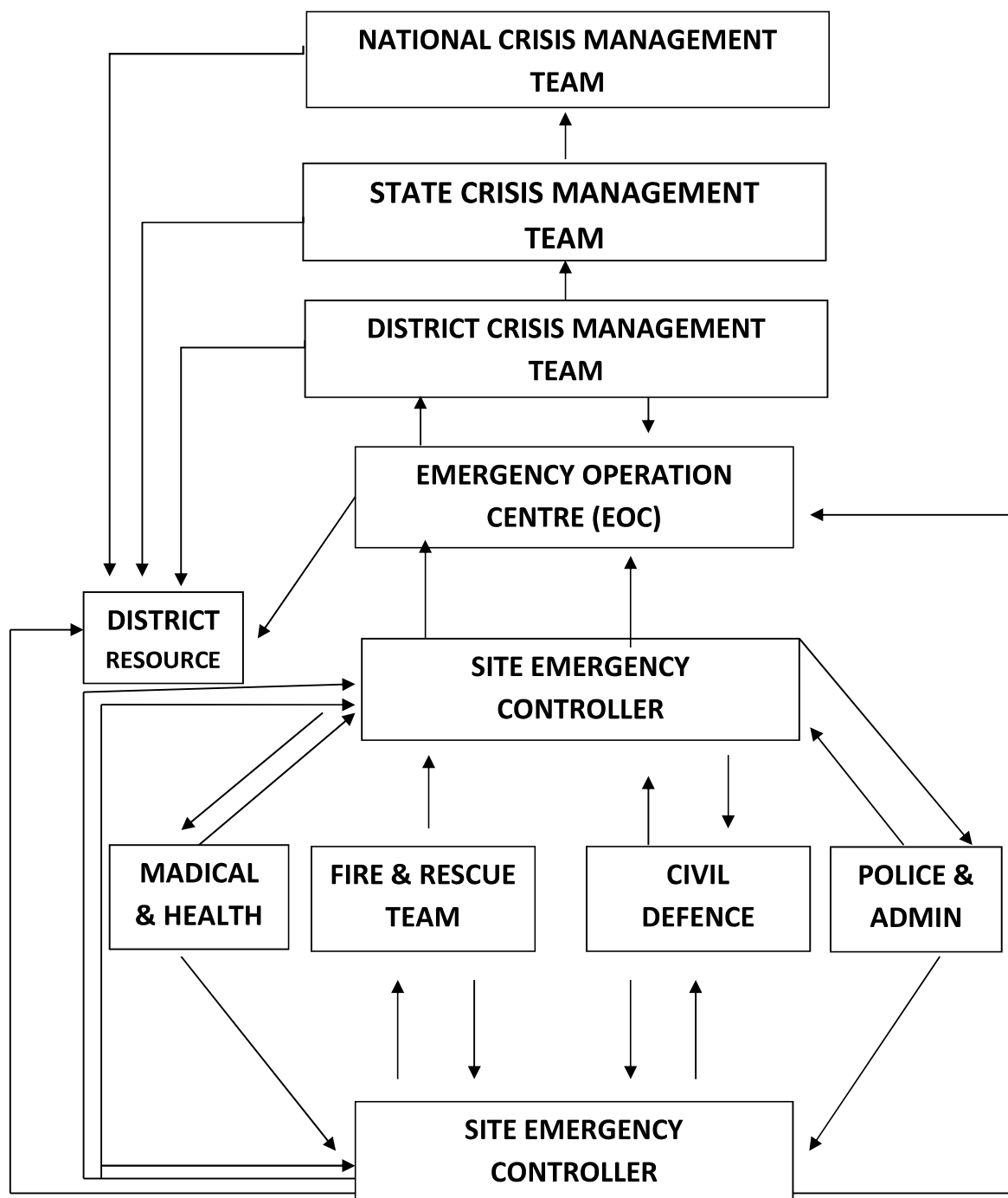
आतापकालीन सहायता संचालन की संरचना (ईएसएफ)

ईएसएफ	संचालन	संभावित कार्य	नोडल एजेंसी / टीम लीडर	सहायता विभाग / एजेंसी
ईएसएफ1	समन्वयक	सरकारी तंत्रों में समन्वय स्थापित कर सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को स्थापित कराना।	जिला कलक्टर	पुलिस अधीक्षक, अति. कलक्टर सहायता, सीएमएचओ, नगर परिषद / नगरपालिका / नगरनिगम, पीडब्लूडी, पीएचईडी, विधुत, जिल संसाधन, परिवहन, अग्नि, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सभी संबंधित विभाग, थानाधिकारी।
ईएसएफ2	संचार प्रणाली	आपात स्थिति में सभी संचार प्रणाली यंत्रों को दुरुस्त कर पुनः स्थापित करना	जिला पुलिस अधीक्षक	एनआईसी, पुलिस, अग्नि, ईओसी, वायरलेस विभाग, टेलिकॉम विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, दूरदर्शन।
ईएसएफ3	हेल्पलाईन चेतावनी, आपातकालीन सूचना निदेशिका	प्रभावित लोगों के बीच सही सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना को अपडेट करना, लोगों को प्रभावित क्षेत्र से निकालकर सहायता शिविर तक पहुंचाना।	एसडीएम, पुलिस	एनआईसी, एसडीएम, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, एनजीओ, मीडिया, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवक
ईएसएफ4	खोज एवं बचाव	टूटे हुए मकानों से दबे हुए घायलों को बाहर निकालना, घायलों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं शिविर की व्यवस्था, इस प्रक्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुभवी, खोज एवं बचाव टीम का गठन	अग्निशमन अधिकारी, सिविल डिफेंस	अग्नि, सिविल डिफेंस, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह रक्षा, आर्मी, पीडब्लूडी, नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद, चिकित्सा, एनजीओ, वार्ड / ग्राम पंचायत प्रतिनिधि।

		करना, साथ ही खोजी कुते का प्रबन्ध करना ।		
ईएसएफ5	आपात निकासी	भूकम्प, रासायनिक दुर्घटना, आतंकवादी घटना, बम विस्फोट, अग्नि दुर्घटना एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना ।	एसडीएम, तहसीलदार , एसएचओ	पुलिस , गृह रक्षा, अग्नि विभाग, सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक एवं एनजीओ
ईएसएफ6	आपात चिकित्सा सुविधा	घायलों को तुरन्त चिकित्सा, मृत व्यक्ति का निस्तारण, महामारी से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सेवा	सीएमएचओ	जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, ट्रोमा सेंटर, रेडक्रॉस सोसायटी, नर्सिंग होम, डिसपेन्सरी एवं अन्य चिकित्सा सेवा केन्द्र ।
ईएसएफ7	सहायता	जरूरत एवं प्रभावित लोगों के बीच खाद्य एवं जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना	एडीएम, डीएसओ, सिविल डिफेंस	एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, परिवहन, एनजीओ, सिविल डिफेंस, स्वयं सेवी संस्था



RESPONSE SYSTEM FLOW CHART



अध्याय : 17

आपदा प्रबन्धन में मीडिया की जिम्मेदारी

आपात स्थिति एवं सम्भावित आपदा की स्थिति में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निम्नानुसार जिम्मेदारी निभाते हैं :—

1. प्रभावित क्षेत्र एवं आपात स्थिति की सही जानकारी प्रशासन एवं आमजन के बीच रखने का काम।
2. प्रशासन के साथ सहयोग कर आपात स्थिति को नियंत्रण करना।
3. अफवाह से होने वाले अधिक जान-माल की क्षति को रोकना।
4. आमजनों एवं प्रभावितों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर बचाव कार्यों में मदद करना।
6. सम्भावित खतरे का समय रहते नियंत्रण एवं रोकथाम करने में प्रशासन की मदद करना।
7. आमजनों को प्रेरित कर सुरक्षित माहौल तैयार करने में सहभागिता निभाना।
8. आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करना।

राजस्थान राहत कोष

(STATE CALAMITY FUND)

अकाल, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्नि चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन-धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष ;छंजपवदंस बंसउपजल थनदकद्ध से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएँ तथा गैर प्राकृतिक आपदाएँ भी हैं जिनसे होने वाली जन-धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिए वर्ष 2005-06 को राज्य के बजट में राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाओं संबंधी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित है।

शीर्षक :

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

“ राजस्थान राहत कोष” का गठन एवं संचालन –

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निक्षेप खाते में रखी जायेगी।
2. किसी दानदाता या संस्था इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्यमंत्री सहायता कोष की भांति इस कोष में दी गई राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आयकर विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियंत्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

राज्य स्तरीय समिति :-

राज्य स्तर पर “राजस्थान राहत कोष” के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी।

मुख्य सचिव	— अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	— सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	— सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	— सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	— सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग	— सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग	— सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	— सदस्य

राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप—

1. राजस्थान, राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. “राजस्थान राहत कोष” से होने वाले व्यय के वित्त पोषण संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. “राजस्थान राहत कोष” के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. “राजस्थान राहत कोष” से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाये उन प्रयोजनों लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति को उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया सकेगा।

7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो “ राजस्थान राहत कोष” की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

“राजस्थान राहत कोष” के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाएँ –

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढहने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य।
3. बहुमंजिले भवनों के ढहने, कुएं के ढहने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य।
4. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने तथा कुएं में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव कार्य।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाएँ जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हो, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे –

1. मनुष्यों में महामारी— विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोंतो निकाले गये मापदण्डों से अत्यधिक हो।
2. पशुओं में महामारी— किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डों से अत्यधिक हो।
3. फसलों में महामारी — विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष को सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

विभिन्न आपदाओं के लिए नोडल विभाग

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. मनुष्यों की महामारी | — चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 2. पशुओं की महामारी | — पशु पालन विभाग |
| 3. फसलों की महामारी | — कृषि विभाग |
| 4. खान में बाढ़ का पानी आना एवं ढहना | — खान विभाग |
| 5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य | — आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग |

क. उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।

ख. प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योजना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।

ग. उपरोक्तानुसार बनायी गयी योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा जायेगा तथा समय समय पर उसे अपडेट करने की कार्यवाही भी संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।

घ. राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसको क्रियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड —

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिए सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिए किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/ मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो, तो उस आपदा के लिये “राजस्थान राहत कोष” से सहायता देय नहीं होगी।

3. “राजस्थान राहत कोष” से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुएं आदि के ढहने की आपदा में
5. खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।
6. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिए, निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी :

1. कुएं ढहने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकाले पर होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपयें की राशि।
2. मिट्टी एवं चट्टान ढह जाने से होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
3. कुएं में जहरीली गैस निकालने से मृत्यु होने पर आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिए अधिकतम 10,000 रूपयें की राशि।

राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि –

1. संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में “राजस्थान राहत कोष” के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, संबंधित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा संबंधित नोडल विभाग की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को संबंधित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।

3. महामारी की आपदाओं में, उप पर नियंत्रण करने एवं पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जायेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजना जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसेक आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिशंषा को राज्य समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करायी जावेगी तथा संबंधित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

अध्याय 19

तहसील कोटपूतली आपदाप्रबन्धन योजना-2025

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय:-

तहसीलदार कोटपूतली का सृजन स्टेट टाइम से ही है जो जिला मुख्यालय पर स्थित है जो कि जयपुर दिल्ली वाईपास से पर स्थित है। तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर (6375876959) एवं नायब तहसीलदार श्रीमती शिवानी भार्मा (8209804739) है।

2. तहसील में संभावित खतरा :-

तहसील में कोटपूतली-बहरोड चतुर्भुज क्षेत्र में बारिश के पानी भराव की समस्या होने के कारण आवागमन व जन-पशु हानी होने का खतरा है। इटली जोहड बासडी में बारिश के पानी भराव की समस्या से आस-पास की कलोनियां प्रभावित होते हैं।

3. यातायात व्यवस्था:-

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है। व सीकर अलबर स्टेट राजमार्ग भी कोटपूतली पर पहुंच मार्ग है।

4. तहसील मूलभूत संसाधन:-

जिला अस्पतालस कोटपूतली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारेहडा व बनेठी में स्थित है। है तथा मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय केन्द्र है। अग्निसमन व्यवस्था-नगर परिशद कोटपूतली में स्थित जो जिला मुख्यालय पर है।

- तहसील में बिजली की व्यवस्था-अन्य फीडर से जुड़ा है।
- पीने के पानी की व्यवस्था-जलदाय विभाग द्वारा किया जाता है।

5. तहसील में ग्रामों/ग्राम पंचायतों की संख्या:- तहसीलकोटपूतली में 20 ग्रामपंचायत व 92 राजस्व ग्राम है।

6. तहसील की जनसंख्या:- तहसील क्षेत्र की कुल 232195 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।

7. एपील/बीपलअन्य:-

8. दक्ष लोगो का विवरण:- तहसील कोटपूतली में डॉक्टर/कम्पांडर/वैद्य/आयुर्वेद कम्पांडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं है।

9. जीविकोपार्जन:- तहसील कोटपूतली में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कुछ परिवार व्यवसाय/नौकरी करते हैं।

10. मुख्य फसल:- रबी-गेहूं जौ, चना सरसों है/खरीफ-बाजरा, ग्वार तिल है।

11. नदी/बांध/तालाब/नालों की स्थिति:- तहसील कोटपूतली में साबी नदी चतुर्भुज, बामनवास, नांगल पंडितपुरा क्षेत्र में बहता है। व सोता नाला सरुण्ड, खेडानिहालपुरा, गोपालपुरा, करवास क्षेत्र से गुजरता है।

12. संचार के साधन:- एयरटेल/वी.आई./जीओ के टावर व कनेक्टिविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।

13. स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिककेन्द्र:- कोटपूतली में दो महाद्यालय व स्कूल स्थित है। धर्मशाला व सामुदायिक केन्द्र है।
14. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची:- तहसील कोटपूतली में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
15. तहसील में उपलब्ध राजकीय/कार्मिकों के नाम व दूरभाष:-सूची संलग्न है।
16. नगरपालिका क्षेत्र उपलब्ध हो तो उसका नाम:-नगरपरिशद कोटपूतली स्थित है।
17. तहसील क्षेत्र में औद्योगिक इकाईया:- तहसील कोटपूतली क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थित है।
18. उपलब्ध मेडिकल दुकानों/सरकारी/प्राइवेट/अस्पतालों व डिस्पेंसरी का नाम विस्तारों की क्षमता /डॉक्टरों/नर्सिंगस्टॉफ की संख्या/पेट्रोलपम्प/ गैस एजेन्सी /गैसगोदाम:-3. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारेहडा,बनेठी में डाक्टर पर्याप्त है। व नर्सिंगस्टॉफ भी पर्याप्त है। एक औषधालय जिसमें पर्याप्त डॉक्टर व कम्पाउंडर कार्यरत है। पेट्रोलपम्प-लगभग 20/गैस एजेन्सी-3 उपलब्धत है।

अनुज्ञाधारक का नाम एवं पेट्रोल पम्प का नाम

श्री कृष्ण भार्मा-9829971213	मैसर्स आनन्द सर्विस स्टेशन चौकी गोरधनपुरा कोटपूतली
------------------------------	---

19. भारीमशीनरी से संबंधित लोगो की सूची:- तहसील क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लान्ट मोहनपुरा में स्थित है।

अध्याय 20

तहसील मांढण आपदा प्रबंधन योजना 2025

तहसील मांढण आपदा प्रबंधन योजना—2024

1 तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय—

तहसीलदार मांढण का सृजन माह 11/07/2023 से हुआ है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली—बहरोड से 66 किलो मीटर दूर स्थित है जो कि बहरोड से कुण्ड रोड पर स्थित है। तहसीलदार का पद रिक्त है जबकि नायब तहसीलदार श्री सुमित भारद्वाज है जिनको कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में पदस्थापित है।

2 तहसील में संभावित खतरा—

तहसील मांढण में रेवाडी—रींगस रेल्वे लाईन में काठूवास ग्राम में बने अडर पास में बारिश के पानी भराव की समस्या होने के कारण आवागमन व जन—पशु हानि होने का खतरा है। अडर पास में बारिश के पानी भराव की समस्या से ग्राम—काठूवास,हुडिया खुर्द, परतापुर,बींझपुर,जैतपुर,रामचन्द्रपुरा व रघुनाथपुरा प्रभावित होते हैं। इसके निदान हेतु जनरेटर द्वारा बारिश के समय में जल निकासी का कार्य सतत किया जाता है।

3 यातायात व्यवस्था

बहरोड से कुण्ड स्टेट हाइवे मार्ग पर ही स्थित है, जिस पर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4 तहसील मूलभूत ससाधन —

तहसील मांढण के ग्राम मांढण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जैतपुर, माजरा,डाबडवास व नंगली—बलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है।

अग्नि शमनव्यवस्था —अग्नि शमन केन्द्र नहीं है लेकिन टोल प्लाजा काठूवास में व रीको नीमराना में अग्नि शमन केन्द्र है जो तहसील मुख्यालय मांढण से क्रमशः 5 व 15 किलो मीटर दूर है।

तहसील में बिजली की व्यवस्था 132 के वी नानगवास फीडर से जुड़ा है।

पीने के पानी की व्यवस्था —सभी ग्रामों में पेयजल के बोरवेल उपलब्ध है।

1. तहसील में ग्रामो/ ग्राम पंचायतों की संख्या— तहसील मांढण में 12 ग्राम पंचायत व 32 राजस्व ग्राम है।
2. तहसील की जनसंख्या तहसील क्षेत्र की कुल 59415 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।

3. दक्ष लोगो का विवरण –तहसील मांढण में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं हैं।
4. जीविकोपार्जन– तहसील मांढण में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं कुछ परिवार व्यवसाय / नौकरी करते हैं।
5. मुख्य फसल– रबी–गेहूँ सरसों हैं/ खरीफ– बाजरा, ग्वार हैं।
6. नदी/बाध/तालाब / नालो की स्थिति– नदी/बाध/तालाब/नाले स्थित नहीं हैं।
7. संचार के साधन एयरटेल/बीएसएनएल/जीओ के टावर व कनेक्टिविटी हैं। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।
8. स्कूल/धर्म शाला/सामुदायिक केंद्र स्कूल स्थित हैं।
9. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची तहसील मांढण में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
10. तहसील में उपलब्ध राजकीय / कार्मिकों के नाम व दूरभाष– सूची सलग्न हैं।
11. नगर पालिका उपलब्ध हो तो उसका नाम –नगर पालिका मांढण हैं।
12. तहसील क्षेत्र में औद्योगिक इकाईया –तहसील मांढण क्षेत्र में रीको क्षेत्र डाबडवास में औद्योगिक इकाई स्थित हैं।
13. उपलब्ध मेडीकल दुकानों/सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों व डिस्पेंसरी का नाम बिस्तरों की क्षमता / डॉक्टरों/ नर्सिंग स्टॉफ की संख्या/पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी/ गैस गोदाम–
1 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांढण – 3 डॉक्टर व 5 नर्सिंग स्टॉफ, निजी व सरकारी मेडीकल स्टोर हैं।पेट्रोल पम्प नहीं है परन्तु हरियाणा के पेट्रोल पम्प 4 किमी दूरी पर हैं। एच पी गैस एजेन्सी ग्राम मांढण में स्थित हैं ।
14. तहसील के ग्रामों में जेसीबी/अन्य मशीनरी उपलब्ध हैं।

कार्यालय तहसीलदार मांडण मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क्र०स०	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
1	श्री सुमित भारद्वाज	कार्यवाहक तहसीलदार	तहसील मांडण	7014147782
2	श्री सत्यपालसिंह	ऑफिस कानूनगो, मांडण (अति०प्रभार)	तहसील मांडण	9461041910
3	श्री औमप्रकाश शर्मा	भू०अ० निरीक्षक	मांडण	7792986688
4	श्री रामसिंह यादव	भू०अ० निरीक्षक	कान्हावास	7014143173
5	श्री सत्यपालसिंह	भू०अ० निरीक्षक	गिगलाना	9461041910
6	श्री सुमेर सिंह	पटवारी (अति०प्रभार)	मांडण	7426040806
7	श्री मनीष कुमार	पटवारी	परतापुर	9887580626
8	श्री प्रदीप कुमार 2	पटवारी (अति०प्रभार)	काठूवास	8278027485
9	श्रीमती सुरेखारानी	पटवारी	हुडिया कला	9306498307
10	श्री सुबेसिंह	पटवारी	गिगलाना	7665989928
11	श्री पवन कुमार	पटवारी	सांतो	9667493470
12	श्री प्रदीप कुमार 1	पटवारी	महतावास	9660806060
13	श्री हरीश कुमार	पटवारी	नानगवास	9828970122

14	श्री जयप्रकाश	पटवारी	कान्हावास	9680710843
15	श्री देवेन्द्र कुमार	पटवारी	डाबडवास	9649360030
16	श्रीमती नीलम यादव	पटवारी	माजरा	7827268566
17	श्री सुमेर सिंह	पटवारी	खून्दरोठ	7426040806
18	श्री नवीन कुमार	पटवारी	एलआरसी 1	9680976860
19	श्री प्रदीप कुमार 2	पटवारी	एलआरसी 2	8278027485

अध्याय-21

तहसील बानसूर आपदा प्रबन्धन योजना-2025

कंटिजेंसी प्लान (तहसील-बानसूर)

● सामान्य परिचय : तहसील बानसूर **27.6919419** अक्षांश व **76.3490575** देशान्तर पर स्थित है यह उपखण्ड/तहसील मुख्यालय है जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड़ तहसील-बानसूर से **17** किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैद्य निकतम रेल्वे स्टेशन (खैरथल स्टेशन) तथा निकटतम एयर पोर्ट जयपुर है तहसील बानसूर में एक उप-तहसील हरसौरा दिशा उत्तर में **18** किलोमीटर दूरी पर स्थित है तहसील बानसूर के पिन कोड नम्बर **301402** तथा पुलिस थाना तहसील मुख्यालय तथा उप तहसील मुख्यालय पर स्थित है तहसील बानसूर में **126** राजस्व ग्रामएं **30** पटवार मण्डलएं **08** भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तएं ग्राम पंचायत **37** एवं **01** नगरपालिका तहसील मुख्यालय बानसूर में स्थित हैद्य तहसील बानसूर का भौगोलिक क्षेत्रफल **55751** हेक्ट. है जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष सम्पर्क नम्बर **01421-299036** एवं जल संसाधन खण्ड सिचाई विभाग अलवर सम्पर्क नम्बर **6960939325**.

- बाढ़ एवं अतिवृष्टि की तैयारी :- बाढ़ एवं अतिवृष्टि के लिए तहसील के समस्त भू-अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियान को हल्के में पाबंद रहने के लिए एवं अतिवृष्टि एवं बाढ़ की सूचना तुरन्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष में देने हेतु पाबंद किया गया है
- दानदाता एवं जनसेवी/स्वयं सेवी संस्थाओं को समय पर सहयोग करने की अपील की गई है
- बाढ़ एवं आपदा के समय भोजन गुड़ एवं चना की व्यवस्था इन्ही संस्थाओं से ली जाएगी
- नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों को नाले एवं नालियों की सफाई के लिए पाबंद कर दिया गया है
- इस तहसील में सिचाई विभाग का एक बांध है जिसका नाम हरसौरा बांध हैद्य जिसमें सामान्य पानी आता है तथा ग्राम मंगलवा के आस-पास नदी में पानी भराव का खतरा रहता हैद्य जिसके लिए संबन्धित काश्तकारों को भराव क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है
- इस तहसील में ग्राम-बालावास रोड पर घड़िया जोहड़ स्थिति हैद्य तथा ग्राम-बाढ़ ठेगूवास में गैर मुमकिन तालाब हैद्य उक्त दोनों में वर्षा का पानी एकत्रित होता है आस-पास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है
- अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिए व्यवस्था:- अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के ठहरने के लिए सामुदायिक भवन/विद्यालय का उपयोग लिया जा सकेगाद्य तथा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तात्कालिक सहायता देने का प्रयास किया जाएगा

- नगर पालिकाए पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत : नगर पालिकाए पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अपने स्तर पर मिट्टी के कट्टे, खाली कट्टे, गैती, टॉर्च केरोसीन आदि तैयार रखें
- अन्य विभाग : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागए विद्युत विभाग.पशुपालन विभागए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागए पुलिस विभागए सार्वजनिक निर्माण विभाग : उक्त सभी विभागों को अपने-अपने स्तर से बाढ़ एवं अतिवृष्टि में सक्रिय रहकर अपने स्तर से संसाधन जुटाकर बाढ़ एवं आपदा में सहयोग करेंगे

➤ कार्यालय तहसीलदार बानसूर मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	पदस्थापन स्थान	मोबाइल नम्बर
गजेन्द्र सिंह	तहसीलदार	बानसूर	9910365470
अर्जुन लाल सालोदिया	उप-तहसीलदार	हरसौरा	9950249683
चन्द्र सिंह मीना	नायब तहसीलदार	बानसूर	9829562426
महेन्द्र सिंह मौर्य	ऑफिस कानूनगो	भू.अ. शाखा बानसूर	9829334937
भागचन्द मीना	अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो	भू.अ. शाखा बानसूर	9079712096
शुभराम जाट	ILR (LR)	भू.अ. शाखा बानसूर	99299797065
अशोक कुमार मीना	ILR (LRC)	भू.अ. शाखा बानसूर	9521218467
कृष्ण कुमार	ILR (LR)	भू.अ. शाखा बानसूर	9929947271
हितेश कुमार माथुर	भू-अभिलेख निरीक्षक	रामपुर	8769586211
राजेन्द्र सिंह यादव	भू-अभिलेख निरीक्षक	बानसूर	9982192584
रोहिताश्व स्वामी	भू-अभिलेख निरीक्षक	गूंता	8696680302
सुमेर सिंह गोठवाल	भू-अभिलेख निरीक्षक	गिरूड़ी	9799892331
भैरुमल स्वामी	भू-अभिलेख निरीक्षक	हमीरपुर	9982184580
शिवराज सिंह शेखावत	भू-अभिलेख निरीक्षक	हरसौरा	9887752525
हितेश कुमार माथुर	भू-अभिलेख निरीक्षक	बाबरिया	8769586211
अशोक कुमार मीना	भू-अभिलेख निरीक्षक	बुटेरी	9521218467
पंकज सिंह राठौड़	पटवारी	बानसूर	9079843945
ज्योति यादव	पटवारी	बालावास	8290094902

रमेश चन्द ज्योतिषी	पटवारी	भूपसेड़ा	8005545143
सोनियाराम	पटवारी	रामपुर	7014541174
अतुल कुमार यादव	पटवारी	बहरामकाबास	9784983870
जितेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	हाजीपुर	8619380513
पंकज कुमार सूठवाल	पटवारी	लेकड़ी	9636291773
राकेश कुमार	पटवारी	बुटेरी (ई.)	6377327571
विरेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	बबेरा (ई.)	9928034713
विरेन्द्र सिंह शेखावत	पटवारी	खेड़ा	9928034713
राकेश कुमार	पटवारी	लोयती	6377327571
राहुल कुमार यादव	पटवारी	नांगल लाखा (ई.)	7300318987
संतोष यादव	पटवारी	श्यामपुरा	6376940162
मोहित कुमार यादव	पटवारी	गूता	7426896612
विष्णु कुमार स्वामी	पटवारी	मौठूका	9251431036
राकेश कुमार सामदिया	पटवारी	शाहपुर (ई.)	7597677645
मीना देवी जाट	पटवारी	महनपुर	7300351042
मायाराम गुर्जर	पटवारी	गिरूड़ी	7597364932
अतुल कुमार यादव	पटवारी	खोहरी	9784983870
पंकज कुमार सूठवाल	पटवारी	होलावास	9636291773
महेश कुमार मीना	पटवारी	हमीरपुर	9660208954
सुभाष चन्द	पटवारी	छीण्ड	6375074189
घनश्याम शर्मा	पटवारी	चूला	9829584802
जयसिंह मीना	पटवारी	हरसौरा	8955684413
राहुल कुमार यादव	पटवारी	माजरा अहीर	7300318987
महेश कुमार मीना	पटवारी	बामनवास (ई.)	9660208954
मुकेश कुमार सिंह	पटवारी	भग्गूकाबास	8619469617
बिजेन्द्र सिंह	पटवारी	बाबरिया	8769898471
कृष्ण कुमार यादव	पटवारी	माजरा ढाकोड़ा	8290300797
बिजेन्द्र सिंह	पटवारी	बबेड़ी (ई.)	8769898471

अध्याय-22

तहसील पावटा आपदा प्रबन्धन योजना 2025

प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत बचाव की पूर्व तैयारी हेतु कंटीजेंसी प्लान (कोटपूतली-बहरोड)

1. सामान्य परिचय – तहसील पावटा 25.580175 अक्षांश व 76.079387 देशान्तर पर स्थित है। यह उपखण्ड/तहसील मुख्यालय है। जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड तहसील पावटा से 17 किलोमीटर दूर स्थित है तथा जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। निकतम रेल्वे स्टेशन जयपुर तथा निकतम एयर पोर्ट जयपुर है। तहसील पावटा के पिन कोड नम्बर 303106 तथा पुलिस थाना तहसील मुख्यालय निकट स्थित है। तहसील पावटा में 79 राजस्व ग्राम, 25 पटवार मण्डल, 06 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 23 ग्राम पंचायत एवं 01 नगरपालिका तहसील मुख्यालय पावटा में स्थित है। तहसील पावटा का भौगोलिक क्षेत्रफल 41252.15 हैक्ट. है।
2. जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष सम्पर्क नम्बर 01421-299036 एवं जल संसाधन खण्ड सिंचाई विभाग अलवर सम्पर्क नम्बर 6960939325 को प्रेषित करेंगे।
3. बाढ़ एवं अतिवृष्टि की तैयारी – बाढ़ एवं अतिवृष्टि के लिए तहसील के समस्त भू अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियान को हल्के में पाबंद करने के लिए, रहने के लिए, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की सूचना तुरन्त बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में देने हेतु पाबंद किया गया है।
4. दानदाता एवं जनसेवीध्वयं सेवी संस्थाओं को समय पर सहयोग करने की अपील की गई है।
5. बाढ़ एवं आपदा के समय भोजन गुड एवं चना की व्यवस्था इन्ही संस्थाओं से ली जाएगी।
6. नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों को नाले एवं नालियों की सफाई के लिए पाबंद कर दिया गया है।
7. इस तहसील में सिंचाई विभाग का एक बांध है जिसका नाम बांध है। जिसमें सामान्य पानी आता है तथा ग्राम के आस-पास नदी में पानी भराव का खतरा रहता है। जिसके लिए संबंधित काश्तकारों को भराव क्षेत्र को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है।
8. इस तहसील में ग्राम पर जोहड स्थित है तथा ग्राम ग्राम में गैर मुमकिन तालाब है। उक्त दोनो में वर्षा का पानी एकत्रित होता है। आस-पास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है।
9. अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीडित व्यक्तियों के लिए व्यवस्था – अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीडित व्यक्तियों के ठहरने के लिए सामुदायिक भवनध्विद्यालय का उपयोग लिया जा सकेगा तथा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए तात्कालिक सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।
10. नगरपालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत – नगर पालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अपने स्तर पर मिट्टी के कट्टे, खाली कट्टे, गैती, टॉर्च, केरोसीन आदि तैयार रखें।
11. अन्य विभाग – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त सभी विभागों को

अपने-अपने स्तर से बाढ़ एवं अतिवृष्टि में सक्रिय रहकर अपने स्तर से संसाधन जुटाकर बाढ़ एवं आपदा में सहयोग करेंगे

➤ कार्यालय तहसीलदार पावटा मे पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क्र.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	पदस्थान स्थान	मोबाईल नम्बर
1.	संजय कुमार	तहसीलदार	पावटा	
2.	संजय गुप्ता	ऑफिस कानूनगो	भू अभिलेख शाखा पावटा	
3.	अनिल कुमार	अति. ऑफिस कानूनगो	भू अभिलेख शाखा पावटा	
4.	गिरधारी	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
5.	शैरसिंह यादव	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
6.	सुमित्रा सैनी	पटवारी	भू अभिलेख शाखा पावटा	
7.	रामनिवास मीणा	भू अभिलेख निरीक्षक	टसकोला	9414857252
8.	पार्वती मीणा	भू अभिलेख निरीक्षक	पावटा	73397622995
9.	शशिधर यादव	भू अभिलेख निरीक्षक	खेलना	9414642442
10.	पाबूदान सिंह	भू अभिलेख निरीक्षक	दांतिल	
11.	मनोज यादव	भू अभिलेख निरीक्षक	प्रागपुरा	
12.	जितेन्द्र कुमार जाट	पटवारी	पावटा	9785580509
13.	श्री महेश कुमार	पटवारी	पंडितपुरा	9680075350
14.	कल्पना	पटवारी	कुनेड	7877237330
15.	प्रदीप कस्वां	पटवारी	जोधपुरा	9875225922
16.	विकास कौशिक	पटवारी	प्रा.पुरा	7014219279
17.	विक्रम यादव	पटवारी	पाथरेड़ी	8949750698
18.	प्रमोद सामरिया	पटवारी	भैंसलाना	7891056994

19.	गुल्लाराम यादव	पटवारी	भूरीभड़ाज	6378187206
20.	श्री शंकर सिंह शेखावत	पटवारी	राजनौता	8003820242
21.	रेखा मीणा	पटवारी	टसकोला	8824405192
22.	रविना कराला	पटवारी	भोनावास	8739801494
23.	मुकेशचन्द वर्मा	पटवारी	टोरडा•जरान	9588075404
24.	मुकेशचन्द वर्मा	पटवारी	बुचारा	9588075404
25.	जितेन्द्र कुमार जाट	पटवारी	खेलना	9785580509
26.	गिरधारी लाल सिंवर	पटवारी	बड़नर	6378457090
27.	संगीता कुमारी	पटवारी	तुलसीपुरा	8385013871
28.	संतोष कुमारी	पटवारी	फतेहपुरा खुर्द	8290792994
29.	विजय कुमार यादव	पटवारी	मंढा	8440904104
30.	मुकेश पारीक	पटवारी	पांचूडाला	9782830019
31.	विकास कौशिक	पटवारी	भांकरी	7597521049
32.	सीमा भुराडिया	पटवारी	कारौली	9024830416
33.	अभिषेक	पटवारी	दांतिल	
34.	गुल्लाराम यादव	पटवारी	पुरुषोत्तमपुरा	9413901990
35.	विक्रम यादव	पटवारी	गोरिकपुरा	8949750698
36.	संगीता कुमारी	पटवारी	सुंदरपुरा	9311003121

अध्याय-23

तहसील बहरोड आपदा प्रबन्धन योजना

तहसील बहरोड आपदा प्रबन्धन योजना-2025

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय-

तहसीलदार बहरोड का सृजन आजादी के समय से ही है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड से 25 कि०मी० उत्तर की ओर स्थित है जो कि NH 48 स्थित है।
तहसीलदार श्री अभिषेक यादव पदस्थापित है।

2. तहसील में संभावित खतरा-

तहसील बहरोड में ग्राम तंसीग, बर्डोद, नालपुर, निम्भोर व जखरानाकला में पहाड़ी होने से भारी बारिश होने से पानी आबादी क्षेत्र में आने से जलभराव कि स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहरोड के ग्राम कारोडा में साबी नदी पर पुल होने से भारी बारिश होने पर नदी बहाव क्षेत्र में पानी आने से पुल जर्जर अवस्था में है जिसका पूर्व में भी मरम्मत कार्य PWD विभाग द्वारा करवाया गया है।

3. यातायात व्यवस्था

तहसील मुख्यालय NH 48 पर स्थित जयपुर से दिल्ली के मध्य स्थित है जिस पर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4. तहसील मूलभूत संसाधन:-

- (1) जिला अस्पताल- 01
- (2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- 03 पहाड़ी, जखराना व बर्डोद
- (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- 06
- (4) उपस्वास्थ्य केन्द्र- 48
- (5) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र- 01
- (6) निजी अस्पताल- लगभग 11
- (7) अग्नि शमन केन्द्र 01
- (8) तहसील में पानी की व्यवस्था- केवल बोरवेल से ही पानी प्राप्त किया जाता है आवश्यकता अनुसार जगह-जगह खुदे हुए हैं।
- (9) तहसील में बिजली की व्यवस्था:-क्षेत्र के ग्राम जखराना, बहरोड, नासरपुर, पहाड़ी, सोतानाला, गूत्ती, गण्डाला, रिवाली, डवानी, तंसीग, बिजोरावास, कोहराना व भगवाडीकलां कुल 13 पावरहाऊस है जिनसे बिजली सप्लाई होती।

5. तहसील में

- (1) राजस्व ग्रामो की संख्या:- 94
- (2) पंचायत समिति 01 बहरोड
- (3) नगर पालिका- 01 बर्डोद
- (4) नगरपरिषद-01 बहरोड
- (5) उप तहसील-01 गण्डाला

6. **दक्ष लोगो का विवरण:-** तहसील बहरोड में डॉक्टर/कम्पाउंडर/वैध /आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तैराक/गोताखोर/नाव चालक लोग नहीं है।
7. **जीविकोपार्जन:-** तहसील में लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय व कुछ लोग राज्य सेवा, केन्द्र सेवा में लगे हुए है। तथा बहरोड में रीको क्षेत्र होने से कुछ लोग यहा संचालित फैक्ट्रीयो में कार्य कर जीवनयापन करते है
8. **मुख्य फसल:-** रबी में गेहूँ, सरसो, जौ व चना तथा खरीफ में बाजरा, कपास व ग्वार की फसल पैदा की जाती है।
9. **नदी/बांध/तालाब/नालो की स्थिति:-** तहसील बहरोड में साबी नदी का बहाव क्षेत्र है जिस पर ग्राम कारोड में पुल बना हुआ है। गांवों में जगह-जगह जोहड है जिनमे बारिश का पानी जमा होता है तथा तहसील में सोतानाला नाम से एक नाला है जो साबी नदी का भाग है।
10. **संचार के साधन:-** तहसील में BSNL, Airtel, Jio,Vi के नेटवर्क टॉवर है तथा तहसील मुख्यालय पर भारतीय डाक सेवा की मुख्य ब्रान्च है तथा लगभग 09-10 सबस्टेशन है।
11. **स्कूल/कॉलेज/धर्मशाला/सामुदायिक केन्द्र:-** तहसील में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उ0मा0 विधालय स्थित है तथा बहरोड में 04 राज्यकिय कॉलेज तथा कुछ निजी कॉलेज भी संचालित है। तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व निजी व सार्वजनिक धर्मशालाएं है।
12. **तहसील में पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी/गैस गोदाम:-** तहसील में एचपी, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पर निजी तोर पर संचालित है तथा एचपी,इन्डेन,भारत गैस की एजेन्सी है तथा इनके गोदाम भी स्थित है।
13. **कार्यालय तहसीलदार बहरोड में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारीयो की सूचना:-**

क्रम स.	नाम कार्मिक	पद	मोबाइल न.
1	श्री अभिषेक यादव	तहसीलदार	9636510723
2	श्री प्रवीण कुमार	नायब तहसीलदार(बहरोड)	7742423009
3	श्री अजीतसिंह यादव	नायब तहसीलदार (गण्डाला)	9887029009
4	श्री प्रहलाद सहाय मीणा	ऑफिस कानूनगो	8890532565
5	श्री पवन कुमार	अति0 ऑफिस कानूनगो	9521552133
6	श्री अविनाश	लीव रिजर्व भू0अ0 निरी0	9461404840
7	श्री राकेश कुमार	लीव रिजर्व भू0अ0 निरी0	9799893363
8	श्री त्रिलोकचन्द यादव	अति0 ऑफिस कानूनगो (गण्डाला)	9929714880
9	श्री बस्तीराम यादव	भू0अ0 निरीक्षक गूत्ती	6375449179
10	श्री मंगलचन्द वर्मा	भू0अ0 निरीक्षक गण्डाला	9694074771
11	श्री विपिन कुमार सेगंर	भू0अ0 निरीक्षक बहरोड	9887362400
12	श्री नवीन कुमार	भू0अ0 निरीक्षक महाराजावास	8094774466

13	श्री रामनिवास मीणा	भू0अ0 निरीक्षक जखरानाकला	9887326032
14	श्री कार्तिक यादव	भू0अ0 निरीक्षक रिवाली	9468956868
15	श्री लीलाराम यादव	भू0अ0 निरीक्षक जैनपुरबास	9929685150
16	श्री द्वारकादास	भू0अ0 निरीक्षक बडौंद	8696448926
17	श्रीमति शर्मिला कुमारी	पटवारी (LRC)	8058664113
18	श्री रामनरेश यादव	पटवारी गण्डाला	9462643743
19	श्री लेखराज गुर्जर	पटवारी दुण्डारिया	9782131242
20	श्री दिनेश कुमार	पटवारी गून्ती	8426939358
21	श्री हंसराज	पटवारी बडौंद	8058024521
22	श्रीमति अनिता	पटवारी गुजरवास	7016308084
23	श्रीमति शर्मिला यादव	पटवारी जागुवास	8890990106
24	श्री रामपत यादव	पटवारी बहरोड तर्फ गंगाबिशन	9887947391
25	श्री अजय कुमार गैनन	पटवारी बहरोड तर्फ डूंगरसी	6377112193
26	श्रीमति आरती यादव	पटवारी हर्मींदपुर	8529641667
27	श्री भुवनेश कुमार कुमावत	पटवारी महाराजावास	9829916386
28	श्री सुगडराम गुर्जर	पटवारी कोहराना	9057980760
29	श्री राजबीर यादव	पटवारी नांगलखोडिया	9785531418
30	श्री अमित कुमार	पटवारी रिवाली	8696030360
31	श्रीमति बीरमाकंवर	पटवारी मांचल	9462858360
32	सुश्री गीता सैनी	पटवारी बूढवाल	9509062562
33	श्री अनिल कुमार	पटवारी पहाडी	8890858632
34	श्री नरेन्द्र कुमार	पटवारी शेरपुर	6377061165
35	श्री संदीप यादव	पटवारी गादोज	9785327533
36	श्री अंकित शर्मा	पटवारी तसींग	8826048823
37	श्री बिजेन्द्र सैनी	पटवारी जखरानाकला	8302326409

38	श्री राजाराम	पटवारी जटगावडा	8690696976
39	श्री योगेश कुमार	पटवारी भगवाडीखुर्द	8209568826
40	श्रीमति मोनिका	पटवारी बसई	8955233129
41	श्री विष्णु यादव	पटवारी लीव रिजर्व	8104244734

अध्याय-24

तहसील नीमराना आपदा प्रबन्धन योजना 2024 –

तहसील नीमराना आपदा प्रबन्धन योजना-2025

1 तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय—

तहसील नीमराना का सृजन 2013 से हुआ है जो जिला मुख्यालय कोटपूतली-बहरोड से 40 किलोमीटर दूर स्थित है जोकि दिल्ली जयपुर NH48 रोड परस्थित है। तहसीलदार श्री अभिषेक यादव एवं नायब तहसीलदार श्री रामनीवास गोठवाल पदस्थापित है।

2 तहसील में संभावित खतरा:—तहसील नीमराना के ग्रामों में जोहड तालाब स्थित होने से वर्षा जल का भराव होता है

3 यातायात व्यवस्था:— तहसील नीमराना दिल्ली जयपुर NH48 रोड परस्थित है। जिसपर निजी बस व रोडवेज बस संचालित है।

4 तहसील मूलभूत संसाधन:—तीन प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुतीना, कायसा व डूमरोली एवं तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमराना, माजरी कला व शाहजहांपुर स्थित है।

अग्नि शमनव्यवस्था:— तहसील नीमराना के रीको औदोगिक क्षेत्र में अग्नि शमनकेन्द्रन स्थित है

तहसील में बिजली की व्यवस्था:— विधुत विभाग के फीडर से विधुत सप्लाई उपलब्ध है

पीने के पानी की व्यवस्था:—सभी ग्रामों में पेयजल के बोरवेल उपलब्ध है।

1. तहसील में ग्रामों/ ग्रामपंचायतों की संख्या—तहसील नीमराना में 17 ग्रामपंचायत व 57 राजस्व ग्राम है।
2. तहसील की जनसंख्या तहसील क्षेत्र की कुल 109321 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।
3. दक्ष लोगो का विवरण—तहसील नीमराना में डॉक्टर/कम्पाउडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है। तैराक/गोताखोर/नावचालक लोग नहीं है।
4. जीविकोपार्जन—तहसील नीमराना में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय / नौकरी करते है।
5. मुख्य फसल—रबी—गेहूंसरसोंहै/ खरीफ—बाजरा, ग्वारहै।
6. नदी/बाध/तालाब / नालो की स्थिति—नदी/बाध/स्थित नहीं है।
7. संचार के साधन एयरटेल/बीएसएनएल/जीओ के टावर व कनेक्टिविटी है। पोस्ट ऑफिस की सुविधा है।
8. स्कूल/धर्म शाला/सामुदायिक केंद्र स्कूल स्थित है।

9. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची तहसील नीमराना में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।
10. तहसील में उपलब्ध राजकीय / कार्मिकों के नाम व दूरभाष—सूची सलग्न है।
11. नगरपालिका उपलब्ध होतो उसका नाम —नगरपालिका नीमराना है।
12. तहसील क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईया—तहसील नीमराना क्षेत्र में रीको क्षेत्र नीमराना एव घीलोट में औद्योगिक इकाई स्थित है।
13. उपलब्ध मेडीकल दुकानों/सरकारी/प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेसरी का नाम बिस्तरों की क्षमता / डॉक्टरों/ नर्सिंगस्टॉफ की संख्या/पेट्रोलपम्प/गैस एजेन्सी/ गैसगोदाम— 1 राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमराना— 2 डॉक्टर व 5 नर्सिंग स्टॉफ, निजी व सरकारी मेडीकलस्टोर हैं। दो पेट्रोलपम्प स्थित है C.N.G गैसपम्प स्थित है इंडियन एजेन्सीग्राम नीमराना में स्थित है।
14. तहसील के ग्रामों में जेसीबी/अन्य मशीनरी उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार नीमराना में पदस्थापित कार्मिकों की सूचना

क्र०स०	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापनस्थान	मोबाईलनम्बर
1	श्री अभिषेक यादव	कार्यवाहक तहसीलदार (अति०प्रभार)	तहसील नीमराना	9636510723
2	श्री रामनीवास गोठवाल	नायब तहसीलदार	तहसील नीमराना	8112286960
3	श्री कृष्ण कुमार	ऑफिस कानूनगो	तहसील नीमराना	9929171900
4	श्री पवन कुमार शर्मा	लि०रि० भू०अ० निरीक्षक	तहसील नीमराना	9784476549
5	श्री हाकिम सिंह	भू०अ० निरीक्षक	श्रीयानी,माजरी कला (अति०प्रभार)	9414362603
6	श्री मनोज कुमार	भू०अ० निरीक्षक	शाहजहांपुर	9887159084
7	श्री दिलबाग सिंह	भू०अ० निरीक्षक	कायसा	8619526819
8	श्री राजेद्रप्रसाद	भू०अ० निरीक्षक	नीमराना	9829240510
9	श्रीमती अमीत कुमार	पटवारी	नीमराना	8059989378
10	श्री प्रशंत	पटवारी	कोलिका जोगा	9660002930
11	श्री मंथन	पटवारी	बिचपुरी	7014672740
12	श्री आसुतोश	पटवारी	प्रतापसिंहपुरा	9057744860
13	श्री किशोर कुमार	पटवारी	जोनायचाकला	9783183485
14	श्री विकास कुमार	पटवारी	शाहजहांपुर(अति०प्रभार)	9511567847
15	श्री कमलेश कुमावात	पटवारी	फौलादपुर	7740960911
16	श्री घनश्याम सिंह	पटवारी	गुगलकोटा	9672504233

17	श्री उमाशंकर भारद्वाज	पटवारी	जेनायचाखुर्द	7737568600
18	श्री मनीष कुमार	पटवारी	श्रीयाणी	9416886150
19	राजकौर कुलहरी	पटवारी	सलारपुर	9351236620
20	श्री विकास कुमार	पटवारी	कुतीना	9511567847
21	श्री देवेन्द्र चोदरी	पटवारी	घीलोट	7742606090
22	श्री मंजीत यादव	पटवारी	कायसा	9024747274
23	श्री संदीप कुमार	पटवारी	अकलीमपुर	9785180919
24	श्री विकास	पटवारी	डूमरोली	9813626697
25	श्री धर्मसिंह	पटवारी	रैवाना (अति0प्रभार),दोसोद	9772113394
26	श्री अजीत सिंह	पटवारी	रोडवाल,दौलतसिंहपुरा(अति0प्रभार),	8769883009
27	श्री संदीप कुमार	पटवारी	माजरी कला	9460834093
28	श्री राजेश कुमार	पटवारी	तहसील नीमराना	9587209587
20	श्री विकास कुमार	पटवारी	कुतीना	9511567847
21	श्री देवेन्द्र चोदरी	पटवारी	घीलोट	7742606090

અધ્યાય—25

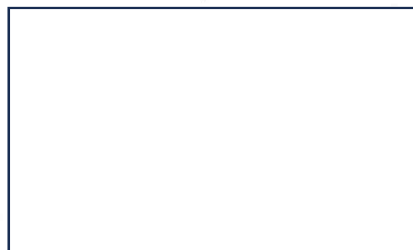
તહસીલ નારાયણપુર આપદા પ્રબંધન યોજના²⁰²⁵

प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2025 से बचाव की पूर्व तैयारी हेतु कंटीन्जेंसीज प्लान यह कंटीन्जेंसीज प्लान

यह कन्टनजेंसी प्लान वर्ष 2025 हेतु उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर में संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति निपटने की सस्ता सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने एवं पशु हानि को रोकने हेतु सक्रिय प्रयासों की क्रियान्विति की जाएगी। उपखण्ड मुख्यालय नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड के मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में लगभग 32 किमी की दूरी पर स्थित है। उपखण्ड नारायणपुर में 18 ग्राम पंचायत एवं 01 नगरपालिका में 62 राजस्व ग्राम है। उपखण्ड नारायणपुर 2 पंचायत समितियों से मिलकर बना है पंचायत समिति बानसूर की 9 ग्राम पंचायत व पंचायत समिति की 11 ग्राम पंचायत इस उपखण्ड में सम्मिलित है।

उपखण्ड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष 15 जून 2025 से स्थापित कर लिया जायेगा। नियंत्रण कक्ष पर निरंतर आठ-आठ घंटे के अंतराल पर स्टाफ की ड्यूटी यथा समय लगाई जाए जा रही है नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01465-294099 हैं।

10. तहसील में पदस्थापित समस्त भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारीगण के हल्के की दूरभाष नंबर उपलब्ध होकर सूची संलग्न है।
11. उपखण्ड क्षेत्र में तैराको/गोताखोरों की सूची तैयार कर संलग्न है।
12. उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुण्डावरा एवं बामनवास काकड़ के समस्त ग्रामों में निचले क्षेत्र में पानी भरने की संभावना रहती है।
13. बाढ़ के समय लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। भूने हुए चनें एवं गुड़ की व्यवस्था के लिए भी इन्हीं संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
14. अतिवृष्टि के कारण मकानों आदि में होने वाली क्षति व अन्य तात्कालिक सहायता/आवश्यकताओं के लिए तहसील स्तर पर बजट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
15. बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को ठहराने के लिए सामुदायिक भवन/विद्यालय भवन आदि का उपयोग किया जा सकेगा।
16. संसाधन (वाहन/इंजन/खाली कट्टे आदि) सिचाई विभाग द्वारा बांधों के गेटों को ऑयल/ग्रीस से मरम्मत कर तैयार करने के साथ अपने सभी वाहन/इंजन गेती, फावड़े आदि दुरुस्त करा तैयार रखे, साथ ही विभाग अपने अधिनस्थ बांध की सुरक्षा हेतु कम से कम 1200 खाली कट्टे बांध पर



रखें एवं अपने कार्मिकों को बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर मुस्तैदी से कार्यवाही करने हेतु आगाह करें।

17. विद्युत विभाग अपने वाहनो सहित किसी भी प्रकार की त्वरित कार्यवाही हेतु सतर्क रहे।

18. पंचायत समिति अपने अधिनस्थ प्रत्येक तालाब,नाडी ,ऐनिकट की सुरक्षा हेतु कम से कम 250 कट्टे ग्राम पंचायत स्तर पर तथा 1000 खाली कट्टे पंचायत समिति स्तर पर रखेंगे। जिन तालाबो की क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। वहां पर लगभग 150 से 200 कट्टे रेत के भरवा कर तैयार रखावें।

इस तरह संबंधित विभाग प्रत्येक तालाब/ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार रेत, सुए, गेती, फावडे, तगारी, सब्बल ,टॉर्च ,केरोसीन आदि तैयार रखावें। आवश्यकता पडने पर आवश्यक व्यवस्था सभी विभाग अपने स्तर पर करेंगे।

तहसील नारायणपुर के पटवारियां भू अभिलेख निरीक्षक एवं मोबाइल नंबरों की सूची

क्र.स	भू.अभि.निरी. /पटवार मण्डल का नाम	भू.अभि.निरी./पटवारी का नाम	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	श्री अशोक योगी	9799273142
2	अजबपुरा	श्री अनुराग शर्मा	7976926166
3	ज्ञानपुरा	श्री अशोक कुमार	9784797955
4	नीमूचाना	सुश्री रेखा बूनकर	9928840066
5	नारायणपुर ए	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	8003173072
6	नारायणपुर बी	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	8003173072
7	विजयपुरा	श्रीमती शिवानी यादव	9079173323
8	बामनवास कांकड	श्री रोहिताश्व योगी	8696208409
9	कोलाहेडा	श्री हवाई सिंह मीना	8426067963
10	अजबपुरा	श्री अरविन्द सैनी	8003885034
11	गढी	श्री राजेश कुमार गुर्जर	8742086820
12	खरकडी कलां	श्री राजेश कुमार गुर्जर	8742086820
13	मुण्डावरा	श्री अरविन्द सैनी	8003885034
14	चांदपुरी	श्री योगेश सैनी	9602133067

15	ज्ञानपुरा	श्री हवाई सिंह मीना	8426067963
16	बिलाली	श्री रोहिताश्व योगी	8696208409
17	कराणा	श्री सुरेन्द्र सिंह	8742086820
18	नीमूचाना	श्रीमती कविता	7851839589
19	चतरपुरा	श्रीमति कृष्णा बाई यादव	8003173072
20	बासदयाल	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	9887586486
21	बसईजोगियान	श्री योगेश सैनी	9602133067



ब्लॉक नारायणपुर के ग्राम विकास अधिकारी के मोबाइल नंबरों की सूची

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम विकास अधिकारी नाम	मोबाइल नम्बर
1	कोलाहेडा	श्री विनित चौधरी	9887684330
2	विजयपुरा	श्री विजय प्रजापत	9057132653
3	बामनवास कांकड	श्री विनित चौधरी	9887684330
4	अजबपुरा	श्री संजय सिंह	7727090406
5	मुण्डावरा	श्री रजनीकान्त	7976448420
6	गढी	श्री मनीष शर्मा	8561833822
7	खरकडी कलां	श्री रामकिशन सैनी	9828748346
8	चांदपुरी	सुश्री रीना यादव	8233518533
9	कानपुरा लोज	श्री दिनेश चौधरी	8209436772
10	बसई जोगियान	श्री विपिन शर्मा	9928538607
11	बुर्जा	अनु यादव	9521463962
12	कराणा	श्री कमल शर्मा	9672279500
13	बिलाली	श्री निर्मल शर्मा	9680859008
14	तुराणा	श्री पवन शेखावत	8302783594
15	नयाबास	श्री गोविन्द शर्मा	9982961409
16	चतरपुरा	श्री सुनील कुमार प्रजापत	9660925011
17	नीमूचाना	श्री मनोज कुमार गुर्जर	9521290014
18	बासदयाल	श्री मनीष कुमार गिटाला	8209106746



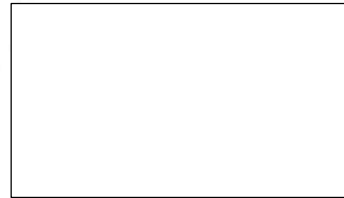
तैराक/गोताखोरो की सूची - उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	तैराक/गोताखोरो	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	श्री	
2	कोलाहेडा	श्री	
3	विजयपुरा	श्री	
4	बामनवास कांकड	श्री	
5	अजबपुरा	श्री	
6	मुण्डावरा	श्री	
7	गढी	श्री	
8	खरकडी कलां	श्री	
9	चांदपुरी	श्री	
10	कानपुरा लोज	श्री	
11	बसई जोगियान	श्री	
12	ज्ञानपुरा	श्री शंकर लाल मीणा	6378065132
13	बुर्जा	श्री सचिन वर्मा	7240214402
14	कराणा	श्री रमेश	8441814934
15	बिलाली	श्री हंसराज	9015254501
16	तुराणा	श्री महेन्द्र कुमार	8107983202
17	नयाबास	श्री विक्रम	9001602482
18	चतरपुरा	श्री मुकेश	9460555185
19	नीमूचाना	श्री जितेन्द्र	8714359078
20	बासदयाल	श्री कमल मीणा	6376154424



उपखण्ड क्षेत्र नारायणपुर में जेसीबी धारको की सूचना

क्र.स.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम विकास अधिकारी नाम	मोबाइल नम्बर
1	नारायणपुर	3. श्री रतन लाल 4. श्री गिरिराज	9636406884 9929554072
2	विजयपुरा	श्री सियाराम	8426815203
3	बामनवास कांकड	श्री भीमसिंह	9694811081
4	मुण्डावरा	श्री भीमसिंह	9694811081
5	गढी	श्री रमेश	9950097772
6	खरकडी कलां	श्री बनवारी	8890908185
7	चांदपुरी	श्री सुनील	8058930011
8	कानपुरा लोज	श्री भीमसिंह	9694811081
9	बसई जोगियान	3. श्री गुडडू हरसाना 4. श्री संदीप	9414632424 8875809528
10	ज्ञानपुरा	श्री नत्थूराम	7300373707
11	बुर्जा	श्री नत्थूराम	7300373707
12	कराणा	श्री पप्पू सिंह	9602072865
13	बिलाली	श्री हुकुम सिंह	9057500634
14	तुराणा	श्री पप्पू सिंह	9602072865
15	नयाबास	श्री पप्पू सिंह	9602072865
16	चतरपुरा	3. श्री छाजूराम मीना 4. श्री देशराज मीना	9784510660 9887303559
17	नीमूचाना	3. श्री छाजूराम मीना 4. श्री देशराज मीना	9784510660 9887303559
18	बासदयाल	—	—



अध्याय-26

तहसील विराटनगर आपदा प्रबंधन योजना 2024

1. तहसील व तहसीलदार का नाम एवं तहसील का परिचय:-

तहसील विराटनगर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित है जो कि शाहपुरा(जयपुर) से अलवर रोड़ पर स्थित है। तहसीलदार श्री लालाराम यादव (6377252790) एवं नायब तहसीलदार श्रीमती मेनका चौधरी (9001473765) है।

2. तहसील में संभावित खतरा:-

तहसील विराटनगर में बाढ़ संभावित बाण गंगा नदी व छीतोली बाध है।

3. यातायात व्यवस्था:- शाहपुरा (जयपुर) से अलवर मुख्य मार्ग पर ही स्थित है।

4. तहसील मूलभूत संसाधन:-

डिस्पेंसरी:- 1 विराटनगर, उप जिला चिकित्सालय, (100 बेड क्षमता) 1 मैड 2. आँतेला, 3 जयसिंहपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सालय केन्द्र विराटनगर, मैड, जयसिंहपुरा, बीलवाड़ी में स्थित है।

अग्नि शमन व्यवस्था:- अग्नि शमन केन्द्र विराटनगर नगरपालिका में स्थित है।

तहसील में बिजली की व्यवस्था:- फीडर से जुड़ा हुआ है।

पीने के पानी की व्यवस्था—बोरवेल एवं कुएँ उपलब्ध है।

5. तहसील में ग्रामों व ग्राम पंचायतों की संख्या तहसील विराटनगर में 29 ग्राम पंचायत व 114 राजस्व ग्राम है।

6. तहसील विराटनगर की जनसंख्या कुल 150515 (जनगणना 2011 के अनुसार) जनसंख्या है।

7. दक्ष लोगो का विवरण तहसील विराटनगर में डाक्टर/कम्पाउंडर/वैध/आयुर्वेद कम्पाउंडर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग है तैराक/गोताखोर/ नाव चालक लोग नहीं है

8. जीविकोपार्जन—तहसील विराटनगर में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है कुछ परिवार व्यवसाय/ नोकरी करते है।

9. मुख्य फसल:- रबी-गेहूँ जौ सरसों तारामीरा है खरीफ बाजरा मूंगफली तिल ग्वार है। व सब्जिया हैं।

10. नदी/ बांध/ तालाब/ नालो की स्थिति:- तहसील विराटनगर में नदी बाणगंगा, साबी तथा बांध एवं तालाब छीतोली, बूजा, बीजक कराठ, नोरगपुरा पालडी आदि है नाले अनेक है।

11. संचार के साधन एयरटेल/ वी आई/ जीओ बीएसएनएल के टावर व कनेक्टिविटी है पोस्ट आफिस की सुविधा है। ग्राम पंचायत बड़ोदिया में नेटवर्क सुविधा नहीं है।

12. स्कूल/कालेज/ धर्मशाला/ सामुदायिक केन्द्र:- तहसील विराटनगर में स्कूल/कालेज/ धर्मशाला/ सामुदायिक केन्द्र स्थित है।

13. तहसील में उपलब्ध बचाव उपकरणों की सूची:- तहसील विराटनगर में सहकारी क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

14. तहसील में उपलब्ध राजकीय कार्मिको के नाम व दूरभाष:- सूची सलग्न

15. नगर पालिका — विराटनगर है

16. औद्योगिक ईकाईया:- तहसील विराटनगर में औद्योगिक ईकाईया नहीं है।

17. उपलब्ध मेडिकल दुकानों सरकारी प्राईवेट अस्पतालों व डिस्पेन्सरी का नाम बिस्तरों की क्षमता डाक्टरों 28 नर्सिंग स्टाफ की संख्या 97 / पेट्रोल पंप की संख्या 15 गैस एजेंसी 03 है।
18. भारी मशीनरी तहसील विराटनगर में 10 JCB मशीन उपलब्ध है।

कार्यालय तहसीलदार विराटनगर में कार्मिकों की सूचना:-

1.	विराटनगर	श्री गोपाल लाल मीणा 9829463311	विराटनगर	सुभाष चन्द लील (अति.)	6350482737
			सोठाना	आशीष कुमार शर्मा (अति)	9875733318
			तेवडी	चेतना शर्मा	7891602965
			कुहाडा	सीताराम ज्योतिषी	9785217091
2.	बीलवाडी	श्री सुनील कुमार शर्मा 9571818775	बीलवाडी	सीताराम ज्योतिषी (अति)	9785217091
			नोरंगपुरा	सुशीला मीना	8005833357
			बागावास चौरासी	विनोद कुमार वर्मा	9079691099
			जवानपुरा	आशीष कुमार शर्मा	9875733318
3.	पालडी	श्रीमती रिकी मीणा 6378782474	पालडी	रामराज मीना	9414543807
			आमलोदा दूदी	मनोज कुमार मीना	9636528208
			भामोद	मनोज कुमार मीना (अति)	9636528208
			बडोदिया	रामराज मीना	9414543807
4.	मैड	धर्मपाल रैगर 9829850473	मैड	विक्रम सिंह गुर्जर	8104258820
			पुरावाला उर्फ मैड बी	सुभाष चन्द लील	6350482737
			जोधूला	अल्का अलवारिया	9571178566
			तालवा बिहाजर	रामनारायण गुर्जर	9929335438
5	आँतेला	श्री कुलदीप मीणा 8306601328	आँतेला	नीलम कुमारी यादव	8005535680
			बजरंगपुरा	अमरचन्द मीना	8690089219
			बागावास अहिरान	महेन्द्र कुमार यादव (अति)	8209657763
			जयसिंहपुरा	महेन्द्र कुमार यादव	8209657763
6.	भाबरू	श्री राजकपूर खरकडिया 9799817638	भाबरू	नरेश कुमार यादव	9509634476
			ढाणी गैसकान	देशराज यादव	8502812011
			लुहाकना कला	मन्जू यादव	7568057359
			छीतोली	अशोक कुमार यादव	9929485885

कार्यालय तहसीलदार विराटनगर सम्पर्क सूची (कार्यालय स्टाफ)

क्रम संख्या	शाखा	नाम कार्मिक	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	भू अभिलेख शाखा	श्री कन्हैयालाल रैगर	आफिस कानूनगो	7665728207

2.		श्री रतनलाल मीना	अति. आफिस कानूनगो	8290782529
3.		श्री ख्यालीराम यादव	लीव रिजर्व ILR	9667418827
4		श्री अनिल कुमार यादव	एल आर सी पटवारी	7240630190
5		श्रीमती हंसा मीणा	एल आर सी ILR	8949635992
		श्री प्रकाश चन्द मीणा	लीव रिजर्व पटवारी	7339940948
6	सामान्य प्रशासन शाखा	श्री महेश सिंह चौहान	सहा. प्रशा. अधिकारी	9829600458
7		श्री गौरव शर्मा	कनि. लेखाकार	9636239010
8		श्री श्रीराम गुर्जर	TRA	8209908822
9		श्री कमल मेहरा	रीडर	9001409902
10		श्री भूपेन्द्र कुमार मीना	कनि. सहा.	8426902404
11		श्री देवीलाल पलसानिया	कनि. सहा	8107743923
12		श्री राहुल शर्मा	कनि. सहा	9610454740
13		श्री कैलाश चन्द मीना	वाहन चालक	7976495982
14		श्री गोपाल लाल गुर्जर	सहा. कर्मचारी	8290731814
15		श्री सन्तोष हरिजन	सहा. कर्मचारी	9928026730
16		श्रीमती सुप्यार देवी	सहा. कर्मचारी	9929091545
17		श्री मोहनलाल	सहा. कर्मचारी	9929634261

अध्याय : 27

जिले के प्रशासनिक अधिकारी ,पुलिस अधिकारी ,जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण विभाग की सूची एवं दूरभाष नम्बर

S.No	Name	Designation	Place	Phone No.	Email ID
1	Smt. Kalpana Agarwal (IAS)	District Collector	Collectorate, Kotputli-Behror	9413318811	dm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
2	Sh. Rajan Dushyant	Superintendent of Police	SP Office Kotputli-Behror	9414000039	SPKOTPUTLIBEHRROR@RAJPOLICE.GOV.IN
3	Mr. Om Prakash Saharan	Add. District Collector	Collectorate, Kotputli-Behror	9413514599	adm.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
4	Sh. Vaibhav Sharma	Add. S.P. of Police	SP Office kotputli	9462809039	addlspkotputlijpr@gmail.com
5	Smt. Shalini	Add. S.P. of Police	SP Office Neemrana	8107840530	aspneemrana@gmail.com
6	Sh. Mahendra Kumar Saini	Add. Chief Executive office, Zila Parishad	Zila Parishad, Kotputli	9999353741	aceoktpbehror@gmail.com
7	Sh. Brijesh Kumar II	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Kotputli	7011684021	sdo.ktp.jpr@gmail.com
8	Sh. Ramkishor Meena	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Behror	9829086213	sdbmbeh.alw@gmail.com
9	Sh. Dinesh Sharma	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Narayanpur	9413632204	SDMNPR.ALW@RAJASTHAN.GOV.IN
10	Sh. Kapil Kumar	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Paota	9680447574	SDO.PAOTA.JPR@RAJASTHAN.GOV.IN
11	Mrs. Amita Maan	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Viratnagar	9166792424	sdoviratnagar1@gmail.com
12	Sh. Anurag Harit	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Bansur	7877950459	sdbmban.alw@gmail.com
13	Sh. Mahendra Singh	Sub Divisional Magistrate (SDM)	Neemrana	9414019062	sdmneem.alw@gmail.com
14	Sh. Ramdhan Gurjar	Tehsildar	Tehsil, Kotputli	6375876959	tldr.ktp.jpr@gmail.com
15	Sh. Abhishek Yadav	Tehsildar	Tehsil, Behror	9636510723	tehsilbehror@gmail.com
16	Sh. Anil Kumar	Tehsildar	Tehsil, Narayanpur	9783806488	tehsildar.npr@gmail.com
17	Sh. Sanjay Kumar	Tehsildar	Tehsil, Paota	9414562777	tldr.paota.jpr@gmail.com
18	Sh. Lala Ram Yadav	Tehsildar	Tehsil, Viratnagar	6377252790	viratnagartdr@gmail.com
19	Sh. Gajendra Singh Rathore	Tehsildar	Tehsil, Bansur	9910365470	tehban.alw@gmail.com
20	Sh. Abhishek Yadav (Add. Charge)	Tehsildar	Tehsil, Neemrana	9636510723	tehsilneemrana@gmail.com
21	Sh. Sumit Bhardaj	Tehsildar	Tehsil, Mandhan	7014147782	tldr.mandhan@gmail.com
22	Sh. Ashok Kumar Verma	Treasur Officer	Treasury Collectorate, Kotputli-Behror	9829242477	to.kot@rajasthan.gov.in
23	Sh. Shashi Shekar Sharma	District Supply Officer	Food Department office Nagar Parisad	9829600407	dsofood-beh.ktp-rj@gov.in
24	Sh. Noor Mohammad (Add. Charge)	Commissioner Nagar Parishad	Nagar Parishad, Kotputli-Behror	9829230911	kotputliulb.jaipur@yahoo.com
25	Dr. Aashish Shekhawat	CM&HO	Kotputli-Behror	9828261988	cmho-ktp.behror-rj@gov.in
26	Dr. Chetant Rawat	Principal Medical Officer (PMO)	Kotputli	9414083793	bdm.hospitalkotputli@gmail.com
27	Dr. Suresh Chand Yadav	Principal Medical Officer (PMO)	Behror	9414200744	pmodhbehror-rj@gov.in
28	Dr. Arvindra Agarwal	RCHO	RCHO Office Kotputli	9414924745	rchkotputlibehror@gmail.com
29	Sh. Rahul Aashiwal	APRO	Information and Public Relations Deparmtment, Kotputli-Behror	9582702781	prokotputlibehror@gmail.com; dipr.kotputli.behror@rajasthan.gov.in
30	Sh. Vipin	DPSW	Social Justice & Empowerment office Kotputli	7891434971	dlo.sje.kotp@rajasthan.gov.in
31	Sh. Ramatar Kumawat	Superintending Engineer	PWD kotputli	9414537005	SEKOTPUTLI.PWD@RAJASTHAN.GOV.IN
32	Sh. Ram Niwas Yadav	Superintending	PHED kotputli	9414545917	secirclekotputli@rajasthan.gov.in

		Engineer			
33	Sh. Manoj Gupta	Superintending Engineer	JVVNL Kotputli	9413389902	sekotputli@jvvn.org
34	Sh. Ramsingh Yadav	DEO	DEO Office Kotputli	9928307875	DEOHQSECKOTPUTLIBEHR@RAJASTHAN.GO
35	Sh. Sunil Kumar Saini	DTO	DTO Office Kotputli	8890991006	dto.kotputli.tport@gmail.com
36	Sh. Girivar Sharma	DEO	Excise office Behror	9829181904	deo.behror.excise@rajasthan.gov.in
37	Sh. Rishidev Yadav	ZSKA	Sainik Welfare Department Behror	9953944529	zska.behror@rajasthan.gov.in
38	Sh. Amichand Duhariya	AME	Mining Office Kotputli	8104036901	ame.kotputli@rajasthan.gov.in
39	Sh. Satpal Yadav	Deputy Director	woman and child development office	9928363176	DDKOTPUTLIBEHROR.WCD@RAJASTHAN.GOV.IN
40	Dr. Harish Kumar	Deputy Director	Animal Husbandry Office Kotputli	9414249319	ddahdktpbehrr@gmail.com
41	Sh. Sunil Kumar Meena	Deputy Director	DOITC Office Kotputli	9799895730	dlo.doit.kotputli.b@rajasthan.gov.in
42	Sh. Leela Ram Jat	Deputy Director	Horticulture Kotputli	9414367083	DDHORT.KOT.BEH.HORTI@RAJASTHAN.GOV.IN
43	Sh. Babu Lal Bairwa	BSO	Statistic office Kotputli	9509563178	BSOKOTPUTLI.DES@GMAIL.COM
44	Sh. Mahendra Kumar Jain	Joint Director	Agriculture office Kotputli	9414257584	JDAGR.KTPBEH@rajasthan.gov.in
45	Sh. Satjeet Khoriya	GM DIC	District Industry Centre Bhiwadi	9001922114	dicbhiwadi@rajasthan.gov.in
46	Sh. Subhash Sharma	GM DIC	District Industry Centre Kotputli	9928157032	dicjprural@rajasthan.gov.in
47	Sh. Rajkumar Sehra	Regional officer	RPCB Neemrana	9829664373	rorpcb.bkt@gmail.com

अध्याय : 28

आपदा प्रबन्धन में लाभकारी शब्दावली

- ARMVs - Accident Relief Medical Vans
- CBOs - Community Based organizations
- CBRN - Chemical, Biological, Radiological & Nuclear
- CCMNC - Cabinet Committee on Management of Natural Calamities
- CCS - Cabinet Committee on Security
- CRF - Calamity Relief Fund
- DDMA - District Disaster Management Authority
- DM - Disaster Management
- GIS - Geographical Information System
- GPS - Global Positioning System
- HLC - High Level Committee
- HPS - High Power Committee
- ICS - Incident Command System
- ICT - Information and Communication Technology
- IDRN - India Disaster Resource Network
- IDKN - India Disaster Knowledge Network
- IMC - Inter-Ministerial Committee
- NCCF - National Calamity Contingency Fund
- NCMC - National Crisis Management Committee
- NDEM - National Database for Emergency Management
- NDMA - National Disaster Management Authority
- NDMF - National Disaster Mitigation Fund
- NDRF - National Disaster Response Force
- NEC - National Executive Committee
- PRIs - Panchayati Raj Institutions
- SDMS - State Disaster Management Authority
- SDRF - State Disaster Response Force
- SEC - State Executive Committee
- SOPs - Standard Operating Procedures
- ULBs - Urban Local Bodies

कमियां एवं ठोस कार्यवाही

(तहसील एवं ग्राम स्तर का अवलोकन एवं डाटा संग्रहण पर आधारित)

1. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की जानकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नगण्य पायी गई।
2. जिले में आपदा न्यूनीकरण योजना को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधन की कमी पाई गई।
3. जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के बीच संचार प्रणाली एवं तालमेल निम्न स्तर पर आंकलन की गई जहां अधिक से अधिक प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।
4. आपदा की प्रभावी योजना एवं तैयारी के लिए प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है।
5. जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों का डाटाबेस एवं दक्ष लोगों की सूची आपातकालीन सूचना केन्द्र पर अपडेट रहना चाहिए, जो नगण्य है।
6. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षित लोगों की भर्ती, फायर टेण्डर की व्यवस्था एवं जल भण्डारण की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि समय की बचत के साथ ही अग्नि दुर्घटना में कम से कम जान-माल की क्षति हों।
7. जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर चिकित्सा एवं ट्रौमा केयर के लिए अस्पतालों का स्तर उँचा करना, संसाधन से लैस एम्बुलेंस, पैरा स्टाफ एवं संचार प्रणाली को व्यवस्थित करना ताकि सड़क दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके।
8. स्कूल एवं शिक्षण संस्थानों में प्रबन्धकों एवं छात्रों को आपदा एवं जागरूकता का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

9. स्थानीय स्तर पर क्षमता वर्धन के लिए लोगों में जागरूकता, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका, मिडिया की साझेदारी एवं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी की प्रबलता बढ़ाई जाये।
10. जिला, तहसील एवं उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन में उच्च स्तर का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये ताकि स्थानीय संसाधन का विकास हो सके।
11. निचले स्तर के सभी सरकारी कर्मियों, एवं जनप्रतिनिधियों, जैसे- सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, शिक्षक, जल संसाधन कर्मी, अस्पतालकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं अन्य कार्मिकों को आपदा प्रबन्धन में कम से कम दो या दो दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यक किया जाये ताकि ग्रामीण स्तर पर इसका लाभ आमजन को मिल सके।
12. आपदा प्रबन्धन कानून का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
13. प्रत्येक तहसील स्तर पर ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) का गठन एवं संचालन 24 घन्टे सुनिश्चित किया जाये ताकि आपात स्थिति में प्रशासनिक तंत्र कम समय में घटना को नियंत्रित कर सकें। प्रशासनिक तंत्र को सूचना प्रणाली को विकसित करने का उपाय करना चाहिए।

सधन्यवाद